राष्ट्रीय सहारा
पटना • बुधवार • 4 दिसम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

सरकार की असफलता

बांग्लादेश में हिन्दू और अल्पसंख्यकों का विश्वास अर्जित करने में असफल रहने के कारण वहां की नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनूस की अंतिम सरकार की विश्वसनीयता पर खरोंचें आ सकती हैं। तीन महीने पहले अगस्त में छात्रों के उग्र और हिंसक आंदोलन के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना पद छोड़कर भारत निर्वासित होना पड़ा था। तब मोहम्मद युनूस ने छात्र आंदोलन को 'दूसरे मुक्ति संघर्ष' की संज्ञा दी थी। अगर यह मन भी लिया जाए कि शेख हसीना की सरकार सर्व सत्तावादी और लोकतंत्र को कोई रौंदने वाली थी और छात्रों के हिंसक आंदोलन ने बांग्लादेश में लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने की उम्मीदें जगाई तो दूसरी ओर देश की

सांप्रदायिक दरारों को भी उजागर किया। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद युनूस ने पिछले तीन महीनों के दौरान राष्ट्रीय एकता, समावेशी सरकार, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना आदि बातें की और हिन्दुओं के तोड़े गए उपासना स्थलों, दुकानों और अन्य व्यापारिक संस्थानों का दौरा भी किया। बावजूद इसके हिन्दुओं के घरों पर हमले होते रहे और उन्हें मारा-पीटा जाता रहा। हैरानी की बात है कि मोहम्मद युनूस के हाव-भाव हिन्दुओं को किसी भी तरह आश्वस्त नहीं कर सका। ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस्लामी उग्रवादियों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्ण दास के बाद वहां की सरकार ने दो और हिन्दू साधुओं को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों से जाहिर होता है कि अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न, मुआवजा और उनके पुनर्वास से संबंधित मांगों को लेकर सड़क पर उतरने वाले प्रदर्शनकारियों पर सरकार की सख्ती बढ़ती जा रही है। अल्पसंख्यक पत्रकारों और वकीलों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। भारत सरकार वहां की सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की लगातार मांग कर रही है। ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से वहां उत्पीड़ित हिन्दुओं को भारत वापस लाने की अपील की है। शेख हसीना के शासन में अल्पसंख्यक सुरक्षित भले रहे हों, लेकिन उन्होंने सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करने का प्रयास नहीं किया। पिछले तीन महीना में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध 2000 से ज्यादा हिंसक वारदात हुए हैं। यह जाहिर करता है कि युनूस की सरकार लोगों की जान-माल की सुरक्षा करने में असफल साबित हो रही है। उन्हें तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि अल्पसंख्यकों में सरकार के प्रति विश्वास का पुनर्निर्माण हो सके।

बन गई बात

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक के बाद सदन की कार्रवाई सुचारू चलने की संभावनाएं दिखी है, जो अच्छी बात है। सत्तापक्ष व विपक्ष के नेताओं के साथ हुई इस बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री किरन रिजीजू ने कहा विपक्षी दल सदन में गतिरोध दूर करने के लिए राजी हो गए हैं। विपक्षी दलों की मांग स्वीकार करते हुए सरकार ने 13-14 दिसम्बर को संविधान पर लोक सभा में, राज्य सभा में 16-17 को चर्चा का ऐलान किया। इसी के साथ शीतकालीन सत्र में जारी गतिरोध टूट गया। विपक्षी दल संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग कर रहे थे। छह दिनों से चले आ रहे गतिरोध को रोकने में सरकार ने चर्चा का

अनुरोध स्वीकार किया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस द्वारा विपक्ष की इस संयुक्त रणनीति का पालन करने से किया गया इनकार अलग संकेत दे रहा है। क्योंकि वह बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को उठाना चाहती है, जबकि विपक्ष संभल व मणिपुर में अशांति का मुद्दा उठाने से चूकने वाला नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं, संभल की घटना भाजपा की सोची-समझी रणनीति है। यादव सदन में इस पर अपनी बात रखना चाहते हैं। कांग्रेस अडानी समूह से जुड़े विवादित मामलों पर चर्चा के लिए अड़ी है। इस ऐतिहासिक चर्चा में प्रधानमंत्री के शामिल होने की संभावना है, जिसमें संविधान के मूल सिद्धांतों, विकास व देश के विकास में इसकी भूमिका पर समग्र विचार हो सकता है। इसे खास मौका बताया जा रहा है, जिसमें दोनों सदनों में संविधान के महत्त्व व प्रासंगिकता पर सरकार के साथ विपक्ष के नेताओं का संवाद होना तय है। शीतकालीन सत्र में विरोध व नारेबाजी से नाराज होकर राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मर्फी नियम का हवाला देते हुए कहा था, जो कुछ गलत हो सकता है, वह गलत ही होगा। लगातार सांसदों से शालीन बर्ताव करने की उम्मीद किए जाने के बाद भी विपक्ष सदन में चर्चा की बजाए हो-हल्ला करने व विरोध जताने में अपनी ऊर्जा लगा रहा है। विरोध करना व सरकारी कामकाज/निर्णयों पर संदेह करना निःसंदेह विपक्ष की जिम्मेदारी है। वह अपना काम करता है मगर कभी यह तरीका असंसदीय हो जाता है। सत्तापक्ष को भी अपने दायित्व को समझना चाहिए। विपक्ष को नजरंदाज करने का उसका तरीका संविधान के अनुकूल नहीं कहा जा सकता।

आधी आबादी/सोनम लववंशी

घरों में ही महफूज नहीं

महिलाओं के लिए उनका अपना घर सबसे महफूज माना जाता है, लेकिन अब वही घर सुरक्षित नहीं रहे। संयुक्त राष्ट्र महिला (यूएन वूमन) और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) की हालिया रिपोर्ट की मानें तो साल 2023 में हर दिन औसतन 140 महिलाओं और लड़कियों की हत्या उनके अपने घरों में कर दी गई। यह संख्या इस बात को रेखांकित करती है कि महिलाएं अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल करीब 51,100 महिलाओं और लड़कियों की हत्या उनके अंतरंग साथी या परिवार के सदस्यों द्वारा की गई, जबकि 2022 में यह आंकड़ा 48,800 था।

देखा जाए तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा की इस चरम सीमा का सबसे बड़ा कारण पितृसत्तात्मक सोच, लैंगिक असमानता और सामाजिक ढांचे में महिलाओं की कमजोर स्थिति का होना है। जब घर ही उनके लिए असुरक्षित बन जाए, तो यह समाज की संरचना पर गंभीर सवाल खड़े करता है। महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा का यह चरम हर क्षेत्र और वर्ग में देखा जा रहा है। चाहे वह विकसित देश हो या फिर विकासशील देश कोई भी इस समस्या से अछूते नहीं हैं। यह समस्या न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि समाज और देश की प्रगति पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है।

ऐसी घटनाएं केवल एक महिला की हत्या तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि पूरे परिवार और समुदाय को प्रभावित करती हैं। इस गंभीर स्थिति के समाधान के लिए सबसे पहले जरूरी है कि समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाए। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने की स्वतंत्रता देकर उनकी स्थिति को मजबूत किया जाए। घरेलू हिंसा के खिलाफ कठोर कानूनों को लागू किया जाए। घरेलू हिंसा का दंश झेल रही महिलाएं अक्सर सामाजिक दबाव, शर्मिंदगी, और कानूनी मदद की कमी के कारण अपनी समस्याओं को सामने नहीं ला पातीं। समाज के हर वर्ग को यह समझना होगा कि महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा केवल एक नैतिक दायित्व नहीं है, बल्कि यह समाज की उन्नति के लिए भी आवश्यक है।

अनमोल वचन

मुझे ये लगता है कि समय सभी चीजों को परिपक्व कर देता है; समय के साथ सभी चीजें उजागर हो जाती हैं; समय सत्य का प्रणेता है

-फ्रन्किओस रावेलैस

हमें भी गंभीर होना पड़ेगा

ऑस्ट्रेलिया : सोशल मीडिया पर प्रतिबंध

नूपुर द्विवेदी पाण्डेय

अपराजिता का मन पढ़ाई में नहीं लगता। उसकी दसवीं की परीक्षा सिर पर है, लेकिन वह हमेशा इस सोच में खोयी रहती है कि मैं इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट करूं जिससे मेरे सारे दोस्त हतप्रभ हो जाएं। उसकी ख्याली दुनिया उसकी असली दुनिया से बहुत परे है। अपनी ख्याली दुनिया में वह रोज मेहनत से दूसरों को बढ़ावा देती है। असल दुनिया में अपने लिए यह काम नहीं कर पाती। उसके कुछ कारण हैं, जिनमें से एक कि वह असल और काल्पनिक दुनिया में ऐसी उलझ कर रह गई है कि उसको भी नहीं पता कि कब सोशल मीडिया की झूठी दुनिया खत्म होती है और असल दुनिया का कड़वा सच शुरू होता है। इस ऊहापोह का परिणाम यह है कि आज वह पढ़ाई में पीछे होती जा रही है, जबकि दिमाग की बहुत तेज है। अपराजिता जैसे कितने ही बच्चे आज सोशल मीडिया के सच और कल्पना के बीच में पिस कर रह गए हैं।

ऐसे समय पर ऑस्ट्रेलिया का 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। पिछले साल संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्जन जनरल डॉ. विवेक मूर्ति ने सोशल मीडिया और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर एक दस्तावेज जारी किया था, जिसमें उन्होंने देशों से यह अपील कि वे सोशल मीडिया उपयोग के पूर्ण प्रभाव को बेहतर तरीके से समझें ताकि वे कुछ ऐसी नीतियां ले कर आएं जो बच्चों के हित में हो। सोशल मीडिया आज हमारे घर, परिवार और जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। माता-पिता सोशल मीडिया द्वारा अपने बच्चों के संपर्क में रहते हैं।

सुनने में भले ही अजीब लगे मगर आज की सच्चाई यही है कि सोशल मीडिया मुसीबत का कारण बना ही इसलिए, क्योंकि बड़ों ने इसको अपनी सहूलियत का जरिया बना लिया है। अब इस लेख को लिखने के लिए गूगल जैसे सर्च इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा, इस मुद्दे पर लोगों की राय क्या है उसका सर्वे लिंकेडिन और व्हाट्सएप्प के माध्यम से किया जा रहा और मजे की बात यह भी है कि सोशल मीडिया कितना कष्टकारी है, यह भी सोशल मीडिया के जरिये ही बताया जा रहा है। है न कमाल की स्थिति! अक्सर जब भी कोई आर्टिकल, या लेख लिखना होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों से उसके बारे में राय लूं। इस बार भी ली। प्रश्न था- क्या भारत में माता-पिता को अपने बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर अधिक सख्त नियंत्रण रखना चाहिए, या सरकार को बच्चों के लिए प्रतिबंध लगाना चाहिए? ज्यादातर अभिभावकों को यह लगता है कि यह माता-पिता और सरकार दोनों को जिम्मेदारी है (65 फीसद)। कुछ का यह मानना है कि सरकार को पहल करनी चाहिए (20 फीसद) और कुछ पूरी तरह माता-पिता की

जिम्मेदारी मानते हैं। सच तो यह है, कायदे कानून कितने भी कड़े क्यों न हो अभिभावक अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। घर में जब 3 लोग सोशल मीडिया स्टेटस को अपने सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ेंगे तो चौथा बच्चा तो इसको संभावित रूप से मान्य ही समझेगा। फिर हम सही और वह गलत कैसे?

एक ऐसे ही चर्चा में किसी ने अपना अनुभव साझा किया, कि यह खुद अपने माता पिता की सोशल मीडिया पर हर चीज शेयर करने की आदत से परेशान है और चाहते हैं कि कोई उनकी मदद करे। सुन कर हंसी भी आई और फिर लगा, बस अब यही सुनना बाकी था।

किस्से के कई पहलू

हर किस्से के कई पहलू होते हैं और सोशल मीडिया प्रतिबंध के भी हैं। क्योंकि सोशल मीडिया हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है- इसमें अगर मैं निष्पक्ष रूप से देखूं तो इसके कई सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखने मिल सकते हैं। एक-एक करके सब पर नजर डालते हैं।

सामाजिक : कैपिओस द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा उपयोग दोस्तों और परिवार से जुड़े रहने के लिए होते हैं। बच्चे इस रिपोर्ट से परे नहीं है। बच्चे भी चाहते हैं कि वह अपने दोस्तों से हमेशा हर वक्त जुड़े रहे और शायद यह सही है, लेकिन यह भी बताता है, कि अब हमारा समाज वह सीमित दायरा नहीं बल्कि पूरा विश्व है जो शायद उतना सुरक्षित भी नहीं।

आर्थिक : कुछ तो सीधे और साफ प्रभाव है, जैसे कि सोशल मीडिया कंपनियों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जुर्माना और दंड अलग, लेकिन एक बड़ा सवाल जो आ रहा है कि सरकार इसकी निगरानी कैसे रखेगी और इसी में काफी आर्थिक व्यवस्था की जरूरत है। नियम तभी तक लागू हो सकते है, जब तक उनके तोड़ के तरीकों को अनुशासित किया जाए।

मानसिक : बच्चों का गुस्सा, माता पिता की हताशा, शिक्षकों में झुंझलाहट-इन सब मानसिक और भावनात्मक परिणामों से जूझने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। ऐसे में यह जरूरी है कि हम बच्चों को सिर्फ यह न बताए कि सोशल मीडिया गलत है या उससे दूर रहो, बल्कि उनको ऐसे संसाधन दे, जिससे वह अपने समय और मन को सकारात्मक तरीके से उपयोग कर सके।

जब मैं तथ्यों की तलाश में थी, कि विश्व में 16 साल से कम के कितने बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादातर सर्वे हमें 18 साल से ऊपर के उपभोगताओं का डाटा देते हैं और शायद यही सबसे बड़ा सामाजिक चुनौती है। सबसे बड़ी मुश्किल होती है जानकारी का न होना, इस वक्त विश्व में 5.22 बिलियन सोशल मीडिया identities है जो हमारी कुल आबादी का 65 फीसद हिस्सा है। बहरहाल, किसी भी प्रतिबंध या रोक का पहला असर उसका प्रतिरोध होता है। और यह स्थिति भी कुछ अलग नहीं। बच्चे बगावत करेंगे और यहां सिर्फ माता-पिता या सरकार ही नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी बन जाती है कि इस मुहिम को सफल बनाए।

(लेख में विचार निजी हैं)

> सुनने में भले ही अजीब लगे मगर आज की सच्चाई यही है कि सोशल मीडिया मुसीबत का कारण बना ही इसलिए, क्योंकि बड़ों ने इसको अपनी सहूलियत का जरिया बना लिया है। अब इस लेख को लिखने के लिए गूगल जैसे सर्च इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा, इस मुद्दे पर लोगों की राय क्या है उसका सर्वे लिंकेडिन और व्हाट्सएप्प के माध्यम से किया जा रहा और मजे की बात यह भी कि सोशल मीडिया कितना कष्टकारी है, यह भी सोशल मीडिया के जरिये ही बताया जा रहा है

मेड इन इंडिया ब्यूटी ब्रांडों को बढ़ावा देने की कवायद

- पिछले कुछ वर्षों में भारत में ब्यूटी इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव हुआ है, और सैकड़ों स्वदेशी ब्रांड उभरे हैं
- यह उद्योग परिवर्तनकारी युग के कगार पर है, क्योंकि सौंदर्य परिदृश्य अपने अगले चरण का विकास देखने को तैयार है
- एक अनुमान के मुताबिक, भारतीय ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट 21-23 बिलियन डॉलर की है, और अगले पांच वर्षों में इसकी ऑनलाइन बिक्री तीन गुना बढ़ कर 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी

(स्रोत : इंडिया'ज ब्यूटी इंडस्ट्री : क्रैकिंग द कोड पैनल)

अमेजन या फ्लिपकार्ट से कोई आर्डर कैंसिल करें तो वे कोई जुर्माना नहीं लगाते मगर भारतीय रेलवे से लिया टिकट यात्रा की तारीख से 20 दिन पहले भी कैंसिल करो तो वह 3AC के लिए 1074 में से 214 रुपए काट लेता है! एक टिकट पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन में रेलवे का कितना खर्च आता होगा?

रंगनाथ सिंह, पत्रकार
@rangnathsingh_

भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत

नौसेना दिवस | लक्ष्मी शंकर यादव

पाकिस्तान व चीन की रक्षा तैयारियों को देखते हुए भारतीय नौसेना को अत्यन्त आक्रामक बनाया जा रहा है। हिन्द महासागर क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए नौसेना का फोकस रणनीतिक रूप से चीन की बढ़ती मौजूदगी का मुकाबला करने के लिए है। इसलिए भारतीय नौसेना अपनी ताकत बढ़ाने की तैयारी कर रही है जिससे वह आने वाले दिनों में और अधिक ताकतवर हो जाए।

समंदर में भारत की ताकत बढ़ाने के लिए नौसेना को इस माह के अंत तक एक नया गाइडेड मिसाइल युद्धपोत प्राप्त हो जाएगा। रूस द्वारा तैयार किए गए दो युद्धपोतों में से आईएनएस तुषील पहला है। रूस-यूक्रेन युद्ध के लंबा खिंचने के कारण आने में देरी हो गई। इसी युद्ध के चलते एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और परमाणु पनडुब्बी के मिलने में भी देरी होने की संभावना है। आईएनएस तुषील युद्धपोत ब्रह्मोस मिसाइलों सहित अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगा। तुषील के मिलने के बाद अगले वर्ष आईएनएस तमल गाइडेड मिसाइल युद्धपोत मिल जाएगा। इन दोनों पोतों के मिलने से भारतीय नौसेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी। उल्लेखनीय है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग सैन्य तकनीकी सहयोग की बैठक के लिए इसी माह रूस का दौरा करने वाले है। इन गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित अत्याधुनिक घातक हथियार तथा सैन्य अभियानों को अंजाम देने के लिए सेंसर लगाए गए हैं। तुषील गाइडेड मिसाइल युद्धपोत इलेक्ट्रॉनिक युद्धकला से सुसज्जित है। इसमें एंटी सबमरीन रॉकेट और तारपीडो लगाए गए है। इसकी लंबाई लगभग 129 मीटर है। इसकी स्पीड 30 नॉटिकल मील प्रति घंटा है। तुषील का वजन 3600 टन से ज्यादा है। इसमें 180 नौसैनिक यात्रा कर सकते हैं। भारत और रूस के बीच वर्ष 2016 में चार तलवार क्लास के स्टील्थ फ्रिगेट बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इसमें से दो रूस में और दो भारत में बनाए जाने थे। भारत में बनने वाला विशाखपट्टनम क्लास का चौथा गाइडेड मिसाइल युद्धपोत शीघ्र ही मिलने की उम्मीद है। यह 7400 टन वजन वाला है। इसमें लगी ब्रह्मोस मिसाइलें लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हैं। इसी वर्ष नीलगिरि फ्रिगेट भी नौसेना को मिलने वाला है। इसका वजन 6670 टन है और इसमें आठ ब्रह्मोस मिसाइलें लगी हैं। विदित हो कि भारतीय नौसेना वर्ष 2003 तलवार क्लास के जंगी जहाज शामिल हो रहे हैं।

वर्तमान में इस श्रेणी के छह स्टील्थ फ्रिगेट्स नौसेना के बेड़े का हिस्सा हैं। इनमें से चार को ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस कर दिया गया है और दो पर काम चल रहा है। इन युद्धपोतों के नौसेना में शामिल होने से भारत की समुद्री ताकत काफी बढ़ जाएगी। भारतीय नौसेना ने 27 नवम्बर 2024 के-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नौसेना ने यह परीक्षण परमाणु पनडुब्बी अरिघात से किया। इस पनडुब्बी को 2017 में लॉन्च किया गया था। अब इसका अपग्रेड वर्जन जल्द ही कमीशन किया जाना है। परमाणु पनडुब्बी अरिघात आईएनएस अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है। इस पनडुब्बी को विशाखापट्टनम में नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में निर्मित किया गया था। अब अरिहंत की तुलना में 6000 टन वजन वाली अरिघात के नये वर्जन को के-4 मिसाइलों से लैस किया जाएगा। इस परीक्षण में के-4 मिसाइल अपने सभी तय मानकों पर खरी उतरी। पनडुब्बी से इस मिसाइल का यह पहला परीक्षण था। वर्ष 2010 में इसका सबसे पहले परीक्षण किया गया था। तबसे अब तक इसके कई परीक्षण किए जा चुके हैं। यह मिसाइल 10 मीटर लंबी और 20 टन वजन वाली है। यह एक टन वजन का पेलोड ले जाने में सक्षम है। के-4 मिसाइलों की मारक दूरी 3500 किलोमीटर तक है। इसलिए बंगाल की खाड़ी में जब इन मिसाइलों को तैनात किया जाएगा तो ये मिसाइलें चीन के मेनलैंड तथा दक्षिण व पश्चिमी इलाके तक के क्षेत्र को अपने निशाने पर ले लेंगी। यही नहीं अपनी मारक क्षमता के तहत ये चीन राजधानी बीजिंग को भी निशाने पर ले सकती है। अरिघात 50 दिन से ज्यादा पानी के अंदर रह सकती है। इसलिए यह चीन के जासूसी जहाजों की नजरों से बचकर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सकती है।

अगर पाकिस्तान से मुकाबले की बात आती है तो अरिघात में तैनात होने पर ये इस्लामाबाद को भी नेस्तनाबूद कर सकती हैं। गौरतलब है कि भारत के पास पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइलों में कम दूरी की मारक क्षमता वाली के-15 मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें 750 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम हैं। पनडुब्बी आईएनएस अरिहन्त में ये मिसाइलें तैनात हैं। इसके अलावा भारत के पास भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) इंटर कॉन्टिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल के-5 पर काम कर रहा है। उम्मीद है कि इसकी मारक दूरी 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। इन सभी की तुलना में के-4 मिसाइलें ज्यादा सटीक, बेहतर एवं आसानी से ऑपरेट होती हैं। अमेरिका से खरीदे गए एमएच-60 रोमियो हेलीकॉप्टर शक्तिशाली पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं के साथ इस पोत पर तैनात रहेंगे। इन सभी के मिलने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी।

तप साधना | श्रीराम शर्मा आचार्य

संसार को, मानव जाति को सुखी और समुन्नत बनाने के लिए अनेक प्रयत्न हो रहे हैं। उद्योग-धंधे, कल-कारखाने, रेल, तार, सड़क, बांध, स्कूल, अस्पतालों आदि का बहुत कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। इससे गरीबी और बीमारी, अशिक्षा और असभ्यता का बहुत कुछ समाधान होने की आशा की जाती है; पर मानव अंतःकरणों में प्रेम और आत्मीयता का, स्नेह और सौजन्य का आस्तिकता और धार्मिकता का, सेवा और संयम का निर्झर प्रवाहित किए बिना, विश्व शांति की दिशा में कोई कार्य न हो सकेगा। जब तक सन्मार्ग की प्रेरणा देने वाले गांधी, दयानंद, शंकराचार्य, बुद्ध, महावीर, नारद, व्यास जैसे आत्मबल सम्पन्न मार्गदर्शक न हों, तब तक लोक मानस को ऊंचा उठाने के प्रयत्न सफल न होंगे। लोक मानस को ऊंचा उठाए बिना पवित्र आदर्शवादी भावनाएं उत्पन्न किए बिना लोक की गतिविधियां ईर्ष्या-द्वेष, शोषण, अपहरण आलस्य, प्रमाद, व्यभिचार, पाप से रहित न होंगी, तब तक क्लेश और कलह से, रोग और दरिद्र से कदापि छुटकारा न मिलेगा। लोक मानस को पवित्र, सात्विक एवं मानवता के अनुरूप, नैतिकता से परिपूर्ण बनाने के लिए जिन सूक्ष्म आध्यात्मिक तरंगों को प्रवाहित किया जाना आवश्यक है, वे उच्चकोटि की आत्माओं द्वारा विशेष तप साधन से ही उत्पन्न होंगी । मानवता की, धर्म और संस्कृति की यही सबसे बड़ी सेवा है। आज इन प्रयत्नों की तुरंत आवश्यकता अनुभव की जाती है, क्योंकि जैसे-जैसे दिन बीतते जाते हैं असुरता का पलड़ा भारी होता जाता है, देरी करने में अति और अनिष्ट की अधिक आशंका हो सकती है। समय की इसी पुकार ने हमें वर्तमान कदम उठाने को बाध्य किया। यों जबसे यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ, 6 घंटे की नियमित गायत्री उपासना का क्रम चलता रहा है; पर बड़े उद्देश्यों के लिए जिस सघन साधना और प्रचंड तपोबल की जरूरत होती है, उसके लिए यह आवश्यक हो गया कि 1 वर्ष हिमालय में रहा और प्रयोजनीय तप सफल किया जाए। इस तप साधना का कोई वैयक्तिक उद्देश्य नहीं। अनेक बार जल लेकर मानवीय गरिमा की प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है, फिर पलायनवादी कल्पनाएं क्यों करें। विश्व हित ही अपना हित है।

रीडर्स मेल

खत्म हो रेवड़ी कल्चर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज चाहे देश में कई राज्यों द्वारा चलाए जा रहे रेवड़ी कल्चर की आलोचना करते हैं, परंतु स्वयं भी अपनी केंद्र सरकार की मुफ्त अनाज बांटने की योजना का कभी विरोध नहीं किया है। कारण मुफ्त अनाज योजना केंद्र सरकार द्वारा कोरोना काल में शुरू की गई थी एवं यह योजना आज तलक भी जारी है, जबकि आज के समय में कोरोना काल की कब से विदाई हो चुकी है। परंतु मुफ्त अनाज बांटने की योजना आज भी लगातार जारी है जबकि इसका देश में सामाजिक तौर पर लगातार विरोध भी किया जा रहा है। फिर अब तो अनाज ही क्या मुफ्त बिजली, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त बस यात्रा आदि कई तरह की रेवड़ियां कई राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही है। तब यह भी विचार मन में आता है कि अगर इसी तरह से सब कुछ मुफ्त दिया जाता रहेगा तो सरकार अपनी योजनाओं के लिए पैसा कहां से लाएगी? कारण जब टैक्स ही वसूल नहीं किया जाएगा तब सरकार के पास अपनी नई योजनाओं को लागू करने के लिए रकम कहां से आएगी? अतः आज चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार उसे यह रेवड़ी कल्चर का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। बल्कि सभी को रोजगार देने का प्रयास करना चाहिए। वरना फिर आगे चल कर उस सरकार के कर्ज में घिर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तकलीफ की बात है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज भी इस मुफ्त की रेवड़ी कल्चर योजना का समर्थन कर रहे हैं जो कि किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता है।

मनमोहन राजावतराज, ई मेल

सख्ती की जरूरत

साइबर अपराधी आजकल नई-नई ट्रिक अपनाकर मासूम लोगों को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में इस तरह की घटनाओं में बहुत तेजी आई है जो निसंदेह गंभीर चिंता का विषय है। यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस विषय पर चिंता जताई है, लेकिन उससे भी आगे कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। डिजिटल अरेस्ट के मामलों में तो यह अपराधी मासूम लोगों को अपने हाथों की कठपुतली बना लेते हैं। लिहाजा यह अत्यंत आवशयक है कि न केवल देश की पुलिस बल्कि साइबर विशेषज्ञ नई तकनीक से वाकिफ हों बल्कि देश के युवाओं को भी इस विषय पर ट्रेनिंग देकर उनको हर तरह की चुनौतियों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाए।

बाल गोविंद, नोएडा

बुलंद करें आवाज

'मां मुझे कोख में मत मारो' इस वाक्य की वेदना आज भी समाज में मौजूद क्रूरता को समाप्त नहीं कर पाई है। सरकार और समाज द्वारा आयोजित विभिन्न गोष्ठियां, बनाए गए कानून और लागू की गई तमाम योजनाएं तब तक आधी आबादी के लिए फलदायी साबित नहीं होंगी, जब तक कन्या भ्रूणहत्या बंद नहीं होगी। कई राज्यों में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में काफी कम है। वंश चलाने और बढ़ाने के नाम पर सबको बेटा चाहिए, बेटी नहीं। निस्संदेह इसे रोकने के लिए कड़े कानून हैं, पर जब तक कोई कानून की शरण में नहीं जाएगा, तब तक अपराध थमेगा कैसे? देखा गया है कि ऐसे मामलों में माताएं अक्सर चुप रह जाती हैं, घर में घुटती रहती हैं, पर मुंह नहीं खोलती। लेकिन अब समय आ गया है कि आप भी अपनी आवाज बुलंद करें, इस अभिशाप से समाज एवं देश को मुक्त करें।

संदीप कुमार, मधुपुर, झारखंड

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया बिहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।

6 | संपादकीय
जनसत्ता | 4 दिसंबर, 2024

कल्पमेधा

स्वाभिमानी पुरुष कभी किसी के आश्रय पर नही जीवित रहते हैं। वे सहारा अवश्य मांगते हैं, पर अपमानित कभी भी नही होना चाहते, यही उनकी विशेषता है।

- टोरी

अमन पर आशंका

अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सहज और शांतिपूर्ण रखने के लिए भारत ने न केवल अपनी ओर से हर स्तर पर पहल की है, बल्कि कई बार विपरीत स्थितियों में भी सकारात्मक रुख दिखाया है। मगर लंबे समय से पाकिस्तान और चीन के रवैये की वजह से सीमा पर अक्सर तनाव और टकराव के हालात पैदा होते रहे हैं और उसके लिए कौन जिम्मेदार रहा है, यह अब दुनिया जानती है। बिना किसी उकसावे के चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास जिस तरह की गतिविधियां चलाता है, उसे किसी भी कसौटी पर उचित नहीं कहा जा सकता। भारत कूटनीतिक स्तर पर इस मसले को अक्सर उठाता रहा है। समय-समय पर होने वाली बातचीत के बाद कुछ समय तक सीमा पर शांति की स्थिति दिखती है, मगर फिर चीन की ओर से कोई न कोई ऐसी गतिविधि शुरू हो जाती है, जिससे उसकी मंशा पर संदेह होता है।

ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, जब भारत और चीन के बीच बातचीत के बाद कई सकारात्मक पहलकदमियां हुईं और शांति बहाली की उम्मीद जगी। इसके तहत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने सैनिकों को पीछे लौटाने के कदम उठाए गए। मगर पिछले कुछ वर्षों में भारत को लेकर चीन का जैसा रुख सामने आया है, उसके मद्देनजर यह आशंका लगातार बनी हुई है कि दोनों देशों के बीच तनाव के हालात में सुधार की स्थितियां कब तक बनी रहेंगी। अब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता ने बहुस्तरीय तनाव में बढ़ोतरी की है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फिलहाल शांति को भारत राहत के रूप में देख सकता है, लेकिन अगर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की गतिविधियों की वजह से दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है, तो यह भारत के लिए भी सचेत रहने का वक्त है। शायद यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ती चिंता की पृष्ठभूमि में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने सोमवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीन की सेना के बीच गतिरोध भले खत्म हुआ है, मगर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की मंशा नहीं बदली है। उस क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य ताकत का प्रदर्शन भारत के लिए चिंता का विषय है।

यह हकीकत है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन खुद को इस रूप में पेश कर रहा है, जिसमें उसे दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के तौर पर देखा-माना जाए। यह उसकी अपनी स्थितियों के अनुकूल हो सकता है, लेकिन इस क्रम में वह अपने पड़ोसी देशों की संप्रभुता का हनन या उनके सामने जोखिम पैदा करके करना चाहता है, तो यह हर लिहाज से गलत है। खासकर भारत को लेकर चीन का रवैया अब तक भरोसेमंद नहीं रहा है। अक्सर भारत और चीन के बीच बातचीत में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति कायम रखने और एक-दूसरे के क्षेत्र में किसी भी तरह की गतिविधियां या दखलअंदाजी न करने पर सहमति बनती है, मगर कुछ समय बाद चीन के पांव फिर बहकने लगते हैं। सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश में उसकी गतिविधियों को किस रूप में देखा जाएगा और उसके क्या कारण हैं? भारत अगर सीमा से संबंधित विवाद के सभी प्रश्नों का हल करना चाहता है, तो चीन को इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए और अपनी ईमानदार इच्छाशक्ति के साथ शांति के लिए बनी सहमति पर अमल करना चाहिए।

गिरावट की मुद्रा

डालर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट से अर्थव्यवस्था को एक और झटका लगा है। चालू वित्तवर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद घट कर 5.4 फीसद पर आ गया। उसमें सबसे बुरी गत विनिर्माण और आठ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की रही। थोक और खुदरा महंगाई अपने उच्च स्तर पर बनी हुई हैं। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है। ऐसे में डालर के मुकाबले रुपए की कीमत अब तक के सर्वाधिक निचले स्तर 84.76 पर पहुंच जाने से स्वाभाविक ही चिंता बढ़ गई है। रुपए की कीमत गिरने का असर सीधे-सीधे आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ता है। पहले ही लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, अब यह और बढ़ जाएगी। इसलिए कि कच्चे तेल से लेकर खाने के तेल, दवाओं के लिए कच्चा माल आदि बहुत कुछ बाहर से मंगाना पड़ता है, जिसका भुगतान डालर में करना पड़ता है। फिर विदेश यात्रा और विदेशों में पढ़ाई कर रहे छात्रों पर भी खर्च का बोझ बढ़ जाएगा।

रुपए की कीमत गिरने की बड़ी वजह फिलहाल डालर के मजबूत होने और नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स देशों को डालर का उपयोग न करने पर सौ फीसद शुल्क लगाने की चेतावनी बताई जा रही है। पर लंबे समय से रुपए की कीमत में नरमी का रुख बना हुआ है। कहा जा रहा था कि सरकार विदेशी मुद्रा भंडार के जरिए इस नरमी को कम करने का प्रयास करती रही, मगर नाकाम साबित हुई है। इसकी एक वजह बढ़ती महंगाई है, जो रिजर्व बैंक के ऊंची रेपो दर लागू करने के बावजूद काबू में नहीं आ रही। फिर, जब से अमेरिकी डालर मजबूत होना शुरू हुआ है और ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए हैं, विदेशी निवेशकों ने भारत से अमेरिका की तरफ रुख कर लिया है। निर्यात में बढ़ोतरी लाना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। मगर फिर भी हकीकत से आंखें चुराने की कोशिश ही देखी जाती है। जब केंद्र में यूपीए सरकार थी, तब भाजपा कहते न थकती थी कि रुपए की गिरती कीमत उसका इकबाल गिरने की निशानी है। मगर विचित्र है कि वह खुद इसे संभाल नहीं पा रही।

घरेलू बाजार से बढ़ेगी आर्थिक मजबूती

हमारे पास उभरता हुआ विशाल बाजार, युवाओं में जबर्दस्त ढंग से आगे बढ़ने की ललक, उद्यमिता की भावना और सुधार का रवैया आदि ऐसे कारण हैं, जिनसे वैश्विक संघर्ष और चुनौतियों के बावजूद भारत में नए अवसरों की बहुलता है।

जयंतीलाल भंडारी

इस समय जब रूस-यूक्रेन युद्ध सहित विभिन्न भू-राजनीतिक कारणों से वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर है, भारत की विकास दर ऊंची बनाए रखने के लिए घरेलू बाजार की मजबूती जरूरी है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वित्तवर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) यानी विकास दर अनुमान से कम 5.4 फीसद रह जाने का प्रमुख कारण घरेलू बाजार का कमजोर हो जाना है। यह कमजोरी प्रमुख रूप से महंगाई, सरकारी व्यय में कमी, जीएसटी संबंधी उलझनें तथा अधिक 'लाजिस्टिक' लागत जैसे घटकों के कारण दिखाई दे रही है। ऐसे में, हर संभव उपायों से घरेलू बाजार की रफ्तार बढ़ाने पर ध्यान देना जरूरी है। 'डेलाइट इंडिया' की 'इंडियाज होम एंड हाउसहोल्ड मार्केट रिपोर्ट 2024' में कहा गया है कि भारत का घरेलू बाजार दस फीसद से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ रहा है। इस तेज गति से वर्ष 2030 तक भारत का घरेलू बाजार लगभग 237 अरब डालर की ऊंचाई पर पहुंच सकता है।

निश्चित रूप से भारत के घरेलू बाजार की मजबूती में देश में वस्तुओं, सेवाओं, कृषि उत्पादों और प्रतिभूतियों की बढ़ती हुई मांग और आपूर्ति की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा डिजिटलीकरण, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, कृषि का तेज विकास, 'मैन्युफैक्चरिंग हब' बनने की डगर, युवा उपभोक्ताओं की बढ़ती क्रय शक्ति तथा छलांगें लगा कर बढ़ता सेवा क्षेत्र भी घरेलू बाजार को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण है। इसमें कोई दो मत नहीं कि देश की अर्थव्यवस्था में घरेलू बाजार अहम भूमिका निभा रहा है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा कि इस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था में चमकते हुए सितारे के रूप में रेखांकित हो रही भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में भारत के घरेलू बाजार की बड़ी भूमिका है। अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मार्गन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी जेमी डिमान के मुताबिक घरेलू बाजार के दम पर तेजी से आगे बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था को देख कर दुनिया अचंभित है। स्विस कंपनी एसआइजी के सीईओ सैमुअल सिग्रिस्ट ने कहा है कि दुनिया में भारत का घरेलू बाजार तेजी से कारोबार बढ़ाने की सारी विशेषताएं रखता है।

निस्संदेह देश में तेजी से आत्मनिर्भरता की नीति और 'वोकल फार लोकल' के मंत्र को आगे बढ़ाना होगा। इससे हमारे स्थानीय और घरेलू बाजार मजबूत होंगे। वर्ष 2014 से लगातार स्थानीय उत्पादों के उपभोग और स्थानीय श्रम को अच्छे मूल्य पर जोर दिए जाने जैसे अभियान से शहरों से गांवों तक स्वदेशी सामान की खरीदी में जोरदार उछाल आया है। चीन से त्योहारी उत्पादों के आयात में कमी के साथ-साथ खिलौनों और दवा बनाने की मूल सामग्री 'बल्क ड्रग इंटरमीडिएटस' (एपीआइ) के आयात में भी सराहनीय कमी आई है। विनिर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सरकार रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रही है। भारत में घरेलू बाजार को तेजी से बढ़ाने में डिजिटलीकरण की भूमिका को बढ़ाना होगा। इससे जहां भारत में वित्तीय समावेश में मदद मिल रही है, वहीं डिजिटलीकरण

लागत को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल बनाने और सेवाओं को सस्ता करने में भी प्रभावी योगदान दे रहा है। इससे भारतीय घरेलू बाजार को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता मिल रही है।

'इन्फोसिस' के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी का कहना है कि

> दुनिया की नजरों में यह युग भारत के घरेलू बाजार को रफ्तार देने का युग है। दुनिया में भारत ग्लोबल 'फिनटेक एडाप्शन' के मामले में पहले क्रम पर है। इंटरनेट उपभोक्ताओं के मामले में दूसरे क्रम पर है। स्टार्टअप के मामले में तीसरे और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मामले में चौथे क्रम पर है। दरअसल, भारत के पास उभरता हुआ विशाल बाजार, युवाओं में जबर्दस्त ढंग से आगे बढ़ने की ललक, उद्यमिता की भावना और सुधार का रवैया आदि ऐसे कारण हैं, जिनसे वैश्विक संघर्ष और चुनौतियों के बावजूद भारत में नए अवसरों की बहुलता है।

भारत ने अपने अनोखे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और नई डिजिटल पूंजी के सहारे पिछले दस साल में घरेलू बाजार को वह ऊंचाई दी है, जिसे पारंपरिक तरीके से काम करते हुए पाने में पांच दशक तक लग जाते। दुनिया की नजरों में यह युग भारत के घरेलू बाजार को रफ्तार देने का युग है। दुनिया में भारत ग्लोबल 'फिनटेक एडाप्शन' के मामले में पहले क्रम पर है। इंटरनेट उपभोक्ताओं के मामले में दूसरे क्रम पर है। स्टार्टअप के मामले में तीसरे और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मामले में चौथे क्रम पर है। दरअसल, हमारे पास उभरता हुआ विशाल बाजार, युवाओं में जबर्दस्त ढंग से आगे बढ़ने की ललक, उद्यमिता की भावना और सुधार का रवैया आदि ऐसे कारण हैं, जिनसे वैश्विक संघर्ष और चुनौतियों के बावजूद भारत में नए अवसरों की बहुलता है।

घरेलू निवेशकों के दम पर, चुनौतियों के बीच, भारतीय शेयर बाजार अपनी प्रभावशीलता बनाए हुए हैं। सरकार ने कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है। देश में कृषि उन्नयन, खेती में नवाचार को प्रोत्साहन देने, लागत को कम करते हुए उत्पादन के साथ ही किसानों की आय बढ़ाने का अभियान आगे बढ़ाया है। घरेलू बाजार को मजबूत बनाने के लिए खाद्य पदार्थों की तेजी से बढ़ती महंगाई को रोकने और विकास की जरूरतों के बीच उपयुक्त तालमेल जरूरी है। चौदह नवंबर को जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, अक्तूबर में थोक महंगाई दर बढ़ कर 2.36 फीसद पहुंच गई, जो चार महीने का उच्चतम स्तर है। बीते महीने खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से सब्जियों और विनिर्मित वस्तुएं महंगी हो गई हैं। जिन राज्यों में महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी हैं, उनमें छत्तीसगढ़, बिहार, ओड़िशा, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश प्रमुख हैं।

ऐसे में सरकार को कुछ महत्त्वपूर्ण उपायों पर ध्यान देकर घरेलू बाजार को मजबूत बनाने की रणनीति पर आगे बढ़ना होगा। 'लाजिस्टिक' लागत घटाने के लिए 'नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकनामिक रिसर्च' की उस रपट पर ध्यान देना होगा, जिसमें कहा गया है कि 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद में लाजिस्टिक की लागत 7.8 से 8.9 फीसद रही, वही स्थिति अब भी है। साथ ही, शहरी क्षेत्रों में ई-कामर्स के क्षेत्र में वाहनों के आवागमन की लागत कुल लाजिस्टिक लागत का 50 फीसद है। ऐसे में शहरों में माल की आवाजाही के प्रबंधन और लाजिस्टिक की लागत कम करने के लिए उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने महानगरों के लिए जो व्यापक शहरी लाजिस्टिक योजना (सीएलपी) तैयार की है, उसे तेजी से लागू करना होगा। यह पहल इसलिए लाभप्रद हो सकती है, क्योंकि इसका लक्ष्य माल और लाजिस्टिक प्रबंधन को सुसंगत बनाना और वाहनों से जुड़ी गतिविधियों को भीड़-भाड़ और प्रदूषण से बचाते हुए जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है।

उम्मीद है कि सरकार घरेलू बाजार को मजबूती देने के लिए आत्मनिर्भरता की नीति और 'वोकल फार लोकल' के मंत्र को देश के कोने-कोने में ले जाएगी। उम्मीद है कि जीएसटी और आय कर में सरलता लाई जाएगी। निवेश के लिए अधिक अनुकूल माहौल बनाया जाएगा। कृषि सुधारों जैसे रणनीतिक कदमों से देश के घरेलू बाजार की गतिशीलता बढ़ाई जाएगी। ऐसे में जीडीपी के नए आंकड़ों के तहत चालू वित्तवर्ष की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था की धीमी पड़ी रफ्तार को बढ़ाया जा सकेगा। घरेलू बाजार की मजबूती से चालू वित्तवर्ष 2024-25 के तहत विकास दर सात फीसद से अधिक की ऊंचाई पर पहुंच सकेगी।

दुनिया मेरे आगे

चिंता की गुत्थियां

राकेश सोहम्

आज पूरी दुनिया द्रुत गति से विकसित हो रही है। आर्थिक संपन्नता के साथ-साथ लोग सुविधा संपन्न भी हो गए हैं। सुविधापरस्ती की अंधाधुंध होड़ के बीच चिंता और उससे उपजे तनाव की बात भी जोर-शोर से चल रही है। ढेरों प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि चिंता क्या है, चिंता होती क्यों है, इसके क्या कारण हैं, इससे कैसे दूर रहा जाए? इन्हें समझना इतना कठिन क्यों है? चिंतक भी चिंता में हैं। वे समझाते हैं कि चिंतन ही चिंता से बचने का उपाय है। चिंतन की गहराई में उतरे बिना चिंता को नहीं समझा जा सकता है। परेशान लोग नए प्रश्नों और शंकाओं की झड़ी लगा देते हैं। चिंतन में कैसे उतरा जाए? क्या चिंता से चिंतन में उतरा जा सकता है? दरअसल, चिंता जैसी गूढ़ गुत्थी सुलझाना और जान पाना सदैव अधूरा ही है।

यों चिंताओं को जानना बहुत आसान मालूम पड़ता है। चिंताएं हर व्यक्ति को होती हैं। हमारे इर्द-गिर्द चिंता की कमी नहीं है। ये बहुतायत में व्याप्त हैं। इसलिए ऐसा मान लिया जाता है कि हम चिंताओं को बखूबी जानते हैं। मगर ऐसा नहीं है। दुनिया में कई लोग, न केवल चिंताओं से घिरे हुए हैं, बल्कि उसकी कैद में दिखाई पड़ते हैं। वे परेशान हैं, छटपटा रहे हैं, चिंता से मुक्ति का मार्ग खोज रहे हैं। बाबाओं के चक्कर काट रहे हैं, नींद की गोलियां फांक रहे हैं, नशे का सहारा ले रहे हैं। उनकी हंसी कहीं खो गई है। हल्की-सी मुस्कान भी होंठों पर नहीं तैरती दिखती। चेहरे पर खुशी नहीं झलकती। मानो उनकी हंसी, खुशी और मुस्कुराहटों पर चिंताओं की पहरेदारी बैठा दी गई हो!

> चिंता से बचने के उपाय व्यक्ति को खुद ही खोजने होंगे। सामान्य तौर पर जो हमारी पहुंच या नजरों से परे है, वही चिंता के कारण होते हैं। अधिकतर चिंताओं का संबंध भूत और भविष्य से हुआ करता है। भूतकाल बीत चुका है, भविष्य अनदेखा है।

आधुनिकता की भागदौड़ से भरी जीवनचर्या में चिंता का होना स्वाभाविक लगता है। लोग चिंता में घिरे तनावपूर्ण जिंदगी जीने के आदी होते जा रहे हैं और असमय काल के गाल में समा जाते हैं। आज पत्र-पत्रिकाएं, टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया भी चिंता को लेकर चिंता में दिखते हैं। ये सिखाने में जुटे हैं कि चिंता से कैसे बचें! इनमें हर बार वही बातें, विन्यास, चिंतकों के वही उद्धरण, बचाव के वही तरीके और उपाय दोहराए जाते हैं, लेकिन लोगों के जीवन से चिंता कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वे और भी घनीभूत हो रही हैं। वाट्सऐप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया के मंच ऐसे कथित ज्ञान से अटे पड़े हैं। ये मंच ऐसे ज्ञान को बांटने के मामले में अग्रणी हैं। इनमें सहारा खोजते लोग समय बे-समय चिंताओं से निपटने के ज्ञान को एक-दूसरे को बांट भी रहे हैं। इसके बावजूद न चिंता कम होती दीख रही है और न ही किसी के समझ में आती है!

चिंता को समझना टेढ़ी खीर है। इसे ठीक-ठीक समझना भी मानो चिंता का ही विषय है। चिंता निराकार होती है। इसका कोई रूप या आकार-प्रकार नहीं होता। इसकी कोई भौतिक अवस्था नहीं है। इसे छूकर देखना संभव नहीं है। फिर भी इसके बारे में बड़े मजेदार तथ्य हैं। चिंताएं छोटी-बड़ी होती हैं। जरूरी नहीं है कि जो विषय किसी एक व्यक्ति के लिए चिंता का कारण है, वह दूसरे के लिए भी दुखदायी हो। दूसरे व्यक्ति के लिए वह प्रसन्नता का विषय भी हो सकता है! एकांत में रहने वाले लोग भीड़ की चिंता करते हैं, जबकि भीड़भाड़ में रहने वाला व्यक्ति एकांत से डरता है।

हमारे आसपास ऐसे अनेक परिवार हैं, जिनके बच्चे अमेरिका में रहते हैं। एक परिवार के मुखिया अपने बच्चों के पास विदेश में इसलिए नहीं रह पाते कि उन्हें अकेलेपन से डर लगता है। वहां की जीवनशैली ऐसी है। वे वहां दो महीने रुकने की योजना के साथ निकलते हैं और हफ्ते दस दिन में उकताने लगते हैं। वहीं दूसरे परिवार के दंपति पूरे छह महीने रुककर आनंद का अनुभव करते हैं। उन्हें वहां की सुकून और शांति रास आती है। छह महीने में अपने देश लौटते हुए बहुत उदास हो जाते हैं।

बहरहाल, चिंता से बचने के उपाय व्यक्ति को खुद ही खोजने होंगे। सामान्य तौर पर जो हमारी पहुंच या नजरों से परे है, वही चिंता के कारण होते हैं। अधिकतर चिंताओं का संबंध भूत और भविष्य से हुआ करता है। भूतकाल बीत चुका है, भविष्य अनदेखा है। इन्हें कुछ किया नहीं जा सकता है, सिवा सोचने के। बस चिंता की जा सकती है। इसलिए चिंता से बचने के लिए वर्तमान में जीने की बात कही जाती रही है। मान लिया जाए कि हम किसी हाइवे या उच्च मार्ग पर चल रहे हैं। मार्ग से गुजरते हुए पीछे किसी दुर्घटना पर नजर पड़ जाए, तो आगे रास्तों में स्वाभाविक तौर पर अफरातफरी होगी। पुलिस व्यवस्था की गहमागहमी हो सकती है। ऐसी स्थिति में आगे और पीछे की बातें ध्यान में रखी जा सकती हैं, उसकी चिंता में घुलने की जरूरत नहीं। रास्ते में जहां तक नजर जाती है, उसे सोचना चाहिए। जो दिख रहा, उसके प्रति सचेत रहा जाए। यही चिंता से मुक्ति का मार्ग है। वर्तमान के प्रति चेतना, यही साक्षी भाव है। चिंता को मिटाना जरूरी काम को निपटाने से होगा। अगर प्रयास के बाद भी काम न निपटे तो यह परिस्थितिजन्य हुआ। इसे स्वीकार करना चाहिए। सही समय की प्रतीक्षा करना चाहिए। यही अपने हाथ में है।

बहुत-सी गैर जरूरी चिंताओं से मुक्त होने की बात कही गई है। दरअसल, व्यक्ति की कुल चिंताओं में से गैरजरूरी चिंताओं का अनुपात ही ज्यादा होता है। असल चिंताएं कम होती हैं। बेमतलब की चिंता को त्यागने की जरूरत है। बस वर्तमान का ध्यान रखा जाए। अच्छे पठन-पाठन से भी चिंताओं से बचा जा सकता है। सुलझी सोच के लोग चिंता में नहीं घुलते, चिंताओं से नहीं घिरते, क्योंकि यह चिंता की बात है।

भ्रष्टाचार की जड़ें

'हकदार बनाम हकमार' (संपादकीय, 2 दिसंबर) सामयिक है। दरअसल, यह प्रशासन में व्यापक रूप से फैले भ्रष्टाचार के अलावा समाज के प्रत्येक वर्ग में नैतिक मूल्यों के पतन का भी प्रमाण है। कमजोर तबके के लिए चलाई जा रही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठाने के लिए समृद्ध परिवार केवल अकेले दोषी नहीं होते। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी खुद उन्हें ऐसी योजनाओं का लाभ उठाने के रास्ते दिखाते हैं और इसके लिए आवश्यक कागजी कार्यवाही पूरी करने में उनकी मदद करते हैं और उन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह पूरा खेल योजनाबद्ध तरीके से होता है। कई बार इस प्रकार के घपले और आर्थिक भ्रष्टाचार सामने आने पर उनकी जांच का नाटक किया जाता है। जांच आयोग भी बनाए जाते हैं, लेकिन असल दोषियों को कभी नहीं पकड़ा जाता। इसमें मुफ्त सरकारी योजनाओं के अंतर्गत घटिया खाद्य सामग्री का वितरण भी शामिल है। इस भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिए ईमानदार प्रयास, कठोर कार्रवाई और दोषियों को सजा देने की जरूरत है, अन्यथा यह अनैतिक कार्य चलता रहेगा।

- इशरत अली कादरी, भोपाल

नैतिक शोध जरूरी

चिकित्सा अनुसंधान में दवाओं और उपचारों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए जानवरों का उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। अक्तूबर 2022 में शोधकर्ताओं ने चूहों के दिमाग में न्यूरान्स प्रत्यारोपित किए। जबकि मानव जीवन को बहुत मूल्यवान माना जाता है। अब सवाल उठता है कि पशु और अन्य जीवों के जीवन का क्या? हाल के वर्षों में, प्रौद्योगिकी में प्रगति ने पशु परीक्षण के बेहतर विकल्प प्रदान किए हैं। जानवर भी इंसानों की तरह दर्द महसूस करते हैं और उन्हें अनावश्यक पीड़ा देना निस्संदेह अमानवीय है। इसके अलावा, जानवरों पर प्रभावी उपचारों की कोई गारंटी नहीं है कि वे इंसानों पर भी वैसे ही काम करेंगे, क्योंकि जैविक अंतर के कारण परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं। कई लोग इस मुद्दे को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जानवरों का जीवन भी महत्त्व रखता है।

- हिमांशी बोरा, जम्मू

बयान पर राय

मोहन भागवत ने कहा कि कुटुंब समाज का हिस्सा है और हर परिवार एक इकाई है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 फीसद से नीचे नहीं होनी चाहिए। इसके लिए दो की बजाय तीन बच्चे पैदा करें। यह संख्या इसलिए जरूरी है, ताकि समाज जिंदा रहे। इसी तरह का विचार आंध्र और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने रखा था, तो उनका मजाक उड़ाया गया था। दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि बुजुर्गों की आबादी बढ़ने से राज्य की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ सकता है, जैसा जापान, चीन और यूरोप के कई हिस्सों में हो रहा है, जहां युवाओं से ज्यादा बुजुर्गों की संख्या है। नायडू ने यह भी कहा था कि दक्षिणी राज्यों में प्रजनन दर 1.6 हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत 2.1 से कम है। तब राष्ट्रवादियों ने इन मुख्यमंत्रियों का मजाक उड़ाया था। मगर आज वही लोग भागवत के बयान पर खामोश बने हुए हैं। निश्चित रूप से देश की आबादी में गिरावट दर्ज की जा रही है, पर इसके लिए सरकार को नीति निर्धारित करनी चाहिए।

- जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

साइबर संजाल

लोगों की मेहनत की कमाई विदेशों में बैठे साइबर अपराधी जिस प्रकार से साफ कर रहे हैं, सुरक्षा एजंसियों के लिए उन तक पहुंचना चुनौती है। इन देशों के अलग-अलग कानून, एजंसियों के सबूत जुटाने की राह में रोड़ा साबित हो रहे हैं। इन साइबर अपराधियों ने इस वर्ष चार महीनों में ही 1,777 करोड़ रुपए की राशि भारतीयों से हड़पी है। 'डिजिटल अरेस्ट' को हथियार बना कर 120 करोड़ की राशि लोगों से धोखाधड़ी कर और डरा-धमका कर वसूली गई। सुरक्षा एजंसियों के लिए अपराधियों को पकड़ना उनके विरुद्ध सबूत इकट्ठा करना और धोखाधड़ी की राशि वसूल करना नामुमकिन हो रहा है। इन अपराधों में अलग-अलग देश के सर्वर और सिम चुनौतियों को और भी मुश्किल बना रहे हैं। साइबर अपराध और साइबर अपराधियों को सजा देने के लिए कठोर कानून बनाना जरूरी है।

- आरके शर्मा, रोहिणी, दिल्ली

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 248

जीएसटी दरों की हो व्यापक समीक्षा

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ढांचे को उपयुक्त बनाने की अनुशंसाओं के लिए बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गठित राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति के बारे में खबर है कि उसने अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दे दिया है। उसने 148 वस्तुओं की कर दरों में भी महत्त्वपूर्ण बदलाव किए हैं। हालांकि इस समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुआ, कुछ अनुशंसाओं की दिशा सही नहीं है। इस संदर्भ में यह बात याद करना उचित होगा कि यह प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है। इसकी कम से कम दो बड़ी वजह हैं। पहली, बीते वर्षों में यह व्यवस्था अपेक्षित प्रदर्शन कर पाने में नाकाम रही। आंशिक तौर पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दरों को कम करने में अपरिपक्वता बरती गई। गत वित्त वर्ष में क्षतिपूर्ति उपकर सहित कुल कर संग्रह कमोबेश उतना ही रहा जितना राजस्व जीएसटी के पहले उन करों से हासिल होता था जिन्हें जीएसटी ढांचे में समाहित कर लिया गया। संभावनाएं बहुत अधिक थीं।

दूसरा, क्षतिपूर्ति उपकर जिसे जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद केवल पांच सालों तक वसूल किया जाना था, उसकी अवधि बढ़ाई गई ताकि कर्ज चुकाया जा सके और कोविड-19 महामारी के दौरान राज्यों को हुई राजस्व हानि की भरपाई की जा सके। अगले वर्ष जब कर्ज का पुनर्भुगतान हो जाने के पश्चात अगर जरूरी कानूनी बदलाव नहीं किए गए तो यह संग्रह रोक दिया जाएगा। एक अन्य मंत्री समूह इस पहलू पर विचार कर रहा है। जीएसटी परिषद अगर दोनों मंत्री समूहों की अनुशंसाओं पर चर्चा करने के पश्चात बदलाव करेगी तो बेहतर होगा और कम से कम उथलपुथल की स्थिति बनेगी।

दरों को औचित्य भरा बनाने में परिषद का प्राथमिक उद्देश्य राजस्व-तटस्थ दर पर जाना होना चाहिए। साथ ही साथ करों की स्लैब की संख्या को भी कम किया जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय द्वारा संसद को दी गई जानकारी के मुताबिक 2023-24 में जीएसटी की औसत दर 11.6 फीसदी थी। जीएसटी को लागू करते समय एक विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाई गई राजस्व-तटस्थ दर 15 से 15.5 फीसदी थी। कम औसत कर दर ने राजस्व संग्रह पर असर डाला है।

हालांकि दरों को वाजिब बनाने में मंत्री परिषद की अनुशंसाएं अभी ज्ञात नहीं हैं किंतु जिन सुझावों के बारे में जानकारी है उनके मुताबिक वे व्यापक सिद्धांत का पालन करती नहीं नजर आ रही हैं। खबरों के मुताबिक समिति का इरादा है कि तंबाकू से बने उत्पादों तथा गैस वाले पेय पदार्थों पर 35 फीसदी की दर से कर लगाया जाए। इससे स्लैब और बढ़ जाएंगी। इतना ही नहीं, इसका इरादा टैक्सटाइल उत्पाद पर उनकी कीमत के मुताबिक अलग-अलग कर लगाने की अनुशंसा करने का भी है। अन्य उत्पादों के लिए भी ऐसी ही अनुशंसाएं की जा सकती हैं। इससे कर ढांचा और जटिल हो सकता है तथा इनपुट क्रेडिट से जुड़े विवाद बढ़ सकते हैं। मंत्री समूह जीएसटी को प्रगतिशील बनाना चाहता है। बहरहाल, अप्रत्यक्ष कर ढांचे में इसे हासिल करने की सीमा है।

ढांचे को सहज बनाने पर काम होना चाहिए। इससे अनुपालन बढ़ेगा और विवाद में कमी आएगी। इससे न केवल छोटे कारोबारियों के लिए कारोबारी सुगमता में सुधार होगा बल्कि राजस्व बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। परिषद को अतीत की गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए जो आज भी कर ढांचे को प्रभावित कर रही हैं। ध्यान देने वाली बात है कि सरकार ने संसद को भी सूचित किया है कि एक ओर जहां विभिन्न दरों पर कर संग्रह का आकलन नहीं किया जा सकता वहीं अनुमान दर्शाते हैं कि गत वित्त वर्ष 70-75 फीसदी जीएसटी संग्रह 18 फीसदी के स्लैब से आया। 12 फीसदी के स्लैब से सिर्फ 5-6 फीसदी राजस्व प्राप्त हुआ। ऐसे में 12 फीसदी की दर को 18 फीसदी में मिला देने से कोई खास उथल पुथल नहीं होगी। ऐसी अन्य संभावनाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर परिषद के लिए यह अहम है कि वह सभी प्रासंगिक सूचनाओं का सावधानी से परीक्षण करे ताकि जीएसटी ढांचे को ऐसा सहज बनाया जा सके जिससे सरकार समेत सभी अंशधारकों को लाभ हो। अप्रत्यक्ष कर ढांचे में व्याप्त कमियों को दूर करने का मौका गंवाना नहीं चाहिए।

अजय मोहंती

शिक्षा क्षेत्र में हो एआई का समुचित इस्तेमाल

एआई का हौआ खड़ा करने के बजाय जरूरत इस बात की है कि शिक्षा के क्षेत्र में उसका भरपूर इस्तेमाल किया जाए और उसकी क्षमताओं का पूरा लाभ लिया जाए। समझा रहे हैं अजित बालकृष्णन

एक समाचार की सुर्खियां हैं: 'शिक्षकों: एआई आपकी नौकरियां ले लेगा!' एक अन्य सुर्खी सवाल करती है, 'क्या एआई विश्वविद्यालयों में निरर्थक नौकरियों को खत्म कर देगा?' तीसरी सुर्खी कहती है, 'छात्रों ने विश्वविद्यालय की परीक्षा में एआई की मदद से धोखाधड़ी की' इन दिनों रोज ऐसी खबरें हमें देखने को मिलती हैं। ये खबरें न केवल ऑनलाइन समाचार पत्रों में देखने को मिलीं बल्कि दुनिया के कुछ अत्यंत प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के जर्नल्स में भी नजर आईं। स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है उसे किस तरह समझा जाए?

अगर कुछ देर के लिए इन बातों पर विचार किया जाए तो दरअसल कहा यह जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं और एक व्यक्ति के रूप में मेरी चिंता जो दरअसल इस मध्यवर्गीय मान्यता पर आधारित है कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था प्रगति और आर्थिक तरक्की का सबसे अहम वाहक है, अगर ऐसा है: क्या एक देश के रूप में हम अपने स्कूलों, कॉलेजों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और चिकित्सा महाविद्यालयों आदि में एआई का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं?

अभी तक यह माना जा रहा था कि हाल के दिनों के अन्य तकनीकी नवाचारों मसलन कंप्यूटर और इंटरनेट की तरह एआई भी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में उपयोगी और सहायक भूमिका निभाएगा। परंतु अब हमारे सामने स्थिति यह है कि शायद एआई की वजह से सीखने और सिखाने की हमारी जांची-परखी तकनीक, स्कूल और कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों जैसे संस्थान और परीक्षा आदि की व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाना पड़ सकता है।

मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने दिन के चार-पांच घंटे पाइथन प्रोग्रामिंग में बिताए हैं, अपने मनोरंजन के लिए कई उभरते अलगोरिद्म का इस्तेमाल किया है (मेरे लिए यह वैसा ही है जैसे मेरे कुछ दोस्तों के लिए टीवी या मोबाइल पर क्रिकेट मैच देखना), ऐसे में मेरा निजी मत अब तक यही रहा है कि एआई के बारे में अधिकांश खबरें बढ़ाचढ़ाकर पेश की गई या चौंकाने वाली रही हैं। मसलन, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ओपनएआई (चैटजीपीटी बनाने वाली) में 14 अरब डॉलर देकर हिस्सेदारी खरीदी गई है। उसकी यह कोशिश शायद गूगल को सर्च या खोज में पछाड़ने की रणनीति का हिस्सा थी। गूगल इस कारोबार से अरबों डॉलर कमाती है। परंतु अब मुझे चिंता हो रही है कि एआई तकनीक में शायद बाजार हिस्सेदारी और राजस्व से अधिक कुछ दांव पर लगा है। खासतौर पर शिक्षा जैसे अहम क्षेत्र में। मैं खुद दिन में कई बार चैटजीपीटी का इस्तेमाल करता हूं और अपनी शंकाओं का निवारण करता हूं। मिसाल के तौर पर मैं उससे पूछता हूं कि स्वस्थ रहने के लिए एक व्यक्ति को दिन में कितने मिनट पैदल चलना चाहिए।

चैटजीपीटी जवाब देता है, 'अच्छा स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए एक वयस्क व्यक्ति को रोज शाम 30 से 60 मिनट तक तेज पैदल चलना चाहिए। हृदय के स्वास्थ्य, वजन के प्रबंधन और तनाव से राहत के लिए इतनी तेज गति से चलना चाहिए कि दिल की धड़कनें बढ़ें लेकिन आप बातचीत करने के लायक रहें।'

इस बात ने मुझे राहत दी क्योंकि इससे मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने चिकित्सक की सलाह पर जो कर रहा हूं वह एकदम सही दिशा में है। अगर मैंने एक सर्च इंजन से यही सवाल किया होता तो उसने मुझे वेबसाइट्स के अनगिनत लिंक प्रदान किए होते, जिन्हें मुझे खोलकर पढ़ना पड़ता। मुझे लगता है कि चैटजीपीटी और अन्य एआई विकल्पों की ओर जाने की एक प्रमुख वजह यह है कि वे इंसानों की तरह बातचीत करते हैं। इसके अलावा मेरे दिमाग में कई ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं है कि उन्हें किस तरह पूछा जाए। उदाहरण के लिए, 'कृपया मुझे बताएं कि मुंबई में इतनी सारी ऊंची इमारतें खाली क्यों पड़ी हैं?' चैटजीपीटी का जवाब है, 'मुंबई की खाली पड़ी ऊंची इमारतें संपत्ति की बढ़ी हुई कीमतों, नियामकीय देरी, अनबिके मकानों, डेवलपर्स के दिवालिया होने और शहरी चुनौतियों के बीच मध्य वर्ग के खरीदारों की सीमित क्षमता के कारण है।' ऐसा जवाब इस मुद्दे को लेकर बुनियादी समझ पैदा करने में मदद करता है।

आज पूरी दुनिया में यह चिंता है कि स्कूल या कॉलेज के छात्र चैटजीपीटी या अपने मोबाइल फोन की मदद से परीक्षा के सवालों के जवाब तलाश कर सकते हैं। फिर चाहे निबंध लिखना हो, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर तलाशने हों या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से जुड़ी पहेलियों का जवाब तलाशना हो। इसके परिणामस्वरूप सभी तरह की परीक्षाओं के लिए परीक्षा कक्षों में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी गई। फिर चाहे वे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन की परीक्षाएं हों या आईआईएम की प्रवेश परीक्षा। परंतु इन सभी बातों के चलते मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या स्कूल और कॉलेजों के हमारे शिक्षण और परीक्षण में अधिक बुनियादी बदलावों की आवश्यकता है। मौजूदा व्यवस्था यह है कि छात्र कक्षाओं में रोज कई घंटों तक शांति से बैठे रहते हैं और इसके बाद घर जाकर पढ़ने और लिखने (गृहकार्य) जैसे अकादमिक काम करते हैं। कई जगह से ऐसे सुझाव आए हैं (कैलिफोर्निया स्थित खान अकादमी के संस्थापक और सीईओ साई खान ने भी अपनी हालिया पुस्तक ब्रेव न्यू वर्ड्स में यही कहा है) कि छात्रों को 'गृहकार्य' के रूप में दिया जाने वाला काम स्कूल में ही करने देना चाहिए और रिकॉर्ड किए गए लेक्चर घर में अपनी सुविधा से देखना चाहिए।

जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी में कंप्यूटर विज्ञान के जानेमाने प्रोफेसर अशोक गोयल ने एआई आधारित आभासी शिक्षण सहायक 'जिल वॉटसन' विकसित किया है जो इस प्रकार डिजाइन है कि छात्रों की जिज्ञासाओं को ऑनलाइन हल किया जा सके। माना जा रहा है कि इस नवाचार ने ऑनलाइन शिक्षा के प्रभाव और दायरे को बहुत बढ़ाने का काम किया है, खासकर जॉर्जिया टेक के कंप्यूटर विज्ञान विभाग के ऑनलाइन मास्टर ऑफ साइंस के अध्ययन में। क्या आज का समय सन 1448 जैसा है जब गुटेनबर्ग प्रेस का अविष्कार किया गया था। उसकी बदौलत किताबों के जरिये ज्ञान और शिक्षा, दोनों सभी लोगों को उपलब्ध हो सके। इससे पहले इंसानों को खुद किताबों की प्रतियां लिखकर तैयार करनी होती थीं।

जोमैटो : चीफ ऑफ स्टाफ पद के लिए आवेदन

प्रिय दीपी (दीपेंद्र गोयल),

मुझे पता है कि अब आप कोई आवेदन नहीं ले रहे हैं, फिर भी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं! लेकिन पहले मैं आपको एक सच बता दूं। कई अच्छे लोगों ने मुझे आपके चीफ ऑफ स्टाफ पद के लिए आवेदन न करने की सलाह दी है। उनका मानना है कि सफल उम्मीदवार से पहले साल में पैसे लेना सही नहीं है।

मेरे एक दोस्त ने अपना स्टार्टअप बेच दिया और वह सोशल मीडिया पर एक बेहद संवेदनशील विषय पर बात करते-करते एन्फ्लुएंसर बन गया। उसने महज 17 महीनों में इंस्टाग्राम पर दस लाख फॉलोअर जुटा लिए। उसका कहना है कि कुछ स्टंट यानी 'तिकड़मबाजी' करके लोगों का ध्यान आकर्षित (यानी अधिक फॉलोअर) किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश, लगता है यह बात बहुत दूर तक पहुंच गई है, और कई मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अब समस्याओं को हल करने की बजाय, नए-नए स्टंट करने के तरीके ढूंढ रहे हैं।

हालांकि, मेरा दोस्त भी मानता है कि नौकरी वाला आपका पोस्ट एक अच्छा आइडिया था। 20 लाख रुपये में हम कई संभावनाएं तलाश सकते हैं जैसे आपके पास खूब सीखने को मिलेगा और आपको ऐसा अनुभव मिलेगा जो कोई भी बिजनेस स्कूल नहीं दे सकता है।

आइए चंद सेकंड हम इस बात पर गौर करते हैं कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों से लोग क्या सीखकर निकल रहे हैं। नौकरी देने वाली कंपनियों के लोग इन छात्रों की गुणवत्ता के स्तर को देखकर हैरान रह जाते हैं और वे छात्रों की इस भीड़ के लिए कई तरह के नाम दे देते हैं जिनमें से 'अनएम्प्लॉयबल यानी नौकरी के लायक नहीं' एक ऐसा शब्द है जिसे इस अखबार में लिखा जा सकता है।

यहां कुछ छात्र अच्छे भी हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। वर्ष 2023-24 की आर्थिक समीक्षा में एक उल्लेखनीय बात निकल कर आई कि कॉलेज से निकलने वाले हर दो स्नातकों में से एक नौकरी दिए जाने के लायक नहीं होता है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी वीर सांघवी को एक साक्षात्कार में बताया कि लगभग 1.9 करोड़ लोग रेलवे की 60,000 नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं और पीएचडी करने वाले लोग भी चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन करने पर मजबूर हैं।

पिछले दिनों एक बिजनेस अखबार में खबर आई थी कि आईआईटी के छात्र एडटेक कंपनियों से जुड़ रहे हैं और कोचिंग सेंटर में शिक्षक बन रहे हैं। इस खबर में जो नहीं लिखा वह यह है कि जिन पेशेवरों को उद्योग में ढंग की नौकरी नहीं मिल पाई, वे ही मजबूरी में शिक्षक बन गए। ऐसे में वे कैसे लाखों छात्रों को इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं?

अनदेखी
सुवीन सिन्हा

खैर, जहां तक आपका सवाल है, आपका चीफ ऑफ स्टाफ बनकर बहुत कुछ सीखने की गुंजाइश बन सकती है। आखिरकार, आप ही वह शख्स हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप को यूनिकॉर्न के मुकाम तक पहुंचाया। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आपने ब्लिंकिट को तब खरीदा जब वह संकट से घिरी हुई थी और उसे मजबूरी में बेचा जा रहा था। अब यह आपकी कंपनी जोमैटो से भी आगे निकलती हुई दिख रही है। कोई व्यक्ति बिजनेस स्कूल जाकर इस महत्त्वपूर्ण बदलाव से जुड़ी केस स्टडी को पढ़ सकता है या अगर कोई आपका चीफ ऑफ स्टाफ बन जाए तब भी वह करीब से देख सकता है कि आप यह सब काम कैसे कर रहे हैं। ऐसे में यह बात निकलकर आती है कि इसके लिए आखिर कोई तंत्र क्यों न बनाया जाए? सिर्फ आप ही नहीं, शायद अन्य स्टार्टअप संस्थापक भी मिलकर कोई ऐसा प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं जहां योग्य उम्मीदवारों को सफल संस्थापकों के साथ काम करने का मौका मिलेगा।

लेकिन, आपके सामने भी एक समस्या हो सकती है। आपने कहा कि आपको करीब 18,000 आवेदन मिले। आखिर ये कैसे आवेदन हैं? मुझे लगता है कि इनमें से कुछ आवेदक वास्तव में आपसे सीखने के इच्छुक होंगे। कुछ आपके प्रशंसक भी हो सकते हैं। कुछ बेहद परेशान करने वाली नौकरियों में फंसे लोग हो सकते हैं। मुझे इस बात का भी डर है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो जीवन में कुछ हासिल न कर पाए हों लेकिन अब वे अपने माता-पिता को 20 लाख रुपये देने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हों।

सवाल यह है कि मैं कौन हूं? मैं आपके पोस्ट से निश्चित रूप से प्रभावित हुआ हूं। आपके अंदाज और आपके आत्मविश्वास का क्या ही कहना। आप वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो 'सही काम करना चाहता हो, भले ही इसकी कीमत दूसरों को नाराज करके क्यों न चुकानी पड़े।' मुझे ऐसा ही लग रहा है (और दूसरा हिस्सा स्वाभाविक रूप से जुड़ गया है।)

मुझे पूरा यकीन है कि आप कोई अजीब या अविश्वसनीय व्यक्ति नहीं हैं। जिस व्यक्ति ने ब्लिंकिट की तकदीर बदल दी वह अविश्वसनीय तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप भी अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा रहे हैं। ऐसे में निश्चित रूप से आप यह सुनिश्चित करेंगे कि उस व्यक्ति का लगाया गया समय और पैसा व्यर्थ न जाए। मुझे यह भी लगता है कि आप निश्चित रूप से एक साहसिक वादा कर रहे हैं कि आपको 'एक शीर्ष प्रबंधन संस्थान की दो साल की डिग्री की तुलना में 10 गुना अधिक सीखने को मिलेगा।'

यह बात भी मुझे आकर्षित करती है कि मैं जो 20 लाख रुपये दूंगा, वह सीधे फीडिंग इंडिया के लिए दान राशि के तौर पर चला जाएगा और इसके बदले आप मेरी पसंद के किसी चैरिटी संस्थान को 50 लाख रुपये दान कर देंगे। इस तरह मैं अपनी आमदनी के स्तर को देखते हुए एक साल में ही इतना दान कर दूंगा, जितना दो जिंदगियों में कर पाता। इसके अलावा, अगर आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अपने वादे पर खरा उतरता है तब लोगों के काम की उत्पादकता में तेजी आएगी और सभी के पास काफी कुछ होगा, ऐसे में वेतन कम महत्त्वपूर्ण हो जाएगा। मुझे इस बात पर भी पूरा भरोसा है।

हालांकि, बस आश्वस्त होने के लिए मैंने अपने एक दूसरे दोस्त, कंवलदीप सिंह को फोन किया। मैंने उन्हें इसलिए फोन किया क्योंकि वे एक अधिकारी होने के साथ लीडरशिप कोच भी हैं और वह हमेशा मेरा फोन भी उठा लेते हैं। उन्होंने शुरुआत में आपके, मेरे और आदर्श स्थिति में एक मध्यस्थ के बीच गंभीरता से बातचीत की सलाह दी। उनके मुताबिक इस बातचीत के माध्यम से हमें मानवीय स्तर पर जुड़ना चाहिए। हमें एक-दूसरे को बताना चाहिए कि हमारी क्या उम्मीदें हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या मैं सिर्फ आपका शेड्यूल बनाऊंगा और मीटिंग की तैयारी में आपकी मदद करूंगा? मुझे इसका अंदाजा कैसे मिलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं? मुझे आपकी कंपनी का संपूर्ण तरीके से जायजा लेने का मौका मिलेगा? अगर मुझे तीन महीने बाद कोई संदेह होने लगे तब क्या होगा? साल के अंत में यह कैसे निर्धारित होगा कि यह काम हमारे लायक था या नहीं?

मुझे पता है कि आप मुझ पर विचार नहीं करेंगे। आप 200 शब्दों का एक पत्र चाहते थे लेकिन मैंने जो पत्र लिखा है वह लगभग 950 शब्दों का है। लेकिन कोई बात नहीं। आपके अपने इस प्रस्ताव से पीछे हटने को लेकर मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई।

आपने समझाया कि 20 लाख रुपये महज एक 'फिल्टर' था और आप इनमें से अधिकांश आवेदनों को अस्वीकार कर देंगे जिनमें 'पैसे के बारे में बात' की गई है। आपने इस बात को साबित करने के लिए यह कहते हुए अपने डायरेक्ट मेसेज के स्क्रीनशॉट तक पोस्ट कर दिए कि पैसे लेना आपकी इस योजना का हिस्सा कभी नहीं था। मैं सोशल मीडिया का दबाव समझता हूं। लेकिन आपका यह रक्षात्मक रुख कहीं से भी 'कूल' नहीं है। आप मेरा आवेदन वापस लेने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको इसे पढ़ने में मजा आया? क्या आप इस तरह लिखना सीखना चाहेंगे? हमारे यहां सालाना इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू होने वाला है। यह एक महीने के लिए है और हम इस एक महीने की इंटर्नशिप के लिए 30,000 रुपये का भुगतान करते हैं।

आपका पक्ष

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य सभा में बताया कि गुजरात में पिछले 4 वर्षों में जीएसटी चोरी के 12,803 मामले दर्ज किए गए

उच्च जीएसटी दरों की अस्वीकार्यता

लेख 'जीएसटी दरें बढ़ाकर राजस्व बढ़ाएं' पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सम्मेलन में जीएसटी दरों को राजस्व संग्रहण बढ़ाने के विचारों को स्पष्ट करता है। दूसरी तरफ उद्योग व्यापार संगठनों और ग्राहक जनमानस जीएसटी दरों को कम करने की मांग कर रहे हैं। आयकर की दरों में पिछले तीन दशकों के परिवर्तन को देखें तो सिद्ध होता है कि धरातल की वास्तविकता, अंतरराष्ट्रीय कीमतों, कर प्रावधानों के अनुपालन, प्रशासनिक क्षमता, व्यापार की सुगमता, स्वदेशी उद्योगों के प्रोत्साहन, छोटे और मध्यम उद्योगों की विदेशी विशेषकर चीन के माल से प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा और सबसे अधिक कर अपवंचन को ध्यान में रखते हुए जीएसटी की कम दरों का प्रावधान आवश्यक और श्रेयस्कर है। इससे धोखाधड़ी, रिफंड स्कैम, अनुपालन की समस्याएं खड़ी नहीं होती है। एक तरफ अमेरिका और चीन जैसे देश अपने उद्योगों को संरक्षित करने के लिए आयातित सामान पर नए- नए टैरिफ लगा रहे हैं और अपने उद्योगों को भरपूर समर्थन दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम इसके विपरीत अपने ही उद्योगों को उच्च राजस्व दरों से आहत कर रहे हैं। जीएसटी जनता की जेब से जाता है, उद्योग व्यापार से नहीं क्योंकि यह अप्रत्यक्ष कर है जिसका बोझ जनता उठाती है। नीति निर्धारण के शिखर से यदि उच्च कराधान के विमर्श चलने लगें तो जनता और उद्योग व्यापार संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। जीएसटी की संरचना को उद्योग व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुनर्गठित किया जाए और कम दरों के साथ अनुपालन प्रक्रिया को भी सरल किया जाए।

विनोद जौहरी, दिल्ली

प्राकृतिक खेती रसायनमुक्त शुद्ध भोजन प्रदान करती है

वर्तमान समय में खेती करने की प्रणाली पूर्ण तरीके से बदल चुकी है, जिसका एकमात्र कारण है बढ़ती जनसंख्या। जिसकी वजह से अधिक खाद्यान्न उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। इस कारण खेतों में अधिक रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है। लोग जैविक खेती को भूलते जा रहे हैं जिसके कारण हमें शुद्ध भोजन नहीं मिल पा रहा है। अत्यधिक रासायनों के प्रयोग से भोजन भी विषाक्त होता जा रहा है। जबकि जैविक खेती भारतीय कृषि की एक प्राचीन पद्धति है, जो भूमि के प्राकृतिक गुणों को बनाए रखने के साथ हमें रसायनमुक्त शुद्ध भोजन प्रदान करती है। यह पर्यावरण की शुद्धता को बनाए रखने में मदद करती है। जैविक खेती में गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, जीवाणु खाद, फसल अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि द्वारा पौधों को पोषक तत्त्व दिए जाते हैं तथा प्रकृति में उपलब्ध जीवाणुओं, मित्र कीट और जैविक कीटनाशकों द्वारा फसल को हानिकारक जीवाणुओं से बचाया जाता है। पिछले कई वर्षों से खेती में काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण खेती में प्रयोग होने वाले रसायन हैं। अगर किसान खेती में अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो उन्हें जैविक खेती की तरफ अग्रसर होना चाहिए।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में मंगलवार को रक्षा प्रमुख (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान, थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी तथा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

चर्चा पर सहमति

होना अंततः यही था। आदर्श स्थिति भी यही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर यह तय किया कि संसद की कार्यवाही के अवरोध अब खत्म कर दिए जाएंगे। सत्ता पक्ष ने संविधान पर संसद में दो दिन की चर्चा कराने की विपक्ष की मांग स्वीकार कर ली और विपक्ष भी सहमत हो गया कि संसद का कामकाज अब नियमित रूप से चलने दिया जाएगा। मगर मामला सिर्फ संविधान पर चर्चा का नहीं है। संसद के हरेक सत्र में दोनों सदनों को ढेर सारे विधायी काम करने होते हैं। बहुत सारे विधेयक पेश किए जाते हैं, जिन पर कई सारे संशोधन आते हैं, कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, शून्यकाल में भी अनेक जरूरी चर्चाएं होती हैं। किसी भी लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए यह सब बहुत जरूरी चीजें हैं। संसदीय कामकाज के लंबे अवरोध इन जरूरी प्रक्रियाओं के लिए भी बाधक बन जाते हैं। कई बार तो गतिरोध के कारण महत्वपूर्ण विधेयकों तक पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय नहीं बचता और उनके गुण-दोष की विस्तृत समीक्षा के बिना ही उनको पारित करना पड़ता है। यहां पर एक पुराना आंकड़ा याद करना जरूरी है। पिछले साल ही मानसून सत्र के दौरान हमें यह बताया गया था कि संसद की एक मिनट की कार्यवाही पर ढाई लाख रुपये का खर्च आता है। ऐसे में, हम यह गणना कर सकते हैं कि एक दिन के अवरोध का आर्थिक दबाव कितना होता है। यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि इस बार यह अवरोध पूरे छह दिन चला है। लेकिन यह कोई रिकॉर्ड अवधि नहीं है, हमारी संसद इससे भी लंबे अवरोध देख चुकी है।

ज्यादातर लोकतंत्रों में ऐसे अवरोध को संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है, पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि संसद अंततः चर्चा व विमर्श का एक मंच है।

इस सर्वदलीय बैठक के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की जिद का जो पर्वत था, वह अब पिघल चुका है। अगले सप्ताह के अंत में जब संसद के दोनों सदनों में संविधान पर चर्चा चलेगी, तो संविधान से जुड़े बहुत से नए-पुराने मुद्दों पर विभिन्न दलों की सोच सामने आएगी। इस लिहाज से यह भी गौरतलब है कि कुछ विपक्षी पार्टियों ने तो पिछले आम चुनाव के दौरान संविधान को ही चुनावी मुद्दा बना दिया था। यहां तक कि उन्होंने संसद सदस्य के रूप में शपथ भी संविधान को हाथ में लेकर ही ली। लेकिन संविधान एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर सत्ता पक्ष के पास भी विपक्ष को घेरने के लिए काफी कुछ है। इसलिए उम्मीद है कि यह चर्चा महत्वपूर्ण तो होगी ही, दिलचस्प भी होगी। यह बहस इसलिए भी अहम है कि हम संविधान अपनाए जाने के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं।

बहरहाल, विपक्ष द्वारा पैदा किए गए अवरोध की वजह से पूरे एक सप्ताह तक देश की संसद का काफी कामकाज हंगामे की भेंट चढ़ गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। आज का विपक्ष अगर यह कर रहा है, तो आज के सत्ताधारी जब विपक्ष में थे, तब वे भी यही करते थे। साल 2012 में एक ऐसे ही मौके पर भारतीय जनता पार्टी की नेता सुषमा स्वराज ने कहा था, संसद को काम न करने देना भी लोकतंत्र का ही एक रूप है। बेशक उनकी इस बात में दम है। दुनिया के ज्यादातर लोकतंत्रों में इस तरह के अवरोध को संसदीय प्रक्रिया का एक हिस्सा ही माना जाता है। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि संसद अंततः चर्चा और विमर्श का एक मंच है। यह अवरोध का मंच ही न बन जाए, यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है। अवरोध कितने भी हों, अंत में चर्चा पर ही सहमति बनानी पड़ती है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 04 दिसंबर, 1949

शांति की खोज

एक के बाद दूसरे युद्ध का शिकार बनती हुई लोकसृष्टि मानो ऊब चली है और ऐसे रास्ते की खोज में है, जिससे नित्य के ये संघर्ष बन्द हों और मनुष्य शांतिपूर्वक उत्कर्ष-कार्य में संलग्न हो। शांतिवादियों का एक वर्ग काफी समय से ऐसे विचारों का रहा है, परन्तु युद्ध में शामिल न होने के नगण्य रास्ते के सिवा कोई निश्चित एवं सक्रिय तरीका वह ढूंढ़ पाया हो, यह नहीं कह सकते। इस बात का श्रेय तो महात्मा गांधी को ही है कि अहिंसा और असहयोग के रूप में उन्होंने इसका एक तरीका न केवल उपस्थित किया है, बल्कि उसे अपनाकर विश्व की एक बहुत बड़ी राजशक्ति को स्वदेश मुक्ति की अपनी बात मानने के लिए भी विवश किया है। अतः यह स्वाभाविक और उचित ही है कि उन्हीं के देश भारत में विश्व-शांतिवादियों का सम्मेलन आजकल हो रहा है।

आजकल गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर के शांति-निकेतन में यह हो रहा है और इसके बाद महात्मा गांधी के सेवाग्राम में जाकर यह अपने विचारों को निश्चयात्मक रूप देने का प्रयत्न करेगा। गुरुदेव और महात्माजी दोनों ही ऐसे महापुरुष थे, जिन्होंने विश्व-शांति की आराधना की, अतः सम्मेलन का यह द्वि-स्थानीय कार्यक्रम सुन्दर है और हम आशा करते हैं कि दोनों की भावनाओं की छत्रछाया में सम्मेलन ऐसा निश्चय करने में समर्थ होगा, जो शांतिवाद को सक्रिय एवं जीवित रूप में पैदा कर सकेगा। सम्मेलन में उपस्थित एक अमरीकन शांतिवादी कुमारी वेरा ब्रिटेन ने शांति-निकेतन के चीनी भवन में भाषण करते हुए आशा दिलाई भी है कि सम्मेलन का निश्चय क्या होगा, यह तो अभी नहीं कहा जा सकता किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि विश्व की विचारधारा में यह एक नये युग का प्रारम्भ करेगा।

शांति की आवश्यकता तो असंदिग्ध है परन्तु, जैसा कि विश्व-शांति-सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए राजकुमारी अमृतकौर ने कहा, आज भी अधिकांश व्यक्ति यह मानते हैं कि युद्ध के सिवा हमारी समस्याओं का कोई और समाधान नहीं है। राजकुमारीजी के अनुसार ऐसी मान्यता होना बताता है कि कहीं-न-कहीं कोई गलती अवश्य है और इस गलती को दुरुस्त करने की कोशिश करना ही विश्व-शांति-सम्मेलन जैसे सम्मेलनों का काम है।

बांग्लादेश में कट्टरता न हो बेलगाम

संजय के भारद्वाज | प्रोफेसर, जेएनयू

बांग्ला अस्मिता को समझने वालों ने चार आधार पर बांग्लादेश बनाया था - धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, समाजवाद और बांग्ला राष्ट्रवाद, पर आज यह देश कहां फंस गया?

बांग्लादेश में तख्तापलट के चार महीने पूरे होने जा रहे हैं, पर अभी भी वहां हालात चिंताजनक हैं। वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति दिनोंदिन बिगड़ती क्यों जा रही है? क्या कारण है कि वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा लगातार खतरे में है? इस पूरे परिदृश्य को हम कैसे देखें? अभी बांग्लादेश में अंतरिम सरकार है। क्या ऐसी सरकार के लिए बांग्लादेश के संविधान में प्रावधान है? इस सरकार पर वैधता का संकट है, क्योंकि यह जनता द्वारा चुनी गई सरकार नहीं है और दूसरी बात, यह निकट भविष्य में चुनाव कराने के बारे में सोच भी नहीं रही है।

बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सलाहकारों की कार्यवाहक सरकार है, जिस पर अल्पसंख्यकों, उदारवादियों, प्रगतिशीलों, समाजवादियों की रक्षा न कर पाने के आरोप लग रहे हैं। केवल अल्पसंख्यकों या हिंदुओं पर ही नहीं, अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भी हमले की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस नोबेल विजेता जरूर हैं, पर उनके 85 प्रतिशत सलाहकार ऐसे हैं, जो पहले बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के समय अपनी सेवाएं दे चुके हैं। खासकर साल 2001 से 2006 के बीच जब बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी की सरकार थी, तब ये सलाहकार किसी न किसी पद पर काबिज थे।

बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद जो सरकार गठित हुई है, उसके बाद ज्यादातर जो नियुक्तियां हुई हैं, वे जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्ताओं की हुई हैं। ये विश्वविद्यालयों में कुलपति बन गए हैं, न्यायपालिका, प्रशासन, सेना, पुलिस में भी उन्हें पद मिल गए हैं।

यह कोई नई बात नहीं है, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के ऐसे समूह मुक्तिवाहिनी के समय से ही रहे हैं, जिन्होंने सदा पाकिस्तानीकरण का पक्ष लिया है। आज ऐसे ही लोग सत्ता में आ गए हैं। इनका मानना है कि बंगबंधु मुजीबुर्रहमान के बजाय मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रपिता का दर्जा देना चाहिए। ये लोग मानते हैं कि बांग्लादेश का निर्माण तो जिन्ना ने किया था। कट्टरता तरह-तरह से फिर से सिर उठाने लगी है।

अंतरिम सरकार से कई लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं। खासकर ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों को उम्मीद थी कि एक लोकतांत्रिक सरकार आएगी, जो रोजगार पैदा करेगी, भ्रष्टाचार का अंत करेगी, निष्पक्ष चुनाव कराने पर ध्यान देगी। बांग्लादेश में बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं, जो धोखे का अनुभव कर रहे हैं। इस सरकार को कौन चला रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है।

बांग्लादेश में जो सरकार है, उसके पीछे जमात है और जमात के पीछे पाकिस्तान है। मोहम्मद यूनुस के पीछे अमेरिकी समर्थन है, डेमोक्रेट नेता यूनुस के समर्थक रहे हैं। यूनुस पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन के संपर्क में रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर जमात के साथ तालमेल बिठाया और यूनुस को आगे रखते हुए शेख हसीना का तख्तापलट कर दिया। क्या तख्तापलट को बांग्लादेशियों ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया है? ध्यान देने की बात है कि बांग्ला अस्मिता को समझने वाले लोगों ने चार आधार पर बांग्लादेश बनाया था- धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, समाजवाद और बांग्ला राष्ट्रवाद। आज सोचने वाली बात है कि बांग्लादेश की बुनियाद किस हाल में है? बांग्लादेश को समझने वाले उदार लोगों ने पहले भी अपने देश को बचाया है और अभी भी उम्मीद रखनी चाहिए कि ये लोग देश के पुनर्निर्माण के लिए वापसी करेंगे। यह कहना गलत नहीं होगा कि 5 अगस्त को जो आंदोलन हुआ था, वह अभी अधूरा है। अमेरिका में भी सत्ता परिवर्तन होने वाला है और आगामी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश को कट्टरता की राह पर नहीं जाने देंगे। उन्होंने हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं।

आंतरिक रूप से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बांग्लादेश पर जमात का ही कब्जा हो गया हो। आने वाले समय में चुनाव तो करवाने पड़ेंगे और चुनाव में अवामी लीग को ताकत दिखाने का मौका मिलेगा। अवामी लीग कतई कमजोर नहीं है। इसकी नेता शेख हसीना भारत में हैं और उनके बिना भी लीग मजबूती से चुनाव लड़ सकती है। देश के कोने-कोने में अवामी लीग की मौजूदगी है। उम्मीद है, जो बंगाली समाज अपनी संस्कृति के लिए 1947 से लड़ता आया है, वह अपनी समावेशी संस्कृति को नहीं छोड़ेगा।

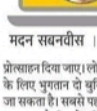

इसमें कोई शक नहीं कि कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ संघर्ष तो करना पड़ेगा। इस्कॉन के पूर्व प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास ऐसी ताकतों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके साथ ही अन्य 17 लोगों को राजद्रोह के मामले में बंदी बनाया गया है। इस्कॉन के 19 पदाधिकारियों के बैंक खातों पर रोक लग गई। कोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया है। अल्पसंख्यकों की आवाज दबाने की साजिश रची जा रही है।

पहले लग रहा था कि मोहम्मद यूनुस देश को उबार लेंगे, पर हकीकत यह है कि उनकी छवि अब बहुत अच्छी नहीं रही। यूनुस को लघु ऋण योजनाओं के लिए जाना जाता है, उसमें ब्याज निहित है और ब्याज को इस्लाम में नाजायज माना जाता है। बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी भी यूनुस को नहीं मानते थे, मगर मजबूरी में जिम्मेदारी देनी पड़ी। असल में, वह महज चेहरा हैं और उनके नेतृत्व में बनी सरकार निष्पक्ष नहीं है। वैसे, बांग्लादेश में सिर्फ हिंदू निशाने पर नहीं हैं, बौद्धों के जो इलाके हैं, वहां मुस्लिमों को बसाने के प्रयास होते रहे हैं। मूल निवासी चकमा को बांग्लादेश छोड़कर भारत के पूर्वोत्तर में शरण लेनी पड़ी है। वहां रोहिंग्या का गलत इस्तेमाल कट्टरपंथी कर रहे हैं।

बांग्लादेश के लिए भारत की चिंता बिल्कुल जायज है। वहां जिस किस्म के नारे लग रहे हैं, उससे खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। मिसाल के लिए, एक नारा लग रहा है, हमारा बाबर, तुम्हारा बाबर, हर तरफ बाबर-बाबर। ध्यान रहे, लुत्फोज्जमान बाबर बांग्लादेश में बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी की सरकार के समय साल 2001-2006 के बीच गृह मंत्री थे। उनके बारे में जांच में खुलासा हुआ था कि भारत के पूर्वोत्तर में हथियारों की तस्करी में उनका हाथ था। तब भारत विरोधी आतंकियों को बांग्लादेश में शरण मिलती है। आज बाबर को याद करने का मतलब है कि एक बड़ा कट्टरपंथी समूह वहां ऐसा है, जो भारत या पूर्वोत्तर भारत को अस्थिर करने का इरादा रखता है। भारत को हर पल सचेत रहना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जो उद्योग रोजगार बढ़ाए, उसे ही धन प्रोत्साहन दिया जाए

मदन सबनवीस | वरिष्ठ अर्थशास्त्री

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 120-130 लाख औपचारिक नौकरियां जुड़ती हैं। यह अच्छी खबर है। दूसरी ओर, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल बेरोजगारी दर 7.2 प्रतिशत से 9 प्रतिशत के बीच रही है। बेरोजगारी (साप्ताहिक स्थिति) पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के आंकड़ों से पता चला है कि तिमाही आधार पर बेरोजगारी 6.5 प्रतिशत से 6.7 प्रतिशत के बीच रही है। इस प्रकार हमें मिले-जुले संकेत मिलते हैं।

साल 2024-25 के केंद्रीय बजट में सरकार ने एक रोजगार-संबद्ध योजना (ईएलआई) पेश की थी, जिसके तहत पहली बार काम पाने वाले कर्मचारियों को दो साल के लिए उनकी ओर से वेतन या भविष्य निधि योगदान आवंटन किया गया था। सरकार ने शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप योजना भी शुरू की है, पर क्या कंपनियों को अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का कोई सीधा तरीका हो सकता है? केंद्र और राज्य सरकारें नीतियां बनाती हैं, भौतिक और वित्तीय बुनियादी ढांचा प्रदान करती हैं, जिससे निजी क्षेत्र को विकास करने में मदद मिलती है। रोजगार संबंधी योजना बनाते समय निजी कंपनियां हमेशा उत्पादकता व लाभ को देखती हैं। कोविड के बाद लोगों को नौकरियां देने के स्थान पर प्रौद्योगिकी के अधिक इस्तेमाल पर जोर रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के चलन में आने के साथ ही नौकरी पर लोगों की मांग घटने की स्पष्ट आशंका है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के क्षेत्र में भी अतिरिक्त कर्मचारी रखने की अवधारणा पुरानी हो चुकी है। यहां अब नियुक्ति बहुत जरूरी होने पर ही की जाती है।

आज देश में ज्यादा रोजगार की जरूरत है। ज्यादा लोगों की भर्ती करने वाली कंपनियों को कई तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है।

सरकार के लिए नीतिगत प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि वह नौकरियों से जुड़ी प्रोत्साहन (जेएलआई) योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करे, जो इसकी उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को प्रतिबिंबित करती है। सरकार का जोर उत्पादन बढ़ाने पर होता है। वह चाहती है कि ज्यादा निवेश हो और उत्पादन बढ़े। कई कंपनियों ने लगभग 14 व्यावसायिक क्षेत्रों में उपलब्ध इस योजना में भागीदारी के लिए आवेदन किया है, इसके तहत महज लक्ष्य पूरा करने वालों को पुरस्कृत या प्रोत्साहित किया जाता है।

यहां यह जरूरी है कि रोजगार देने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाए। लोगों की भर्ती करने वाली कंपनियों के लिए भुगतान दो बुनियादी तरीकों से डिजाइन किया जा सकता है। सबसे पहले, यह सब्सिडी के रूप में दिया जा सकता है, जिसमें वृद्धिशील टर्नओवर के 4-6 प्रतिशत की समान राशि दी जाए, बशर्ते कंपनी पिछले तीन वर्षों में अपने कर्मचारियों की संख्या में शुद्ध रूप से पांच प्रतिशत की वृद्धि करे। इतने कर्मचारियों को तो नियुक्ति मिलनी ही चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में आठ प्रतिशत की वृद्धि होने पर कॉरपोरेट कर्मचारियों की संख्या में सात-आठ प्रतिशत की वृद्धि होती है। आने वाले वर्षों में छह-सात प्रतिशत या जीडीपी में उससे अधिक की वृद्धि मानते हुए भी पांच प्रतिशत नौकरी बढ़ाना बहुत ज्यादा नहीं है। यहां प्रोत्साहन के रूप में देय राशि को कंपनी के प्रति कर्मचारी टर्नओवर से भी जोड़ा जा सकता है। इसलिए, जब उत्पादन बढ़ता है, तो नियोक्ता को लाभ के साथ ही रोजगार की गति भी बनाए रखनी चाहिए।

एक अन्य विकल्प, पांच प्रतिशत की कर कटौती भी हो सकती है, बशर्ते उससे समान लक्ष्य पूरा हो। गौरतलब है, 2019 में सरकार ने कम टैक्स दरों का विकल्प दिया था। हालांकि, इससे निवेश में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई, जितनी उम्मीद की जा रही थी। आज रोजगार से जुड़ी कर रियायतें एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा कर सकती हैं। आज देश में रोजगार बढ़ाने की बहुत जरूरत है।

रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना समयबद्ध इंटर्नशिप कार्यक्रम चलाने या नियोक्ताओं की ओर से भविष्य निधि भुगतान की तुलना में अधिक प्रभावी साबित हो सकती है, जैसा इस साल केंद्रीय बजट में घोषणा हुई थी। रोजगार देने के लिए कंपनियों को आगे आना चाहिए। लाभ और निवेश के साथ रोजगार देना भी कंपनियों की प्रतिबद्धताओं में शामिल है। सरकारों को भी चाहिए कि ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनियों का ज्यादा ध्यान रखें।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

शरीर रूपी रथ का सारथी

हमारा मन कभी निराश हो जाता है, कभी खुशियों से भर जाता है और बड़े से बड़ा काम करना ठान लेता है। आपने कभी सोचा है कि आखिर इस मन को कौन चला रहा है?

मानव शरीर एक रथ की तरह है, जिसमें आत्मा यात्री है। जैसे अन्य वाहनों के यात्री को कोई काम नहीं करना पड़ता, उसी तरह आत्मा भी सिर्फ एक साक्षी के रूप में कार्य करती है। शरीर रूपी रथ को चलाने वाला सारथी बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ यहां विवेक से है, जो शरीर और मन को सही दिशा दिखाता है। बुद्धि ही यह निश्चित करती है कि रथ (शरीर) किस दिशा में जाए। मानव जीवन में मन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे रथ को सही दिशा में रखने के लिए सारथी को लगाम लगाने की जरूरत पड़ती है, वैसे ही मन को नियंत्रण में रखना आवश्यक होता है।

याद रखिए, जब भी कोई जीव किसी वस्तु से संपर्क करता है, तो वह उस वस्तु के रूप, ध्वनि और अन्य संकेतों का अनुभव करता है। जैसे, आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक किसी व्यक्ति से टकरा जाते हैं। आपने उस व्यक्ति की उपस्थिति का अनुभव कैसे किया? उसके रूप की प्रकाश तरंगें आपकी आंखों की रेटिना पर पड़ीं, उसके मुंह से निकली ध्वनि तरंगें आपके कान के पर्दे से टकराईं और कदमों की आवाज आपके कान तक पहुंची। लेकिन कभी-कभी आप किसी व्यक्ति के पास से गुजरते हुए उसकी उपस्थिति या आवाज को नहीं सुनते। इसका कारण यह होता है कि उस समय आपका मन किसी अन्य चीज में व्यस्त होता है और आपकी बुद्धि उस व्यक्ति की उपस्थिति या आवाज पर ध्यान नहीं देती। यानी आपकी इंद्रियां भले ही उस व्यक्ति को महसूस करती हों, लेकिन आपका जागृत मन उन पर ध्यान नहीं दे पाता। इससे क्या पता चलता है? यही कि आत्मा केवल उसी वस्तु से जुड़ती है, जिस पर बुद्धि उसे ले जाती है। अगर मन भटका हुआ है, तो हम किसी चीज को सही से अनुभव नहीं कर पाते।

हमारी इंद्रियां शरीर रूपी रथ के घोड़े का काम करती हैं। इन घोड़ों की सहज प्रवृत्ति है कि वे हमेशा बाहरी वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं। और जब तक वे किसी वस्तु का अनुभव नहीं कर लेते, तब तक शांत नहीं होते। जैसे ही उन्हें कोई सुखद अनुभव होता है, वे कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। मगर यह शांति स्थायी नहीं होती। इसीलिए वे कुछ ही पलों में किसी अन्य वस्तु की ओर दौड़ पड़ते हैं। इसी दौड़ को रोकने के लिए मन और बुद्धि का सही नियंत्रण जरूरी है। किसी उच्च लक्ष्य को पाने के लिए हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में नहीं आता।

शरीर रूपी रथ का सारथी बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ यहां विवेक से है, जो शरीर और मन को सही दिशा दिखाता है। बुद्धि ही यह निश्चित करती है कि रथ (शरीर) किस दिशा में जाए।

श्री श्री आनंदमूर्ति

अमित शाह | केंद्रीय गृह मंत्री

देश की आजादी के लिए हंसते-हंसते फांसी के फंदे को गले लगाने वाले खुदीराम बोस ने अपने जीवन से यह बताया कि देश सेवा की कोई आयु नहीं होती और राष्ट्र के लिए समर्पण की कोई सीमा नहीं होती।

ट्रंप अपने देश का हित सोच रहे तो क्या गलत

अमेरिका के नए निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में यह कहा है कि ब्रिक्स के देश यदि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की जगह किसी अन्य मुद्रा को अपनाएंगे, तो उनको सौ फीसदी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि इस बात की कोई संभावना नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ब्रिक्स डॉलर की जगह ले पाए और ऐसा करने वाले किसी भी देश को अमेरिका को अलविदा कह देना चाहिए।

ट्रंप ने कोई नई बात नहीं कही है। वह हमेशा से कहते आए हैं, 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन'। यह स्वाभाविक है कि कोई भी देश अपनी मुद्रा को कमजोर नहीं होने देगा। फिर जिस तेजी से चीन अमेरिकी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने की कोशिशें कर रहा है, उसे देखते हुए ट्रंप का चौकन्ना होना स्वाभाविक ही है।

दरअसल, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर ने एक तरह से वैश्विक मुद्रा की मान्यता हासिल कर ली है। दुनिया भर के देशों के केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार में अकेले डॉलर की मात्रा करीब 65 प्रतिशत रहती है। ऐसे में, ब्रिक्स जैसे संगठन यदि डॉलर को त्यागते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। विगत दशक में एक राजनीतिक महाशक्ति के रूप में अमेरिका की हैसियत काफी कमजोर पड़ी है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी, यूक्रेन-रूस युद्ध, इजरायल-हमास जंग, यूरोप और अमेरिका में बढ़ते मतभेद, म्यांमार में सैनिक शासन का लौटना, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जो बताते हैं कि दुनिया के छोटे-छोटे मुल्क भी अब वाशिंगटन से 'डिक्टेशन' लेने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में, यदि उसकी अर्थव्यवस्था भी पिछड़ गई, तो फिर बीजिंग को उसे पटकने में कितने साल लगेंगे?

हरेक देश अपने हितों के हिसाब से ही समझौते करता है। संयुक्त राष्ट्र को गठित हुए कितने दशक बीत गए और कब से दुनिया भर के देश यह मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाए; इसे अधिक लोकतांत्रिक बनाया जाए। मगर पांचों देश अपने इस विशेषाधिकार को बांटना नहीं चाहते। ऐसे में, अमेरिका से यह अपेक्षा करना कि वह अपने आर्थिक हितों की कीमत पर अन्य देशों को फलने-फूलने देगा, भोलेपन के सिवा और कुछ भी नहीं। फिर ट्रंप खुद एक बड़े कारोबारी हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि सौदेबाजी में सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा अनुकूल बनाने के लिए किस तरह से दांव चले जाते हैं। इसलिए वह कोई अनैतिक काम नहीं कर रहे।

अनिरुद्ध शर्मा, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

ट्रंप के तेवर

फिर उनकी सनक का शिकार बनेगी दुनिया

डोनाल्ड ट्रंप एक आत्मकेंद्रित राजनेता हैं और ऐसे नेता दूसरे के बारे में रत्ती भर भी नहीं सोचते। उनके सत्ता संभालने में अभी करीब डेढ़ महीने हैं, मगर उन्होंने ब्रिक्स के देशों को एक तरह से धमकी दी है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वे डॉलर से अलग गए, तो फिर खामियाजा भुगतने को भी तैयार रहें। लेकिन ऐसा करते हुए ट्रंप भूल गए कि यदि उन्हें अमेरिकी इकोनॉमी की फिक्र है, तो ब्रिक्स के देशों को भी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए हितकारी रास्ते तलाशने का पूरा-पूरा अधिकार है। ट्रंप प्रशासन ने पिछले कार्यकाल में जैसे उल्टपटांग फैसले किए, उसका खामियाजा इंसानियत और तमाम देशों को आज तक भुगतना पड़ रहा है।

ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में जिस हड़बड़ी में अफगानिस्तान को तालिबान के हाथों में सौंप दिया, उससे अफगानियों की सारी कुर्बानी और दो दशकों की तरक्की बेमानी हो गई। वहां के करोड़ों नागरिकों की आशाओं पर तुषारापात हो गया, दुनिया के कई देशों के अरबों डॉलर के निवेश डूब गए। इस वाकये से एक बार फिर संसार भर के शांतिकामी लोगों और देशों को यही पैगाम गया कि अमेरिका कतई भरोसे के काबिल नहीं है और उसके बूते कोई जंग फतह नहीं की जा सकती। इसी तरह, राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के मुद्दे का खुलकर उपहास उड़ाया और वह अंतरराष्ट्रीय संधि से निकल गए। लिहाजा, यह कवायद शिथिल पड़ गई और दुनिया भर में यह संकट और गंभीर होता चला गया। बराक ओबामा के कार्यकाल में ईरान परमाणु संधि पर यूरोप-अमेरिका के साथ निगरानी समझौते के लिए सहमत हो गया था, मगर ट्रंप प्रशासन ने उस करारनामे से भी किनारा कर लिया। अगर वह समझौता हो गया होता, तो शायद ईरान के सामाजिक जीवन में भी मध्य एशिया के देशों की तरह बदलाव की बयार बह पाती और कट्टरपंथ की पकड़ थोड़ी ढीली होती। कोरोना महामारी के दौरान भी ट्रंप प्रशासन का रवैया बेहद गैर-जिम्मेदारी भरा रहा। उन्होंने उस वक्त दुनिया के कई देशों को आंखें दिखाकर जिस तरह से दवाएं अपने नागरिकों के लिए बटोरी थीं, उसे आज तक लोग भूले नहीं हैं।

इसलिए अंदेशा यही है कि एक बार फिर दुनिया डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में अमेरिकी सनक का शिकार बनने जा रही है। डॉलर के मुद्दे पर संसार की सबसे तेजी से उभरती व बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को ट्रंप ने जो सख्त संदेश दिया है, वह इसकी एक बानगी है। उनसे किसी अच्छे की उम्मीद बांधना वास्तव में अपने को धोखे में रखना ही है।

मोहम्मद अनीस, टिप्पणीकार

चिंतन

कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें सरकारें

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार व उत्पीड़न काफी पीड़ादायक है। आज भी हमारे सरकारी व निजी दफ्तर महिला फ्रेंडली नहीं बन सके हैं। सरकार की कई गाइडलाइन्स, अदालतों की हिदायत और कानूनी कवच के बावजूद कार्यस्थल महिलाओं के लिए मुफीद नहीं हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो देश में सालाना हजारों मामले होते हैं, इनमें से सैकड़ों ही प्रकाश में आते हैं और कुछेक सौ की ही रिपोर्ट दर्ज होती हैं। लेकिन हर वर्ष पिछले वर्ष से अधिक मामले दर्ज होते हैं, यह बानगी है कि देश में सरकारी व निजी कार्यस्थल महिलाओं के लिए पूर्णतया सेफ नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का देशव्यापी अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी सरकारी विभागों एवं उपक्रमों में आंतरिक शिकायत समिति गठित करने का निर्देश दिया है। चूंकि, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम को पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसलिए शीर्ष अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 दिसंबर, 2024 तक प्रत्येक जिले में एक अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया, जो 31 जनवरी, 2025 तक एक स्थानीय शिकायत समिति का गठन करेगा और तालुका स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने उपायुक्तों/जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि वे अधिनियम की धारा 26 के तहत आंतरिक शिकायत समिति अनुपालन के लिए सार्वजनिक और निजी संगठनों का सर्वेक्षण करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए, वर्ष 2013 में 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम' लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत, यौन उत्पीड़न की शिकायत करने के लिए, पीड़ित महिला या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति आंतरिक शिकायत समिति या स्थानीय समिति के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। इस अधिनियम के तहत, कार्यस्थल पर अगर संगठन में दस या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, तो शिकायत आंतरिक शिकायत समिति के पास दर्ज करानी होती है। अगर संगठन में दस से कम कर्मचारी हैं, तो शिकायत जिला अधिकारी द्वारा गठित स्थानीय समिति के पास दर्ज करानी होती है। अगर नियोक्ता आंतरिक शिकायत समिति नहीं बनाता या अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उस पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई संगठन में जाने वाली महिला उस संगठन के किसी कर्मचारी से परेशान होती है, तो वह उस संगठन की आंतरिक समिति के पास शिकायत दर्ज करा सकती है। निजी क्षेत्र में कार्यस्थल पर महिलाएं अधिक शिकार होती हैं, घरेलू महिलाकर्मियों के साथ भी ऐसी घटनाओं की संभावना अधिक रहती है। अमेरिकी ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक, भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कानून के पालन में बहुत सारी खामियां हैं। मीटू कैंपेन ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की भयावहता उजागर की थी। राज्य सरकारों व स्थानीय प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यस्थल महिलाओं के लिए सुरक्षित रहें, उनका यौन उत्पीड़न न हो। कामकाजी महिलाओं को भी अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना चाहिए और हर स्तर पर एहतियात बरतनी चाहिए।

दिवस विशेष

डॉ. एल. एस. यादव

मजबूत हो रही भारतीय नौसेना

भारतीय नौसेना अपनी ताकत बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है जिससे वह आने वाले दिनों में और अधिक ताकतवर हो जाए। नौसेना को इस माह के अंत तक एक नया गाइडेड मिसाइल युद्धपोत प्राप्त हो जाएगा। रूस द्वारा तैयार किए गए दो युद्धपोतों में से आईएनएस तुशील पहला है। रूस-यूक्रेन युद्ध के लम्बा खिंचने के कारण इसकी प्राप्ति में विलम्ब हो गया। इसी युद्ध के चलते एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और परमाणु पनडुब्बी के मिलने में भी देरी होने की संभावना है। आईएनएस तुशील युद्धपोत ब्रह्मोस मिसाइलों सहित अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगा। तुशील के मिलने के बाद अगले वर्ष आईएनएस तमाल गाइडेड मिसाइल युद्धपोत मिल जाएगा।

पाकिस्तान व चीन की रक्षा तैयारियों को देखते हुए भारतीय नौसेना को अत्यन्त आक्रामक बनाया जा रहा है। हिन्द महासागर क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए भारतीय नौसेना का मुख्य फोकस रणनीतिक रूप से चीन की बढ़ती मौजूदगी का मुकाबला करने के लिए है। इसलिए भारतीय नौसेना अपनी ताकत बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है जिससे वह आने वाले दिनों में और अधिक ताकतवर हो जाए। समुद्र में भारत की ताकत बढ़ाने के लिए नौसेना को इस माह के अंत तक एक नया गाइडेड मिसाइल युद्धपोत प्राप्त हो जाएगा। रूस द्वारा तैयार किए गए दो युद्धपोतों में से आईएनएस तुशील पहला है। रूस-यूक्रेन युद्ध के लम्बा खिंचने के कारण इसकी प्राप्ति में विलम्ब हो गया।

इसी युद्ध के चलते एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और परमाणु पनडुब्बी के मिलने में भी देरी होने की संभावना है। आईएनएस तुशील युद्धपोत ब्रह्मोस मिसाइलों सहित अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगा। तुशील के मिलने के बाद अगले वर्ष आईएनएस तमल गाइडेड मिसाइल युद्धपोत मिल जाएगा। इन दोनों पोतों के मिलने से भारतीय नौसेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी। उल्लेखनीय है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग सैन्य तकनीकी सहयोग की बैठक के लिए इसी माह रूस का दौरा करने वाले हैं। इन गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित अत्याधुनिक घातक हथियार तथा सैन्य अभियानों को अंजाम देने के लिए सेंसर लगाए गए हैं। तुशील गाइडेड मिसाइल युद्धपोत इलेक्ट्रॉनिक युद्धकला से सुसज्जित है। इसमें एंटी सबमरीन रॉकेट और तारपीडो लगाए गए हैं। इसकी लम्बाई लगभग 129 मीटर है। इसकी स्पीड 30 नॉटिकल मील प्रति घण्टा है। तुशील का वजन 3600 टन से ज्यादा है। इसमें 180 नौसैनिक यात्रा कर सकते हैं। भारत और रूस के बीच वर्ष 2016 में चार तलवार क्लास के स्टील्थ फ्रिगेट बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इसमें से दो रूस में और दो भारत में बनाए जाने थे। भारत में बनने वाला विशाखपट्टनम क्लास का चौथा गाइडेड मिसाइल युद्धपोत शीघ्र ही मिलने की उम्मीद है। यह 7400 टन वजन वाला है। इसमें लगी ब्रह्मोस मिसाइलें लम्बी दूरी तक मार करने में सक्षम हैं। इसी वर्ष नीलगिरि फ्रिगेट भी नौसेना को मिलने वाला है। इसका वजन 6670 टन है और इसमें आठ ब्रह्मोस मिसाइलें लगी हैं। विदित हो कि भारतीय नौसेना वर्श 2003 तलवार क्लास के जंगी जहाज षामिल हो रहे हैं। वर्तमान में इस श्रेणी के छह स्टील्थ फ्रिगेट्स नौसेना के बेड़े का हिस्सा हैं। इनमें से चार को ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस कर दिया गया है और दो पर काम चल रहा है। इन युद्धपोतों के नौसेना में शामिल होने से भारत की समुद्री ताकत काफी बढ़ जाएगी।

भारतीय नौसेना ने 27 नवम्बर 2024 के-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नौसेना ने यह परीक्षण परमाणु पनडुब्बी अरिघात से किया। इस पनडुब्बी को 2017 में लॉन्च किया गया था। अब इसका अपग्रेड वर्जन षीघ्र ही कमीशन किया जाना है। परमाणु पनडुब्बी अरिघात आईएनएस अरिहंत का अपग्रेडेड

वर्जन है। इस पनडुब्बी को विशाखापट्टनम में नौसेना के शिपबिल्डिंग सेंटर में निर्मित किया गया था। अब अरिहंत की तुलना में 6000 टन वजन वाली अरिघात के नये वर्जन को के-4 मिसाइलों से लैस किया जाएगा। इस परीक्षण में के-4 मिसाइल अपने सभी तय मानकों पर खरी उतरी। पनडुब्बी से इस मिसाइल का यह पहला परीक्षण था। वर्ष 2010 में इसका सबसे पहले परीक्षण किया गया था। तबसे अब तक इसके कई परीक्षण किए जा चुके हैं। यह मिसाइल 10 मीटर लम्बी और 20 टन वजन वाली है। यह एक टन वजन का पेलोड ले जाने में सक्षम है।के-4 मिसाइलों की मारक दूरी 3500 किलोमीटर तक है। इसलिए बंगाल की खाड़ी में जब इन मिसाइलों को तैनात किया जाएगा तो ये मिसाइलें चीन के मेनलैंड तथा दक्षिण व पश्चिमी इलाके तक के क्षेत्र को अपने निषाने पर ले लेंगी। यही नहीं अपनी मारक क्षमता के तहत ये चीन राजधानी बीजिंग को भी निशाने पर ले सकती हैं। अरिघात 50 दिन से ज्यादा पानी के अंदर रह सकती है। इसलिए, यह चीन के जासूसी जहाजों की नजरों से बचकर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सकती है। अगर पाकिस्तान से मुकाबले की बात आती है तो अरिघात में तैनात होने पर ये इस्लामाबाद को भी नेस्तनाबूद कर सकती हैं। इन मिसाइलों से नौसेना की विध्वंसक क्षमता काफी बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि भारत के पास पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइलों में कम दूरी की मारक क्षमता वाली के-15 मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें 750 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम हैं। पनडुब्बी आईएनएस अरिहन्त में ये मिसाइलें तैनात हैं। इसके अलावा भारत के पास भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द इंटर कॉन्टिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल के-5 पर काम कर रहा है। उम्मीद है कि इसकी मारक दूरी 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। इन सभी की तुलना में के-4 मिसाइलें ज्यादा सटीक, बेहतर एवं आसानी से ऑपरेट होती हैं। भारत की नीति यह है कि वह पहले किसी पर परमाणु हमला नहीं करेगा लेकिन यदि उस पर हमला हुआ तो वह उसे छोड़ेगा नहीं। ऐसी स्थिति में ये मिसाइलें काफी कारगर सिद्ध होंगी। नवम्बर 2024 में ही गोला बारूद नौका एलएसएएम-12 यार्ड 80 नौसेना को प्राप्त हुई है। उल्लेखनीय है कि ऐसी कुल आठ नौकाओं के निर्माण के लिए विशाखापट्टनम की मैसर्स सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया समझौता इस साल 19 फरवरी 2024 को पूरा हो गया था। इन नौकाओं के नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल होने से उसकी परिचालन क्षमता में काफी वृद्धि हो जाएगी। इन नौकाओ को स्वदेशी रूप से डिजाइन करने के लिए भारतीय जहाज इंजीनियरिंग फर्म से सहयोग लिया गया। इसके अलावा नौसेना की विशाखापट्टनम की विज्ञान एवं तकनीकी प्रयोगषाला में इनका मॉडल सफलतापूर्वक तैयार किया गया जिससे इसकी समुद्री योग्यता का आकलन किया जा सके।

इनका निर्माण भारतीय नौवहन रजिस्टर के निश्चित नियमों के तहत किया गया है। नौसेना के लिए निर्मित किया गया पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत अपनी पूर्ण परिचालन क्षमता को हासिल कर चुका है। अब यह युद्ध मोड में तैनात होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नौसेना इसे कहीं भी तैनात कर सकती है। इस पोत पर तैनात होने वाले 30 विमान बेड़े में 18 मिग-29 तथा 12 कामोव हेलीकॉप्टर होंगे। अमेरिका से खरीदे गए एमएच-60 रोमियो हेलीकॉप्टर शक्तिशाली पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं के साथ इस पोत पर तैनात रहेंगे। इन सभी के मिलने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी।

(लेखक सैन्य विज्ञान के प्राध्यापक रहे हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

पड़ोस

आर.के. सिन्हा

पाक में क्यों बह रहा शिया मुसलमानों का खून

मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस इस्लामिक देश पाकिस्तान को बनवाया था, वहां मुसलमान ही अब मुसलमानों की जान के दुश्मन हो गये हैं। वहां सुन्नी और शिया समुदायों के बीच हुए हालिया संघर्ष में 130 से ज्यादा लोगों का खून बहा। हिंसा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अफगानिस्तान की सीमा से लगे कुर्रम जिले में हुई। सुन्नी बहुल पाकिस्तान में 24 करोड़ की आबादी में शिया मुस्लिम लगभग 15 प्रतिशत ही हैं। पाकिस्तान में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच का हालिया संघर्ष जटिल है, जिसकी जड़ें सदियों पुरानी धार्मिक और राजनीतिक विभाजन के इतिहास पर टिकी हैं। वैसे तो कुछ कट्टरपंथी समूह दोनों पक्षों में ही मौजूद हैं जो हिंसा का इस्तेमाल करके ही अपने धार्मिक विचारों को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। ये समूह साम्प्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा देते हैं और हिंसा को सही ठहराते हैं। पाकिस्तान में सुन्नी समुदाय कतई शिया मुसलमानों को पसंद नहीं करते। इससे साफ है कि इस्लाम अपने मानने वालों को भी नहीं जोड़ता। हालांकि बातें बहुत होती हैं कि सारी दुनिया के मुसलमान एक हैं। लेकिन, ये अपनी इस बात को तो स्वयं ही बार-बार गलत साबित करते रहते हैं। पाकिस्तान में शिया मस्जिदों में धमाके और विस्फोट होना भी आम बात हो चुकी है। पेशावर में मई, 2022 में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान हुए दिल दहलाने वाले आत्मघाती बम विस्फोट में लगभग 60 से अधिक शिया नमाजी मारे गए थे।। हमलावरों ने निशाना बनाया था शिया मुसलमानों और उनकी इबादतगाह को। यह भी याद रखा जाए कि एक इस्लामिक मुल्क में ही शिया मुसलमानों का जीना मुश्किल हो गया है।

वे हर वक्त डर-भय के साए में जीने को मजबूर बने रहते हैं। यह हाल उस पाकिस्तान का है जो मुसलमानों के वतन के रूप में बना था। पेशावर की शिया मस्जिद में हमला कोई अपने आप में पहली बार नहीं हुआ था। वहां पर शिया मुसलमानों पर लगातार जुल्मों-सितम होते रहे हैं। पाकिस्तान में लगातार प्रतिबंधित संगठन शियाओं के ख़िलाफ़ खुलेआम प्रदर्शन भी करते हैं। इस तरह के ज्यादातर प्रदर्शन लाहौर, क्वेटा, पेशावर वगैरह शहरों में देखने को मिलते हैं। वहां पर शिया मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने वाला साहित्य भी हर जगह आसानी से वहाँ पर आम लोगों को आसानी से उपलब्ध है। तालिबान और इसी तरह के अन्य अतिवादी समूहों के विचारों का प्रभाव पाकिस्तान में है, जो साम्प्रदायिक संघर्षों को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। यह समूह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए शिया-सुन्नी संघर्ष का उपयोग आम तौर पर करते हैं। पाकिस्तान में कुछ सियासी नेता साम्प्रदायिक तनाव को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे मतदाताओं को लुभाने के लिए और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को कमजोर करने के लिए साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काते हैं। बेशक, पाकिस्तान सरकार की सुन्नी परस्त नीति के कारण साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने में नाकामी, या यहां तक कि कुछ मामलों में इसमें सहयोग करने से, इस समस्या को और बढ़ावा मिलता है। पाकिस्तान में कुछ सुन्नी जिन्ना को भी शिया बताते हैं। कौन जाने कि एक बार जिन्ना शिया साबित कर दिए गए तो उनकी विरासत को भी बिना कुछ जाने-समझे ही पाकिस्तान में धूल में मिला दिया जाएगा। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों, विशेषकर शिया मुसलमानों, हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों के साथ भेदभाव के कई जटिल कारण हैं, जिनमें धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक उद्देश्य और कई सामाजिक-आर्थिक कारक शामिल हैं। कोई एकल कारण नहीं है, बल्कि ये कारक आपस में जुड़े हुए हैं।

पाकिस्तान में कुछ अतिवादी आतंकी धार्मिक समूहों का प्रभाव काफी है, जो सुन्नी इस्लाम के एक विशेष व्याख्या का प्रचार करते हैं जो अन्य धर्मों और शिया इस्लाम के प्रति असहिष्णुता को बढ़ावा देता है। कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं ने अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को अक्सर सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित किया जाता है। उन्हें अच्छी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच होती है, जिससे वे और भी हाशिए पर आते ही चले जाते हैं। पाकिस्तान में हिन्दुओं के साथ कभी न्याय नहीं हुआ। इसी का नतीजा था कि जिन्ना का करीबी एक दलित हिन्दू मंत्री तक पाकिस्तान में नहीं रह सका। कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान में अभी तो सिर्फ सुन्नी ही सुरक्षित हैं। आगे क्या होगा शायद खुदा को खुद भी पता न हो। आगे - आगे देखिये होता है क्या?

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

संकर सहज स्वरूप सम्हारा

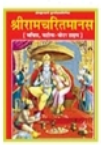

संकलित

दर्शन

श्रीरामचरितमानस में भगवान शंकर भक्ति के दाता भी माने गए हैं और भक्ति के भिक्षुक भी। शिव भक्ति देते भी हैं और मांगते भी हैं। भगवान शंकर में नवभक्ति का दर्शन होता है। उनमें अष्टांग योग का, ज्ञान की सातों भूमिकाओं का और धर्म के दसों लक्षणों का दर्शन भी होता है। लंका कांड में गोस्वामी जी ने जो धर्मरथ का वर्णन किया है। उसमें जितने धर्म के सूत्र बताए हैं, वे सभी महादेव में प्रस्थापित होते हैं। शिव भक्ति स्वरूप हैं। शिव का बाहरी रूप तो 'कुंडल कंकन पहिरे ब्याला' वाला है, लेकिन आंतरिक स्वरूप भजन है, भक्ति है। मानस में है- 'संकर सहज स्वरूप सम्हारा'। सहज स्वरूप का अनुसंधान शिव ने किया। उनकी जो सहज प्रवृत्ति है, वह भजन है। भगवान भी कहते हैं कि 'संकर भजन बिना नर भगति न पावइ मोरि'। शंकर की भक्ति जो करेगा, वही मेरी भक्ति पाएगा अथवा शंकर का जो सहज भजन स्वरूप है, उसे आत्मसात करेगा, वह मेरी भक्ति पाएगा। शबरी के सामने गाई गई नौ प्रकार की भक्ति में गोस्वामी जी ने पहली भक्ति संत का संग बताई है- 'प्रथम भगति संतन्ह कर संगा'। आप महेश का चरित्र देखिए। जैसे ही अवसर मिला, वे साधु-संतों का संग करते दिखाई देते हैं। पार्वती के विरह में संतों का संग करते थे। महादेव सत्संग के प्यासे हैं। दूसरी भक्ति है कथा श्रवण। कथा में जहां जगह मिले, वहां बैठकर कथा के प्रसंगों का रस उठाना। शिव कहते हैं, पार्वती, मैं काकभुशुंडि जी के आश्रम में हंस बनकर पीछे बैठ गया था। कथा श्रवण में इतनी रुचि, यह दूसरी भक्ति शिव में है।

सुख-सुविधाओं से ज्यादा संस्कार देने पर दें ध्यान

संकलित

प्रेरणा

महाभारत में दो खास परिवार हैं, पहला पांडव और दूसरा है कौरव। पांडव परिवार में कुंती और पांच पुत्र थे। जबकि कौरव परिवार में धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ ही सौ पुत्र थे। पांडवों के पास सुख-सुविधाओं का अभाव था, जबकि कौरवों के पास सारी सुख-सुविधाएं थीं। महाभारत में कुंती अपने पांच पुत्रों के साथ वन में रह रही थीं, क्योंकि धृतराष्ट्र और दुर्योधन नहीं चाहते थे कि पांडु के पुत्रों को राज्य मिले। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अधर्मी था। वह बचपन से ही पांडव पुत्रों को परेशान कर रहा था। कुंती के पति पांडु शाप की वजह से मर चुके थे। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री भी जीवित नहीं थी। इन दोनों के बाद कुंती को पांच पुत्रों का पालन करना था। तीन पुत्र कुंती के थे और दो पुत्र माद्री के थे। कुंती जानती थीं कि जंगल में तो कोई सुख-सुविधा तो मिलेगी नहीं, इसलिए कुंती ने बच्चों का पालन करते समय संस्कारों पर ज्यादा ध्यान दिया। दूसरी ओर कौरव पक्ष में धृतराष्ट्र अंधे थे, गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। दुर्योधन और उसके भाई लगातार गलत काम कर रहे थे, लेकिन माता-पिता ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि सभी कौरव पुत्र अधर्मी हो गए। महाभारत युद्ध में जब श्रीकृष्ण को ये निर्णय लेना था कि किसके पक्ष में रहेंगे, तब उन्होंने धर्म मार्ग पर चल रहे पांडव पुत्रों को चुना। धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपने पुत्रों को सुख-सुविधा की हर एक चीज दी थी, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं दिए थे। संतान के मोह में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को सही-गलत का फर्क नहीं बताया।

अंतर्मन

आज की पाती

दिव्यांगों का दर्द

तीन दिसंबर को हर वर्ष विश्व दिव्यांग (विकलांग) दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों का सशक्तिकरण और इनके लिए समान अधिकार और विकास संभावनाओं की सुनिश्चितता करना भी है। हमारे देश मे दिव्यांगों की संख्या काफी है। अगर हम वर्ष 2011 की जनसंख्या के आंकड़े देखे तो इसमें बताया गया है कि उस समय इनकी संख्या लगभग 2.68 करोड़ थी जो देश की जनसंख्या का लगभग 2 से ऊपर का प्रतिशत था।जैसे-जैसे जनसंख्या मे वृद्धि हुई है, वैसे-वैसे यह आंकड़ा भी बढ़ा होगा। दिव्यांगों के प्रति हर नागरिक की सहानुभूति होनी चाहिए। सरकार को भी उनके कल्याण के लिए नई योजनाएं लेकर आगे आना चाहिए।

- संदीप पाठक, महासमुंद

करंट अफेयर

चीन का अंटार्कटिका में वायुमंडलीय स्टेशन

चीन ने अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन स्थापित किया है। चीन इस बर्फीले और संसाधन-संपन्न दक्षिणी महाद्वीप में इस अनुसंधान स्टेशन का निर्माण कर वहां अपनी मौजूदगी को मजबूत कर रहा है। चीन मौसम विज्ञान प्रशासन (सीएमए) के अनुसार, पूर्वी अंटार्कटिका के 'लार्समैन हिल्स' में स्थित झोंगशान नेशनल ऐटमॉसफेरिक बैकग्राउंड एडमिनिसट्रेश (सीएमए) में रविवार से कामकाज शुरू हो गया है। सीएमए वेबसाइट पर सोमवार को प्रकाशित एक लेख में कहा गया है, 'यह स्टेशन अंटार्कटिका के वायुमंडलीय घटकों में सांद्रता परिवर्तनों के बारे में निरंतर और दीर्घकालिक परिचालनात्मक अवलोकन करेगा तथा क्षेत्र में वायुमंडलीय संरचना तथा संबंधित विशेषताओं की औसत स्थिति का विश्वसनीय प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा।' हांगकांग स्थित 'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' की खबर के अनुसार, लेख में कहा गया है कि निगरानी डेटा 'जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करेगा'। यह चीन का नौवां वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन और विदेश में इसका पहला स्टेशन है। इसके अलावा, चीन में वर्तमान में 10 नए वायुमंडलीय निगरानी स्टेशनों का परीक्षण किया जा रहा है।

ऑफ बीट

डाउन सिंड्रोम में बुढ़ापे के लिए डीएनए जिम्मेदार

डाउन सिंड्रोम से पीड़ित मरीजों में समय से पहले बुढ़ापे के लिए क्रोमोजोम-21 में मौजूद एक अतिसक्रिय जीन जिम्मेदार हो सकता है, जो डीएनए की मरम्मत की प्रक्रिया को बाधित करता है और ढलती उम्र से जुड़े लक्षणों को गति देता है। ब्रिटेन स्थित क्वीन मैरी विश्वविद्यालय के नेतृत्व में हुए एक नये अनुसंधान में यह दावा किया गया है। अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक, शरीर में रासायनिक क्रियाओं में तेजी लाने वाले एंजाइम पर 'डीवाईआरके1ए' नामक जीन की अतिसक्रियता डीएनए की मरम्मत करने वाले तंत्र को प्रभावित करती है। इससे कोशिकाओं में मौजूद डीएनए को ज्यादा नुकसान पहुंचता है और उनके अधिक संवेदनशील हो जाने से बुढ़ापे की प्रक्रिया तेज हो जाती है। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार, डाउन सिंड्रोम क्रोमोजोम-21 की एक अतिरिक्त प्रति या ट्राइसोमी-21 की मौजूदगी के कारण होता है। इस क्रोमोजोम के साथ जन्मे व्यस्कों में बुढ़ापे की जैविक प्रक्रिया से जुड़े लक्षण, मसलन-ऊतक पुनर्जनन क्षमता में कमी, जख्म भरने में देरी, ऑस्टियोपोरोसिस, मस्तिष्क की कोशिकाओं में क्षरण और प्रतिरक्षा कोशिकाओं का कमजोर पड़ना आदि जल्दी उभरने लगते हैं।

ट्रेंड

प्रथम राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि

देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी को उनकी जन्म-जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भारतीय लोकतंत्र की सशक्त नींव रखने में उन्होंने अमूल्य योगदान दिया।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

द साबरमती रिपोर्ट

'द साबरमती रिपोर्ट' फिल्म ने देशवासियों को गोधरा के सच से परिचित कराया। इस फिल्म के माध्यम से लोगों को पता चल रहा है कि कैसे एक इकोसिस्टम ने इतने बड़े सच को सालों तक देश से छिपा कर रखा। -अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

अल्पसंख्यकों पर हिंसा

पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद वहां नई सरकार में खासकर हिन्दू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा व जुल्म-ज्यादती आदि तथा उससे वहां बिगड़ते हालात अति-दुखद व चिन्ताजनक।

-मायावती, पूर्व सीएम, उप्र

हार्दिक शुभकामनाएं

संत फ्रांसिस जेवियर के पर्व के शुभ अवसर पर गोवा के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। संरक्षक संत की स्थायी विरासत हमें शांति, सद्भाव और भाईचारे के मार्ग पर मार्गदर्शन करती रहेगी।

-राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। बुधवार, 4 दिसंबर 2024

बुरे फंसे बाइडन

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने बेटे हंटर बाइडन को आपराधिक मामलों में माफी देकर अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों को विवादास्पद बना दिया है। विशेष परिस्थितियों में किसी दोषी को माफी देना राष्ट्राध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है, लेकिन यहां जिस तरह से उसका इस्तेमाल किया गया, उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। यह मामला सीधे-सीधे परिवारवाद का है और अगर राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठी शख्सियत इस तरह के फैसले लेगी, तो उससे जनता के विश्वास को चोट ही पहुंचेगी।

सवालों में फैसला | बाइडन के पूरे कार्यकाल में उनके बेटे हंटर भी चर्चा में रहे। उन पर दो गंभीर संघीय अपराध साबित हुए थे। एक, बंदूक खरीदने के दौरान ड्रग्स इस्तेमाल करने से जुड़ी गलत जानकारी देना और दूसरा केस टैक्स चोरी का था। हंटर को इसी महीने के आखिर में दोनों केस में सजाएं होनी थीं, लेकिन अपने पिता की 'दया' से अब उन पर कोई आरोप नहीं है। इसने डॉनल्ड ट्रंप को पूछने का मौका दे दिया है कि जनवरी 2021 में हुए दंगे में शामिल लोगों को भी क्या माफी दी जाएगी? कोई हैरत नहीं, अगर अगले महीने पद संभालने जा रहे ट्रंप अपने समर्थकों को नए साल के तोहफे में माफी दे दें।

बेटे को आपराधिक मामलों में माफी दी

बेजा दखल | बाइडन इसलिए भी घिर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपराधिक मामलों में विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया। आमतौर पर इस तरह के निर्णय मानवीयता के आधार पर लिए जाते हैं या फिर उन जगहों पर, जहां मामले राजनीतिक प्रकृति के हों। वैसे, अपनों को राहत देने वाले बाइडन अकेले अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में दामाद को और बिल क्लिंटन ने चचेरे भाई को माफी दी थी। हालांकि दोनों केस में सजा हो चुकी थी, जबकि यहां राष्ट्रपति ने पहले ही क्षमा दे दी, जिसे न्याय व्यवस्था में दखल कहा जाएगा।

पुराने विवाद | भारत में भी राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास सजा को कम करने या माफ करने का अधिकार है। मंशा जो भी रही हो, लेकिन इस तरह के कदम कई बार विवाद भी पैदा कर देते हैं। 2013 में यूपी सरकार ने सीरियल ब्लास्ट के संदिग्धों पर से इस आधार पर केस वापस लेने का फैसला लिया था कि आरोप राजनीति से प्रेरित थे। हालांकि तब हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा था।

आखिरी हथियार | स्टेट हेड को क्षमा का अधिकार इसलिए दिया गया है, ताकि न्याय प्रणाली में मानवीयता बनी रहे। यह आखिरी हथियार की तरह है, जिसका इस्तेमाल तभी किया जाता है, जब यह लग रहा हो कि किसी को न्याय नहीं मिल सका और उसे सजा देने में गलती हुई है। क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन यह भी मायने रखता है कि इसका पात्र कौन है और जिसे दूसरा मौका दिया जा रहा है, क्या वह उसके लायक है।

इन दिनों

यहां सब साथ हैं

मृत्युंजय राय

फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बर्निये के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिससे उनकी सरकार गिर सकती है और ऐसी सूरत में वहां बजट का पास होना भी मुश्किल है।

पिछले साल सितंबर में बर्निये को राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था और यहीं वह गलती हुई, जिससे आज के हालात बने। तब संसदीय चुनाव के नतीजे मैक्रों की पार्टी और उनके सहयोगियों के खिलाफ थे। कहा जा रहा है कि उन्हें उस वक्त वामपंथी अलायंस के नेता को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था, जिसे चुनाव में सबसे अधिक वोट मिले थे। लेकिन उन्होंने पारंपरिक सेंटर राइट के लीडर बर्निये को इस पद के लिए चुना। इससे वामपंथी गठबंधन में जबरदस्त नाराजगी पैदा हुई। इसी वजह से बर्निये के लिए कामकाज करना भी मुश्किल हो गया। इन्हीं हालात में पिछले सोमवार को बर्निये ने वहां की लोकसभा में बिना मतदान के बजट पास करवाने की कोशिश की, जो उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की वजह बना। अजीब बात है कि दक्षिणपंथ और वामपंथ का आम तौर पर किसी भी मुद्दे पर साथ आना मुश्किल होता है, फ्रांस में वामपंथी अलायंस और मरीन ले पेन की धुर-दक्षिणपंथी नैशनल रैली पार्टी, दोनों ने ही बर्निये के खिलाफ यह प्रस्ताव पेश किया है। इस पर बुधवार को वोटिंग हो सकती है और इसके पास होने की पूरी संभावना है। ऐसे में बर्निये के पास इस्तीफा देने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा और फिर कार्यवाहक सरकार वजूद में आएगी, जो नए कानून नहीं बना सकती। अब एक बार फिर से मैक्रों को अपनी पसंद का नया पीएम नियुक्त करना होगा।

बर्निये ने अपने बजट में 60 बिलियन डॉलर की टैक्स बढ़ोतरी और खर्च में कटौती का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब इसका भविष्य अधर में है। अगर मैक्रों जल्द नया प्रधानमंत्री चुन लेते हैं और नई सरकार बन जाती है तो साल खत्म होने से पहले वह बजट पेश कर सकती है। इसकी समीक्षा के लिए संसद के पास 70 दिनों का वक्त होगा। यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो नए बजट के मुताबिक खर्च करने का रास्ता नए साल में ही साफ होगा। अगर संसद उस बजट पर मुहर लगाने से इनकार कर दे तो मैक्रों अपनी खास संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल कर देश पर अपना बजट थोप सकते हैं, लेकिन फ्रांस में पहले ऐसा नहीं हुआ है। फिर बात यह भी है कि जनता इसे लेकर मैक्रों से नाराज है कि चुनावी नतीजों यानी उनकी इच्छा देखते हुए प्रधानमंत्री क्यों नियुक्त नहीं किया गया।

एकदा

नेपोलियन की नज़र

नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी और राजनेता थे। उन्होंने अपने सैन्य कौशल और ताकत के बल पर फ्रांस के राजा को उखाड़ फेंका और प्रथम फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना कर वहां के सम्राट बन गए। वह जितने सैन्य कुशल थे, उतनी ही पारखी नजरें भी थीं उनकी। नेपोलियन अपने प्रशासन में छोटी-से-छोटी बात पर भी बहुत ध्यान देते थे। एक शासक के रूप में वह कभी-कभी कठोर और क्रूर भी हो जाते थे। उन दिनों फ्रांस में सैनिकों की वर्दी उनके पद और रैंक को दर्शाती थी। एक बार नेपोलियन ने एक टेलर को अपने लिए नई वर्दी बनाने की जिम्मेदारी दी। टेलर बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसे नेपोलियन की बारीक नजर के बारे में पता था। उसने वर्दी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर माप को बहुत ही सटीक तरीके से लिया। जब वर्दी पूरी हो गई तो टेलर ने उसे नेपोलियन के सामने पेश किया। नेपोलियन ने वर्दी को बहुत ध्यान से देखा। हर एक हिस्से को बारीकी से जांचा। फिर एक छोटी-सी सिलाई की ओर इशारा करते हुए कहा, 'यहां थोड़ी सी गलती है।' नेपोलियन की बात सुनते ही टेलर चौंक गया, लेकिन उसे समझ में आ गया कि वर्दी में जरूर कोई गलती हुई है। नेपोलियन ने टेलर की घबराहट को भांप लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'एक महान नेता को छोटी-से-छोटी गलती को देखना आना चाहिए, तभी वह बड़ी से बड़ी जीत हासिल कर सकता है।' टेलर ने राहत की सांस ली और उसे समझ में आया कि नेपोलियन कैसे महान और शक्तिशाली शासक बन पाए।

Subrata Dhar

संकलन : रिंकल शर्मा

लंबी अवधि में भारत 8% ग्रोथ की क्षमता रखता है, पर राजनीतिक बाधाओं के कारण 6.5% सही लक्ष्य

सब पॉलिटिक्स का चक्कर है बाबू भइया

स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर

भारतीय इकॉनमी पहेली की तरह है। कोविड महामारी की तबाही के बाद के तीन वर्षों में GDP में लगातार ग्रोथ दिखी, जो वित्त वर्ष 2023-24 में शानदार 8.2% तक जा पहुंची। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भी ग्रोथ 7.2% थी, जो बहुत ही अच्छी कही जा सकती है।

निचले तबके की मुश्किल | फिर भी खपत कमजोर बनी हुई है। इसका अंदाजा नेस्ले के सितंबर तिमाही के नतीजों से भी लगा, जो 1.6% रह गई थी। यह पिछले कई वर्षों में कंपनी की सबसे कम ग्रोथ है। दूसरी ओर, स्मॉल फाइनैंस बैंकों में लोन डिफॉल्टर्स की संख्या बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि समाज के निचले तबकों की आर्थिक मुश्किलें काफी ज्यादा हैं।

6.5% रहेगी ग्रोथ | जुलाई-सितंबर तिमाही में GDP ग्रोथ घटकर 5.4% पर आ गई, जो कोविड के बाद किसी भी तिमाही में सबसे कमजोर ग्रोथ है। इसके बाद जो अर्थशास्त्री पहले मौजूदा वित्त वर्ष में ऊंची ग्रोथ का अंदाजा लगा रहे थे, वे अब अपने अनुमान में कटौती करने में जुटे हैं। अब वे कह रहे हैं कि इस वित्त वर्ष में ग्रोथ 6.5% के करीब रहेगी।

सरकार का इरादा | लेकिन सरकार की ख्वाहिशें बड़ी हैं। उसने 2047 तक भारत को उच्च आय वाला देश बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए तब तक 8% की औसत GDP ग्रोथ हासिल करनी होगी। शायद, इस लक्ष्य को हासिल भी किया जा सकता है, लेकिन देश में जो राजनीतिक रोड़े सामने आते रहते हैं, वे इसे नामुमकिन बना देते हैं।

2019-20 की याद | सितंबर तिमाही में ग्रोथ के 5.4% तक फिसलने का मतलब है कि इकॉनमी में बुनियादी दिक्कतें बनी हुई हैं। जिन्हें भारत से बहुत आशा नहीं है, वे कहते हैं कि ग्रोथ कहीं वित्त वर्ष 2019-20 की तरह गोता न लगा दे। तब यह 4.0% तक जा पहुंची थी।

आधा-अधूरा जवाब | अर्थशास्त्रियों को इसका कारण समझाने में मुश्किल हुई। उनकी ओर से जो वजहें बताई गईं, वे आधी-अधूरी लगती हैं। मेरे खयाल से इसका आसान जवाब यह है कि उस वित्त वर्ष में देश की सारी कमजोरियां सामने आ गईं। वैश्विक ग्रोथ में गिरावट का भी बुरा असर पड़ा। फिर कोविड महामारी ने भी दस्तक दी थी।

ग्रोथ का सीन
- 8% की विकास दर मुमकिन नहीं
- लॉन्ग टर्म में 6.5% ग्रोथ संभव
- मुफ्त वादों से आ रही मुश्किल

क्यों गिरी ग्रोथ | पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार शंकर आचार्या जैसे निराशावादी कहते रहे हैं कि भारत शायद 5.5% से ही बढ़ता रहे। IMF के पूर्व अर्थशास्त्री अशोक मोदी ने तो इससे भी कम ग्रोथ की भविष्यवाणी की है। लेकिन सच यह भी है कि कोविड महामारी के बाद भारत की ग्रोथ काफी तेज रही है। फिर सितंबर तिमाही में क्या हुआ?

गलती कहां हुई | मैन्युफैक्चरिंग कमजोर है। दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र में भी रिकवरी नहीं हुई। लेकिन इस साल मॉनसूनी बारिश अच्छी हुई है, इसलिए अगली दो तिमाहियों में कृषि क्षेत्र की ग्रोथ अच्छी रह सकती है। इस साल मई में आम चुनाव हुए थे। इसलिए वित्त वर्ष की पहली दो तिमाहियों में सरकार की ओर से खर्च धीमा रहा। आने वाली दो तिमाहियों में इसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस वित्त वर्ष में ग्रोथ 6.5% या उससे कुछ ज्यादा रहेगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है।

क्या है मुश्किल | भारत निम्न मध्यम आय वाला देश है। ऐसे में 6.5% की ग्रोथ सराहनीय कही जा सकती है। खासतौर पर ऐसे हालात में जब दुनिया में नए शीत युद्ध की वजह से वैश्विक व्यापार और निवेश पर बुरा असर पड़ा है। लेकिन यह बात भी सही है कि चीन यह साबित कर चुका है कि निम्न मध्यम आय वाला देश भी कई वर्षों तक 10% से अधिक ग्रोथ हासिल कर सकता है। ऐसे में यह सवाल तो बनता है कि भारत लगातार 8% की ग्रोथ हासिल क्यों नहीं कर पाता?

रेवड़ी कल्चर दोषी | इसका जवाब देश के सियासी माहौल में छिपा है। चुनाव जीतने के लिए यहां सरकारें किसान, ट्रेड यूनियन, शिक्षक, जज लॉबी को खुश करने की कोशिश करती हैं। वे किसानों, बड़े उद्योगों, SME एंटरप्राइजेज और कई धार्मिक समूहों, जातियों, बच्चों, महिलाओं, पेंशनधारियों को रेवड़ियां बांटती हैं। इसी वजह से सरकारों के पास निवेश के लिए जरूरी रकम नहीं बच पाती।

राजनीतिक बाधाएं | BJP देश में BMS नाम से सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन चलाती है और कांग्रेस AITUC। इस लिहाज से दोनों ही श्रमिकों की पार्टियां हैं। इसलिए इनसे श्रम सुधारों या ऐसे ही दूसरे रिफॉर्म्स की आशा नहीं की जा सकती।

संतुलित ग्रोथ 6.5% | भारत के पास 8% ग्रोथ हासिल करने की प्रतिभा है, बशर्ते राजनीतिक रुकावटें न आएं। अगर ग्रोथ और राजनीतिक दिक्कतों के बीच संतुलन बनाया जाए तो भारत 6.5% की ग्रोथ हासिल कर सकता है। आशावादी इससे अधिक चाहते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मानकों के लिहाज से देखें तो 6.5% की ग्रोथ अच्छी मानी जाएगी। इसलिए दूसरी तिमाही के नतीजों पर बहुत हाय-तौबा मचाने की जरूरत नहीं है।

अनसोशल होता बचपन

ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। इसी साल हुए एक सर्वे में लगभग 60% भारतीय अभिभावक भी ऐसा ही कुछ चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर यह बहस तेज हो चुकी है कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाना चाहिए या नहीं? या फिर इसके फायदे-नुकसान क्या हैं? आइए समझते हैं पूरा मामला...

यहां का हाल

ऑस्ट्रेलिया की बात

2025 की शुरुआत में लागू होगा नया कानून।

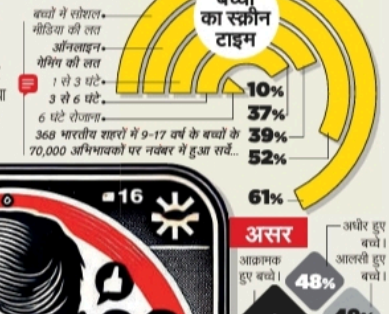

- X, टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम जद में।
- यूजर्स को बतानी होगी उम्र।
- एडवांस वेरिफिकेशन तकनीक बनानी होगी।
- कंपनियां नहीं रख पाएंगी डेटा।

77% ऑस्ट्रेलियाई चाहते थे यह कानून।

$32M का जुर्माना कानून तोड़ने पर।

आयु प्रमाण के लिए नहीं देने होंगे सरकारी दस्तावेज।

असर

(लोकलसर्किल्स)

फायदे-नुकसान

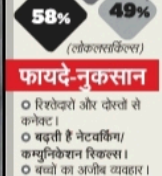

- रिश्तेदारों और दोस्तों से कनेक्ट।
- बढ़ती है नेटवर्किंग/कम्युनिकेशन स्किल्स।
- बच्चों का अजीब व्यवहार।
- धमकी, ब्लैकमेल, पॉर्न।

जोखिम कम नहीं

अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की किशोरावस्था में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सलाह...

- अत्यधिक सोशल मीडिया से किशोरों की क्षमता खराब।
- समय के साथ अधिक गंभीर मनोवैज्ञानिक नुकसान का जोखिम।

"बच्चों को सच-झूठ का कोई आइडिया नहीं होता। नंबर देखकर वे अपनी झूठी दुनिया बना लेते हैं, लेकिन धोखा खा जाते हैं। इसके चलते बच्चों में सबसे ज्यादा डिप्रेशन और सोशल एंग्जाइटी सामने आ रहा है। *-डॉ. विकास सैनी, सीनियर साइकैट्रिस्ट*"

किताब से आइडिया

कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का बैन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जोनाथन हैडट की इसी साल आई किताब- 'The Anxious Generation' से भी प्रेरित है...

- किताब में है कि फोन व इंटरनेट ने बचपन का 'खेल' बदला।
- 2010 तक बच्चों का खेलना बंद।
- दुनिया में इंटरनेट के हर 3 यूजर में से 1 यूजर बच्चा होता है।
- बच्चे सोशल मीडिया पर चिंताजनक सामग्री देखते हैं।

कंटेंट: राहुल पाण्डेय, ग्राफिक्स: अर्जुन सिंह

कायदा-कानून

भारत

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 की धारा 9 में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के डेटा के लिए 3 शर्तें हैं...

- अभिभावक की सहमति।
- व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण में पहले बाल कल्याण।
- निगरानी या टारगेटेड विज्ञापन बैन।

दुनिया का हाल...

US+UK	फ्रांस	चीन
वेबसाइटें बिना पैरेंट्स की मंजूरी के 13 वर्ष से कम के बच्चों का डेटा नहीं ले सकती।	कंपनी को माता-पिता की अनुमति के बिना 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ब्लॉक करना होगा।	अगस्त 2023 में इंटरनेट उपयोग की सीमा- 16-18 वर्ष-2 घंटे, 8-15 वर्ष - 1 घंटे।

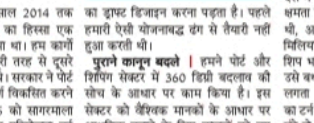

पोर्ट और शिपिंग सेक्टर की दुनिया कैसे बदली

डॉ. मनसुख मांडविया

देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की संकल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने आह्वान किया कि सन 2047 में, जब देश आजादी के 100 साल का जश्न मनाए, तब भारत विकसित बने। पीएम ने इसके लिए जरूरी पॉलिसी और रोडमैप भी पेश किया। देश को विकसित बनाने की यह सोच बेहद दूरदर्शी है।

इंफ्रा पर खर्च | किसी भी देश को तरक्की करनी है, तो पहले उसे आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। आर्थिक क्षेत्र की तरक्की सीधे-सीधे जुड़ी है देश के लॉजिस्टिक्स सेक्टर से। इस बात के महत्व को समझते हुए NDA सरकार ने इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स मॉडल बनाने की शुरुआत की है। 2014 के बाद इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा बजट देना शुरू किया। इससे देश में रोड, रेल, पोर्ट, हवाई अड्डे, जलमार्ग वगैरह का निर्माण तेजी से शुरू हुआ।

10 साल की उपेक्षा | आज पोर्ट और शिपिंग में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन चल रहा है। 2004 से 2014 तक, एक दशक के दौरान सभी सेक्टर उपेक्षित रहे थे। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ पोर्ट और शिपिंग सेक्टर को। पोर्ट में शिप का वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, कार्गो कंजेशन टाइम आदि दुनिया के मुकाबले बहुत पिछड़ा हुआ था। दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आने वाले कार्गो जहाज के लिए पानी की जरूरी गहराई (ड्राफ्ट) उपलब्ध नहीं थी। इसके कारण शिप को पूरा भर के पोर्ट तक नहीं लाया जा सकता था। इससे शिपिंग की लागत अधिक रहती थी।

योजनाबद्ध तैयारी | साल 2014 तक ग्लोबल शिपिंग में भारत का हिस्सा एक प्रतिशत से भी कम हो गया था। हम कार्गो के आवागमन के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों के जहाजों पर निर्भर थे। सरकार ने पोर्ट और शिपिंग सेक्टर को पूर्ण विकसित करने के लिए 31 जुलाई 2015 को सागरमाला प्रॉजेक्ट लॉन्च किया। यह परियोजना नई तकदीर लिख रही है। पहली बार भारत ने दुनिया की तरह सोचने की शुरुआत की। जैसे कि, दुनिया में अभी किस तरह के जहाज चल रहे हैं और भविष्य में किस तरह के चलेंगे, इसे ध्यान में रखते हुए पोर्ट पर बर्थ की लंबाई, इक्विपमेंट और पानी का ड्राफ्ट डिजाइन करना पड़ता है। पहले हमारी ऐसी योजनाबद्ध ढंग से तैयारी नहीं हुआ करती थी।

AI Image

कॉमन रूम

पुराने कानून बदले | हमने पोर्ट और शिपिंग सेक्टर में 360 डिग्री बदलाव की सोच के आधार पर काम किया है। इस सेक्टर को वैश्विक मानकों के आधार पर आधुनिक बनाने के लिए कानूनों को नए सिरे से तैयार किया गया है। उदाहरण के तौर पर, 156 साल पुराने एडमिरैलिटी एक्ट की जगह पर एडमिरैलिटी एक्ट 2017 लाया गया। 94 साल पुराने लाइट हाउस एक्ट का स्थान एड्स टु नेविगेशन एक्ट 2021 ले चुका है। 66 साल पुराने कोस्टल शिपिंग कानून की जगह कोस्टल शिपिंग बिल 2024 और मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 भी लाया गया है। इस सेक्टर का एकमात्र बचा हुआ पुराना कानून 1908 से चला आ रहा है और अब इसे भी नया बनाने की प्रक्रिया आखिरी चरण में है। देश में 2014 तक सिर्फ 5 नैशनल वॉटर वेज थे, आज 111 हैं।

अभूतपूर्व प्रगति | आज हमारे पास 'फ्लैग इन इंडिया इंसेंटिव पॉलिसी' और 'मैरीटाइम इंडिया विजन 2030' है। कुछ आंकड़ों पर गौर कीजिए, वर्ष 2014 तक देश में सरकारी पोर्ट पर कुल कार्गो वहन की क्षमता सालाना 1400 मिलियन मीट्रिक टन थी, आज बढ़कर सालाना लगभग 2700 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है। पहले जब शिप भारत के बंदरगाहों पर आता था, तब उसे बर्थ मिलने में औसत 36 घंटे का समय लगता था। अब 19 घंटे लगते हैं। कंटेनर का टर्न अराउंड टाइम 42 घंटे से घटकर 30 घंटे हो गया है। दुनिया के कुल सी-फेरर में 2014 तक भारत की हिस्सेदारी 5.9% थी, यह बढ़कर अभी 15% हो गई है। संक्षेप में कहें तो पोर्ट और शिपिंग से जुड़े सभी पहलू पर देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है।

(लेखक केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री हैं)

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

परमात्मा से जुड़ते ही जीवन आनंद से भर जाता है

आनंदमूर्ति गुरुमां

मानव सामान्य तौर पर वही चीज जल्दी समझ सकता है, जिससे वह जुड़ा होता है। गृहस्थ जीवन में एक स्त्री अपने पति को बेहतर समझ पाती है, उसी तरह से पति भी पत्नी को। जिस प्रकार एक स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, वैसे ही एक भक्त के लिए भगवान उसके प्रियतम होते हैं। इस नजरिए से देखें तो परमात्मा ही उसका पीर और पति बन जाते हैं। जीव रूपी स्त्री के प्रियतम परमात्मा ही होते हैं। यदि यह जीव अपने प्रभु के संग नहीं है, तो वह घोर दुख में डूबा रहता है, पर जब वह अपने परमात्मा से जुड़ता है, तो स्वयं को प्रभु के साथ बैठा हुआ महसूस करता है और आनंदित होता है।

यदि कोई जीव परमात्मा के सुमिरन से दूर है, तो उसका जीवन नीरस हो जाता है। जब जीव अपने प्रभु के संग रहता है, तो वह वास्तविक शोभा बन जाती है। जो जीव परमात्मा को खोज रहा है, जो आनंद और शांति की तलाश में है, और जो अपने परमात्मा रूप पति के संग एकाकार हो जाता है, वही अपने जीवन में शोभा प्राप्त करता है। इसे हम उस स्त्री के उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जिसका पति परदेस में है और वह अकेली बैठी आंसू बहा रही है और उसका इंतजार कर रही है। यह स्थिति उस जीव की होती है, जो परमात्मा से दूर होता है।

गुरु अर्जुन देव जी महाराज का उपदेश है कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं, वे थोड़े समय के लिए खुशी दे सकते हैं। रिश्ते, भोग-विलास और खाने-पीने की चीजें कुछ समय के लिए आनंद दे सकती हैं, लेकिन संसार की वस्तुओं का एक नियम है कि वह कभी स्थायी सुख नहीं दे सकतीं। इसके विपरीत, जब जीव परमात्मा के संग होता है, तो उसे बिना किसी शर्त के सुख, सुरक्षा और शांति प्राप्त होती है। जिनकी बातें आपको शुकून देती हैं, आप उनके पास बैठना चाहते हैं। हालांकि बदले में क्या वह आपसे शुकून भरा पल नहीं चाहता।

परमात्मा अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। चाहे वह ज्ञान में हो या अज्ञान में, शांत हो या अशांत, परमात्मा हमेशा उसके साथ रहते हैं, उसके भीतर रहते हैं। जब तक जीव अपने अस्तित्व को परमात्मा से अलग नहीं मानता, तब तक वह परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि उसका अस्तित्व स्वयं परमात्मा का अस्तित्व है। गुरु महाराज ने ध्यान और भक्ति के महत्व को स्पष्ट किया है। जब एक जीव अपने ध्यान में गहरे उतरता है, तो उसका मन हर बंधन से मुक्त हो जाता है। जब मन में कोई दुनियावी इच्छाएं या रिश्तों की पकड़ नहीं रहती, तब जीव परमात्मा के संग एकाकार होता है। यह तब संभव है, जब ध्यान की पूर्णता प्राप्त होती है।

अगर मन में किसी रिश्ते, वस्तु या व्यक्ति से जुड़ी कोई पकड़ होती है, तो वह केवल दुख ही देती है। इसलिए हमें इन सारी दुनियावी चीजों से अपनी पकड़ छोड़ देनी चाहिए और परमात्मा के संग एकात्मता की ओर बढ़ना चाहिए। जब हम यह पूरी तरह से करते हैं, तो हमारा समय और जीवन आनंद और सुख से भर जाता है।

हमें परमात्मा के संग एकता स्थापित करनी चाहिए। और यह ध्यान और भक्ति से संभव है। जब हम अपने मन और तन को परमात्मा के रंग में रंग लेते हैं, तब अपने जीवन को सुखमय और आनंदमयी बना सकते हैं। यही सच्चा सुख और शांति है।

निवेश को बढ़ावा देने के लिए आत्मविश्वास के साथ यह भी जरूरी है कि अनिश्चितता कम से कम हो। -जोआकिम लेवी

आयुष मंत्रालय की बीते एक दशक की यात्रा देश में आयुष बाजार के अभूतपूर्व विकास की कहानी बताने के साथ भारत के स्वदेशी ज्ञान और परंपराओं की शक्ति को भी दर्शाती है। सही दिशा में प्रयास जारी रहे, तो विज्ञान व परंपरा के संगम से आयुष प्रणाली सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया को आरोग्य की राह दिखा सकती है।

आरोग्य की राह

आयुष मंत्रालय के आंकड़े पिछले दस वर्षों में देश में आयुष बाजार के अभूतपूर्व विकास की कहानी को तो खैर दर्शाते ही हैं, ये भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में लोगों के बढ़ते भरोसे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती स्वीकृति के भी प्रमाण हैं। 2014 में आयुष मंत्रालय के गठन के बाद आयुष बाजार (आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नीतिगत सुधार तो किए ही, आयुष मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) में सामंजस्य बैठाते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से ही योग को अंतरराष्ट्रीय मंच पर विशेष पहचान मिली, जिसके परिणामस्वरूप ही संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। आंकड़ों की बात करें, तो देश में आयुष बाजार का आकार 2014 के 2.85 अरब डॉलर से बढ़कर 2023 में 43.4 अरब अमेरिकी डॉलर हुआ है। साथ ही, इस क्षेत्र से होने वाले निर्यात के दोगुने होने से यही पता चलता है कि भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां न केवल घरेलू, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही हैं। आयुष बाजार की वृद्धि केवल स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसने रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर भी पैदा किए हैं। आयुर्वेदिक दवाओं, हर्बल उत्पादों व योग से जुड़े सामानों का निर्यात तेजी से बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में भी छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिला है। जाहिर है कि आयुष मंत्रालय की पिछले एक दशक की परिवर्तनकारी यात्रा ने भारत को पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में पहुंचा दिया है। भारतीय आयुष उत्पादों को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्यता मिलना भी इस क्षेत्र के लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ चुनौतियों पर भी ध्यान देना होगा। गुणवत्ता नियंत्रण के मानकों को बनाए रखना, जड़ी-

बूटियों की आपूर्ति शृंखला को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाने पर ध्यान देना, वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुसार उत्पादों को विकसित करना भी बेहद आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक चिकित्सा मॉडल के साथ समन्वित करना भी एक अहम मुद्दा है, ताकि यह पूरक व्यवस्था के रूप में कार्य कर सके। आयुष बाजार की प्रगति भारत के स्वदेशी ज्ञान और परंपराओं की शक्ति को दर्शाती है। अगर सही दिशा में प्रयास जारी रहे, तो विज्ञान व परंपरा के संगम से आयुष प्रणाली सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया को आरोग्य की राह दिखा सकती है।

केंद्रीय बैंक को कई बातों का जवाब देना है

जीडीपी वृद्धि के लिए उसके पूर्वानुमान से लेकर मुद्रास्फीति लक्ष्यों तक रिजर्व बैंक को बहुत-सी बातों का जवाब देना है। जनवरी में उसने तर्क दिया कि खाद्य महंगाई उसके दायरे से बाहर है और अगस्त में उसने तर्क दिया कि उसे इसे कम करना होगा। इस बीच, खाद्य मुद्रास्फीति 18 महीनों से औसतन सात प्रतिशत से ऊपर रही है।

पिछले कई महीनों से लिविंग रूम्स, बाजारों और सी-सुइट्स में चल रही कानाफूसियां और आशंकाएं अब सच साबित हो रही हैं। अर्थव्यवस्था में सब कुछ ठीक नहीं है। शुक्रवार को सांख्यिकी मंत्रालय ने सूचित किया कि जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत रही, जो पिछले साल की समान अवधि के 8.1 प्रतिशत से कम है। यह लगभग दो वर्षों में सबसे कम है। सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) 5.6 प्रतिशत रहा, जो 8.1 प्रतिशत के नॉमिनल जीवीए से कम है। इसके बावजूद यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, मगर अपनी क्षमता से काफी कम विकास कर रही है।

देश की युवा जनसांख्यिकी एवं युवा बेरोजगारी की चुनौतियों को देखते हुए यह मध्यम एवं लंबी अवधि के लिए जोखिम भरा है। विशेष रूप से, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े कृषि प्रधान राज्यों में इसके गहरे राजनीतिक निहितार्थ हैं। सुस्ती की हकीकत सरकारी व कॉरपोरेट डाटा में सभी क्षेत्रों में उपभोक्ता मांग और कॉरपोरेट आय में स्पष्ट दिखाई दे रही है, जो एक अनुमान के अनुसार चार साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। शहरी मजदूरी में लगातार गिरावट से स्थिति और भी खराब हो रही है, जिसका असर उपभोग पर पड़ रहा है। हालांकि, आंकड़ों ने देश के मुद्रा प्रबंधक को बहुत बेचैन नहीं किया है। बीते नौ अक्तूबर को रिजर्व बैंक ने दर्ज किया कि पहली तिमाही में विकास धीमा था, लेकिन दावा किया कि दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि 7.2 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। यह अनुमान गलत साबित हुआ है।

शंकर अय्यर
वरिष्ठ पत्रकार

वित्तीय वर्ष के छह महीने बीत चुके हैं और वर्ष की पहली छमाही में जीडीपी वृद्धि छह प्रतिशत है। जाहिर है, 7.2 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि के लक्ष्य के लिए जरूरी दर चुनौतीपूर्ण है। कम वृद्धि से रोजगार सृजन में कमी आती है और निवेश और खपत में बाधा आती है। सुस्ती के बारीक विवरण स्पष्ट हैं। 2023-24 की दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र 14.3 प्रतिशत से गिरकर 2.2 प्रतिशत पर आ गया है; खनन क्षेत्र, जो पिछले साल 11.1 प्रतिशत पर था, सिकुड़ गया है। 3.5 प्रतिशत पर कृषि, विनिर्माण से अधिक तेजी से बढ़ रही है। हाल के वर्षों में भारत की कहानी सार्वजनिक निवेश से प्रेरित रही है। साल-दर-साल के आधार पर, सरकार का अंतिम उपभोग व्यय इस साल की दूसरी तिमाही में 14 प्रतिशत से घटकर 4.4 प्रतिशत हो गया है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण, जो नए निवेश का संकेत है, 11.6 प्रतिशत से घटकर 5.4 प्रतिशत हो गया है। प्रभावी रूप से सरकारी व्यय कम है। निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय धीमा है। निजी उपभोग कम है, क्योंकि जीवनयापन का खर्च और भर्ती व कैंपस प्लेसमेंट में कमी के कारण रोजगार की अनिश्चितता के चलते उपभोक्ता अपनी इच्छाओं और क्षमताओं के अनुसार उपभोग नहीं कर पाते। कुल मिलाकर, नतीजा यह है कि विकास की दर मुद्रास्फीति की दर से पीछे चल रही है। कहावत है कि पैसा ही आर्थिक गतिविधि, निवेश, रोजगार सृजन, आय और उपभोग को बढ़ावा देता है। व्यय, निवेश, आय और उपभोग में कमी विकास को नीचे खींच रही है। मुद्रास्फीति की राजनीति ने विकास को कम कर दिया है।

सरकारी खर्च कम होने के कई कारण बताए गए हैं-चुनावों से लेकर चरम मौसम की घटनाओं तक। जाहिर है कि तर्कों में दम है, भले ही आंशिक रूप से ही क्यों न हो। खराब शासन आर्थिक सुस्ती का मुख्य कारण है। विश्लेषकों ने बताया है कि राज्य सरकारों ने रियायतों पर जरूरत से ज्यादा खर्च किया है। आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि मुफ्त सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किए गए राजस्व व्यय में वृद्धि हुई है और परियोजनाओं पर कम खर्च हुआ है। इंडिया रेटिंग्स की हालिया रिपोर्ट बताती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित 11.11 लाख करोड़ रुपये में से लगभग 62,000 करोड़ रुपये खर्च ही नहीं किए जा सके। एक तरफ तो खर्च नहीं किया गया पैसा है, दूसरी तरफ पैसे की लागत है। निजी उपभोग 61 फीसदी से ज्यादा जीडीपी में योगदान करता है और मांग को बनाए रखने के लिए पैसे तक पहुंच और कीमत, दोनों मायने रखते हैं।

अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता रिजर्व बैंक की कार्रवाइयों का खामियाजा भुगत रहे हैं - माइक्रो फाइनेंस संस्थानों पर कार्रवाई, व्यक्तिगत ऋण और उच्च ब्याज दरों पर कार्रवाई। आरबीआई को बहुत-सी बातों का जवाब देना है : जीडीपी वृद्धि के लिए उसके पूर्वानुमान से लेकर मुद्रास्फीति लक्ष्यों तक। जनवरी में, आरबीआई ने तर्क दिया कि खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति उसके दायरे से बाहर है, और अगस्त में उसने तर्क दिया कि उसे इसे कम करना होगा। इस बीच, खाद्य मुद्रास्फीति 18 महीनों से औसतन सात प्रतिशत से ऊपर रही है। नवंबर में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6.2 प्रतिशत और खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति 10.9 प्रतिशत पर थी। खाद्य मुद्रास्फीति सीपीआई का 45 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है और सबसे गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ब्याज दरों में कटौती की जरूरत पर खूब चर्चा हो रही है। इससे मांग को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन आर्थिक सुस्ती से निपटना ब्याज दरों में कटौती से कहीं अधिक जरूरी है।

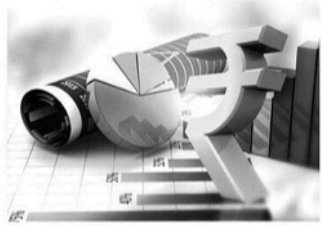

भारत की अर्थव्यवस्था तत्काल संरचनात्मक सुधार की मांग करती है। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को समायोजित करने के लिए परिवारों को अपने बजट में बदलाव करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। उच्च ब्याज दरों ने कीमतों को कम नहीं होने दिया है। इसका कारण मौसम की अनिश्चितताओं और मनमानी नीतियों के अलावा उपलब्धता, भंडारण, वितरण और प्रसंस्करण की अपर्याप्तता है। अनिवार्य रूप से भारत को जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं और अनाज के लिए एक राष्ट्रीय ग्रिड की आवश्यकता है, जैसे दूध के लिए है। यह सीधे राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है। रोजगार सृजन के लिए सक्रिय निवेश प्रोत्साहन जरूरी है।

यह कोई रहस्य नहीं है कि श्रम कानून व्यवसाय को बाधित करते हैं। वे कंपनियों को बड़ी संख्या में लोगों को काम पर रखने से भी रोकते हैं। फिर भी 2019 में तैयार नया श्रम कानून कई राज्यों ने नहीं अपनाया है। बोझिल और पुरानी विनियामक आवश्यकताओं और अनुपालनों को मिला लें, तो नए और पुराने व्यवसाय डरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक वर्ग को इन कमियों का पता नहीं है। इसका पता चुनावी क्षेत्र के नवाचार से मिलता है। कटु सच्चाई यह है कि चुनावी बीजगणित रोजगार और विकास की तुलना में करदाताओं को दी गई रियायतों का पक्षधर है। 1990 के दशक में बिल क्लिंटन 'इट्स द इकनॉमी, स्टुपिड' के नारे पर सत्ता में आए थे। भारतीय संदर्भ में, आर्थिक सुस्ती का मूल कारण राजनीति है!

edit@amarujala.com

जीवन धारा

सरदार पूर्ण सिंह

वर्षा और नदी के जल से तो अन्न पैदा होता है, परंतु नयनों की गंगा से प्रेम और वैराग्य द्वारा मनुष्य जीवन को आग और बर्फ से बपतिस्मा मिलता है, अर्थात नया जन्म होता है।

दिल खोलकर रोना भी वरदान है

धन्य हैं वे नयन, जो कभी-कभी प्रेम-नीर से भर आते हैं। प्रतिदिन गंगाजल में तो स्नान होता ही है, परंतु जिस पुरुष ने नयनों की प्रेमधारा में कभी स्नान किया है, वही जानता है कि इस स्नान से मन के मलिन भाव किस तरह बह जाते हैं, अंतःकरण कैसे पुष्प की तरह खिल जाता है, हृदय-ग्रंथि कैसे खुल जाती है, कुटिलता और नीचता का पर्वत कैसे चूर-चूर हो जाता है। सावन-भादों की वर्षा के बाद वृक्ष जैसे नवीन-नवीन कोपलें धारण किए हुए एक विचित्र मनमोहिनी छटा दिखाते हैं, उसी तरह इस प्रेम-स्नान से मनुष्य की आंतरिक अवस्था स्वच्छ, कोमल और रसभीनी हो जाती है। प्रेमधारा के जल से सींचा हुआ हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। हृदयस्थली में पवित्र भावों के पौधे उगते, बढ़ते और फलते हैं। वर्षा और नदी के जल से तो अन्न पैदा होता है, परंतु नयनों की गंगा से प्रेम और वैराग्य के द्वारा मनुष्य जीवन को आग और बर्फ से बपतिस्मा मिलता है, अर्थात नया जन्म होता है। मानो प्रकृति ने हर एक मनुष्य के लिए इस नयन नीर के रूप में मसीहा भेजा है, जिससे हर एक नर-नारी कृतार्थ हो सकते हैं। यही वह यज्ञोपवीत है, जिसे धारण करने से हर आदमी द्विज हो सकता है। क्या ही उत्तम किसी ने कहा है-'हाथ खाली मर्दमे दीदा बुतों से क्या मिलें। मोतियों की पंज-ए-मिजगां में इक माला तो हो।।'

आज हम उस अश्रुधारा का स्मरण नहीं करते, जो ब्रह्मानंद के कारण योगीजनों के नयनों से बहती है। प्रेम की बूंदों में यह असार संसार मिथ्या रूप होकर घुल जाता है और हम पृथ्वी से उठकर आत्मा के पवित्र नभो-मंडल में उड़ने लगते हैं। अनुभव करते हुए भी ऐसी घुली हुई अवस्था में हर कोई समाधिस्थ हो जाता है, अपने-आपको भूल जाता है, प्रेम की काली घटा ब्रह्म रूप में लीन हो जाती है। चाहे जिस शिल्पकार, चाहे जिस कला-कुशल-जन के जीवन को देखिए, उसे इस परमावस्था का स्वयं अनुभव हुए बिना अपनी कला का तत्वज्ञान नहीं होता। चित्रकार सुंदरता को अनुभव करता है और तत्काल ही मारे खुशी के नयनों में जल भर लाता है। बुद्धि, प्राण, मन और तन सुंदरता में डूब जाते हैं। सारा शरीर प्रेमवर्षा के प्रवाह में बहने लगता है। वह चित्र ही क्या, जिसको देख-देखकर चित्रकार की आंखें इस मदहोश करने वाली ओस से तर न हुई हों। वह चित्रकारी ही क्या, जिसने हजार बार चित्रकार को इस योग-निद्रा में न सुलाया हो। हमारी आंखें कुछ ऐसी ही हैं। जिस प्रकार वे इस संसार के कर्ता को नहीं देख सकतीं, उसी प्रकार आध्यात्मिक देश के बादल और धुंध में सोए हुए कलाधर पुरुष को नहीं देख सकतीं। उसकी कविता, जो हमको मदमत्त करती है, वह एक स्थूल चीज है और यही कारण है कि कला निपुण जन प्रतिदिन अधिक से अधिक उस आध्यात्मिक अवस्था का अनुभव करता है।

सपनों की सुंदरता में विश्वास करें

सूत्र

आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद न करें। हठधर्मिता में न फंसें, जो दूसरे लोगों की सोच के परिणामों के साथ जीता है, उनका कुछ नहीं होता। भविष्य उनका है, जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, आगे बढ़ते रहने का साहस ही मायने रखता है। जितना जरूरी हंसना है, उतना ही जरूरी रोना भी है, खुल कर रोएं, आप बेहतर महसूस करेंगे।

दूसरा पहलू

वैज्ञानिकों ने चूहों पर किए शोध में पता लगाया है कि कोविड मरीज में विशेष तरह के मोनोसाइट्स का निर्माण होता है।

कोविड आरएनए में छिपी कैंसर के इलाज की चाबी

कोरोना संक्रमण ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इस गंभीर संक्रमण के एक अप्रत्याशित लाभ का पता चला है यानी यह कैंसर के खतरे को कम करता है। चूहों पर किए गए शोध के आधार पर हाल ही में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक कोविड के संक्रमण के कारण कैंसर ट्यूमर सिकुड़ जाते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिन्हें मोनोसाइट्स कहते हैं, जो हमारे शरीर को तमाम संक्रमणों और अन्य खतरों से बचाने में अहम भूमिका निभाती हैं।

जस्टिन स्टेबिंग

सामान्य मोनोसाइट्स के विपरीत, जिन्हें ट्यूमर द्वारा सुरक्षात्मक कोशिकाओं में परिवर्तित किया जा सकता है, इन प्रेरित मोनोसाइट्स ने अपने कैंसर से लड़ने वाले गुणों को बरकरार रखा।

कैंसर रोगियों में कभी-कभी ट्यूमर कोशिकाएं मोनोसाइट्स को अपहृत कर उसे कैंसर-अनुकूल कोशिकाओं में परिवर्तित कर देती हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली से ट्यूमर की रक्षा करते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि गंभीर कोविड संक्रमण के कारण शरीर कैंसररोधी गुणों वाले विशेष प्रकार के मोनोसाइट्स का उत्पादन करता है, जो कैंसर कोशिकाओं से भी लड़ता है। मोनोसाइट्स एक विशेष ग्राह्य होता है, जो कोविड आरएनए के एक विशिष्ट अनुक्रम से अच्छी तरह से जुड़ता है। शोध में शामिल नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक अंकित भरत ने ताला-चाबी के उदाहरण से समझाया कि यदि मोनोसाइट एक ताला था और कोविड आरएनए उसकी चाबी, तब कोविड आरएनए उसमें एकदम फिट हो गया। अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए शोध दल ने मेलेनोमा, फेफड़े, स्तन और पेट के कैंसर सहित विभिन्न प्रकार के स्टेज-4 कैंसर वाले चूहों पर प्रयोग किया। उन्होंने चूहों को एक ऐसी दवा दी, जो गंभीर कोविड संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की नकल करती थी, जिससे इन विशेष मोनोसाइट्स का उत्पादन प्रेरित होता था। सभी चार प्रकार के कैंसर में चूहों के कैंसर ट्यूमर सिकुड़ने लगे थे।

सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए शोध दल ने मेलेनोमा, फेफड़े, स्तन और पेट के कैंसर सहित विभिन्न प्रकार के स्टेज-4 कैंसर वाले चूहों पर प्रयोग किया, जो सफल रहा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह शोध इन्सानों में भी सफल होगा।

सामान्य मोनोसाइट्स के विपरीत, जिन्हें ट्यूमर द्वारा सुरक्षात्मक कोशिकाओं में परिवर्तित किया जा सकता है, इन प्रेरित मोनोसाइट्स ने अपने कैंसर से लड़ने वाले गुणों को बरकरार रखा। फिलहाल यह अध्ययन चूहों पर किया गया है। उम्मीद है कि इससे इन्सानों के कैंसर रोग में भी सफलता मिले। साथ ही नया शोध नई दवाओं और टीकों के विकास की संभावनाओं के द्वार खोलता है। यह अध्ययन वायरस, प्रतिरक्षा प्रणाली और कैंसर के बीच जटिल संबंधों की हमारी समझ में एक रोमांचक कदम का प्रतिनिधित्व करता है। यह नए चिकित्सकीय दृष्टिकोणों के लिए आशा प्रदान करता है और अक्सर अप्रत्याशित तरीकों को रेखांकित करता है, जिससे वैज्ञानिक खोजों से चिकित्सा संबंधी सफलताएं मिल सकती हैं। *(-द कन्वर्सेशन से)*

आंकड़े

वस्त्र निर्यात

भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष में अलग-अलग तरह के वस्त्र और इसे बनाने वाली सामग्री का निर्यात विभिन्न देशों में किया है।

रेडीमेड	42.4%
सूती धागा, हैंडलूम	34%
हस्तनिर्मित वस्त्र	13.6%
हस्तनिर्मित कार्पेट	5.2%
मशीन कार्पेट, अन्य	4.7%

आंकड़े निर्यात किए गए वस्त्र व अन्य सामग्री के, प्रतिशत में | स्रोत : IBEF

भक्त रघु के जाल में फंसी मछली ने जब यह कहा, 'नारायण रक्षा करो', तो वह समझ गए, यह ईश्वर की प्रेरणा है। इसके बाद भगवान ने रघु को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए।

भक्त रघु केवट

जगन्नाथ पुरी से दस कोस पर पिपलीचटी गांव में रघु नामक एक केवट रहता था। रघु रोज नदी पर जाता और मछलियां पकड़कर बेच देता था। वह मछलियों को जाल में फंसकर तड़पते देखता, तो उसका हृदय पसीज जाता, लेकिन आजीविका का दूसरा कोई साधन न देखकर, वह स्वयं को कई तरह की दलीलें देकर मन को शांत करता।

उसे एक दिन अपनी इस वृत्ति से बड़ी घृणा हुई और एक महात्मा के पास जाकर उनसे दीक्षा ली। और धीरे-धीरे उसका काम छूट गया। कुछ दिन तक घर ठीक चला, लेकिन जब अन्न समाप्त हो गया, घर में त्राहि-त्राहि मच गई। अंत में विवश होकर जाल लेकर नदी की ओर चला, जाल में एक बड़ी भारी मछली फंस गई। उसी समय मछली बोली, 'रक्षा कर, नारायण! रक्षा कर।' रघु ने यह सुनते ही उसे वापस पानी में छोड़ दिया। रघु समझ गया और प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान! शब्द रूप से आपने दर्शन तो दे दिए, लेकिन मैं आपके साक्षात दर्शन करना चाहता हूं। वह उसी स्थान पर तीन दिन बिना कुछ खाए-पिए नारायण मंत्र का जप करता रहा। भक्त की अचल भक्ति देखकर भगवान ने दिव्य चतुर्भुज रूप से दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। रघु ने कहा, 'अब तो केवल यही इच्छा है कि मेरा हृदय निरंतर आपके ध्यान में तल्लीन रहे और मेरा जीव हिंसा का स्वभाव बदल जाए।' भगवान ने तथास्तु कहकर सारी समस्याओं को हर लिया और अंतर्धान हो गए।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 01 अगस्त, 1962

रेलवे दुर्घटना का मुख्य कारण दोषपूर्ण संचालन नियम

रेलवे दुर्घटना का मुख्य कारण दोष पूर्ण संचालन नियम

अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा पारित किए गए एक प्रस्ताव में कहा गया है कि अधिकांश ट्रेन दुर्घटनाओं के होने का कारण अन्य कारणों के अलावा दोषपूर्ण संचालन नियमों तथा सामान का उपयोग है।

क्या भयमुक्त हैं हमारे विद्यालय

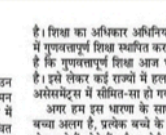

विद्यालयों में भयमुक्त माहौल न मिलने की वजह से बच्चे मनोदैहिक विकार 'साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर' का शिकार हो सकते हैं।

रवींद्र कुमार मिश्र | मुद्दा

क्या हमारे विद्यालय भयमुक्त शिक्षा के केंद्र हैं? यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। भयमुक्त शिक्षा केंद्र का मतलब है-एक ऐसा स्कूली वातावरण, जहां बच्चे डर, तनाव और किसी भी प्रकार की धमकी से मुक्त महसूस करें। विद्यालय में ऐसा वातावरण बच्चों की रचनात्मकता, आत्मविश्वास और समग्र विकास को बढ़ावा देता है। बच्चों को मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक, किसी भी प्रकार से दंड देना, कानूनन अपराध भी है। बच्चों के लिए सकारात्मक और सहायक वातावरण में बढ़ना और सीखना बहुत जरूरी होता है।

दबाव या दंड के बजाय, उन्हें समझाने और मार्गदर्शन देने से उनके मानसिक और भावनात्मक विकास में सहायता मिलती है। किसी मानसिक दबाव, दंड से अक्सर बच्चों में डर, चिंता और नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो उनके विकास को प्रभावित करती हैं। बच्चे मनोदैहिक विकार 'साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर' का शिकार हो सकते हैं। वे मन ही मन खुद को अकेला मान लेते हैं, जो उनकी शारीरिक समस्याएं बढ़ने का कारण बन जाते हैं।

बच्चों की दिनचर्या को देखें। ज्यादातर विद्यालय, जो लगभग सूर्योदय के साथ प्रारंभ होते हैं, वहां अभिभावक बच्चों को जगाते हैं। बच्चों की नींद पूरी होती नहीं। बच्चे हड़बड़ी में नित्य कर्म से निवृत्त होते हैं, तरोताजा होते या नहीं, एक गंभीर सवाल है। शहर हो या गांव, उन नौनिहालों की सोचिए, जो प्रतिदिन वाहनों में आवागमन करते हैं, लंबी यात्रा करते हैं, बसों में ऊंघते, कक्षा में ऊंघते बचपन के उन्मुक्त जीवन और खेलों से वंचित रहते हैं। स्कूल या प्ले-स्कूल में एक तय फॉर्मेट है, जहां बच्चों की उन्मुक्तता सीमित-सी है, एकरस, नीरस जैसी है, वाहन, पाठ्यक्रम और लर्निंग आउटकम से बंधी है। बचपन वाहन, पाठ्यक्रम, आउटकम और स्कूल के बीच बंधा हुआ है। यदि इसे मशीनीकरण की उपमा दी जाए, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। बच्चे के सीखने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात लर्निंग आउटकम में समाहित हो जाती। समग्र प्रगति पत्र (होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट) एक अन्य आयाम है भय पैदा करने का।

गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा को लेकर शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई-2009 में बच्चों को बिना रोके अगली कक्षा में भेजने की व्यवस्था के पीछे समझ यह थी कि परीक्षा बच्चों पर दबाव बनाती है, छलनी का काम करती है, बच्चों में भय पैदा करती है और बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं के स्तर पर परीक्षा इस बात की वजह नहीं बननी चाहिए कि बच्चे शिक्षा से जी चुराने लगें। एक दलील यह कि बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं और आगे की कक्षाओं के परिणाम प्रभावित हो रहे हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन के साथ यह विचार खारिज कर दिया गया। आउटकम मापने पर जोर दिया जाने लगा और सीखना-सिखाना, गतिविधि आधारित शिक्षण, आनंददायी शिक्षण, लर्निंग रिकवरी जैसे शब्दों के जाल में सिमट गया प्रतीत होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम और नई शिक्षा नीति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्थापित करने की बात है। विडंबना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आज भी एक सपना बनी हुई है। इसे लेकर कई राज्यों में हलचल तो है, लेकिन यह असेसमेंट्स में सीमित-सा हो गया है।

अगर हम इस धारणा के साथ चलते हैं कि प्रत्येक बच्चा अलग है, प्रत्येक बच्चे के सीखने के तरीके भिन्न हो सकते हैं, होते हैं, और मनोवैज्ञानिक पक्ष कहता है कि सीखना भय रहित बेहतर होता है, तो फिर प्रतिफल असेसमेंट्स की कितनी आवश्यकता है? असेसमेंट के फलस्वरूप बच्चों और अभिभावकों पर हो रहे मानसिक दबाव का अध्ययन करना चाहिए। यह भी अध्ययन हो कि इसके आधार पर चलने वाले तथाकथित लर्निंग रिकवरी कार्यक्रम कितने वैज्ञानिक हैं और तीन से अधिक वर्ष से पढ़ाई में अच्छा नहीं करने वाले या पढ़ाई छोड़ देने वाले के लिए लर्निंग रिकवरी कार्यक्रम कितनी उपयुक्त रणनीति है? क्या तीन या उससे अधिक साल की कमी को छह महीने से एक साल में पूरा किया जा सकता है, विशेषकर बड़े बच्चों में?

बच्चों के साथ सावधानी बरतना और उन्हें प्यार, देखभाल और समझ प्रदान करना, सीखने के पर्याप्त अवसर देना महत्वपूर्ण है। यह केवल उनके भले के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी अधिक लाभकारी है। बच्चे अपने व्यवहार से सीखते हैं और यदि उन्हें सकारात्मक उदाहरण और सही मार्गदर्शन दिया जाता है, तो वे अपने अनुभवों से बेहतर समझ बना सकते हैं, सीख सकते हैं। बच्चे देश का भविष्य हैं, सामाजिक परिवर्तन के माध्यम हैं, यह कथनी और करनी, दोनों में परिलक्षित होनी चाहिए। -लेखक भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में मुख्य परामर्शदाता रहे हैं।

सम्पादकीय

सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा, निष्कर्षों को अमल में लाने के ठोस उपाय

भुवनेश्वर में आयोजित पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के तीन दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृहमंत्री और प्रधानमंत्री का शामिल होना इस सम्मेलन की महत्ता को रेखांकित करता है। इसकी पुष्टि इस सम्मेलन में आतंकवाद, नक्सलवाद, साइबर अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी और खालिस्तान समर्थक समूहों की गतिविधियों के अतिरिक्त आंतरिक सुरक्षा से जुड़े अन्य विषयों पर गहन चर्चा से भी होती है। इस सम्मेलन में तीन दिनों तक विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा के निष्कर्षों को अमल में लाने के ठोस उपाय करने से ही आंतरिक सुरक्षा को बल मिलेगा। वर्तमान में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कई मोर्चों पर गंभीर चुनौतियां खड़ी होती हुई दिख रही हैं। यह अच्छा है कि इस सम्मेलन में साइबर अपराधों पर भी गंभीर चर्चा की गई, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि साइबर अपराध बढ़ते ही चले जा रहे हैं। साइबर अपराधी जिस तरह संगठित होकर काम करने लगे हैं, वह सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि फिलहाल हमारी सुरक्षा एजेंसियां साइबर अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही हैं। यह ठीक है कि साइबर अपराधों के प्रति लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को साइबर अपराधियों के दुस्साहस का दमन भी करना होगा। अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है।

दुःख का बीज

हम ने अगर किसी को दु:ख देने का जरा सा भी भाव पैदा कर लिया तो समझ लो कि हम अपने लिए बीज बो रहे हैं,क्योंकि दु:ख देने का भाव का बीज तो हमारे मन की भूमि पर ही गिरा हुआ है , किसी दूसरे के मन की भूमि में नही गिरा हुआ। बीज तो हमारे भीतर ही लग गया, अंकुर भी हमारे भीतर ही फूटेगा,पौधा भी हमारे भीतर ही बनेगा और वह वृक्ष भी बनेगा, बड़ा पेड़ भी बनेगा, फल भी आएंगे और हमें ही वह फल भोगने होंगे। अंतरंग भाव से समझो तो देखिए जिस दिन हम दूसरों को दु:ख देने का प्लान मानते हैं उसी दिन से दु:ख पाना शुरू कर देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझिए, जब हम क्रोधित हैं,दूसरे को नष्ट कर देना चाहते हैं दूसरा नष्ट हो या ना हो हमारा खुद का तिल-तिल नष्ट होना शुरू हो जाता है। क्रोधित व्यक्ति का ब्लड प्रेशर (रक्तचाप) का यदि अपन निरीक्षण करें तो पता चलेगा कि क्रोध ने ब्लड प्रेशर कहां का कहां पहुंचा दिया । क्रोध करने वाले का बीपी हाई है लेकिन जिस पर क्रोध कर रहा है वह आनंद के साथ मुस्कुरा रहा है। यानि बीज हमारे भीतर की भूमि पर गिर गया है और चाहे खेत की भूमि उपजाऊ हो ना हो हमारी भूमि भयंकर उपजाऊ है। ये क्षण भर में अपना रंग दिखाती है देख लीजिए अधिकतर सुबह धार्मिक स्थलों पर में जाने वाले भक्त शाम होते ही दारू के ठेके पर पहुँच जाते हैं क्योंकि सुबह राम नाम का बीज अंकुरित होता है शाम तक भूमि रावण के बीज को अंकुरित कर डालती है। क्योंकि धार्मिक स्थलों पर जाने वाले दस मिनट से कोई खास असर नही होता क्योंकि मनुष्य को तो दिन भर तो झूठ,पाखंड, फरेब और कपट के वस्त्र पहन कर ड्रामा करना पड़ता है।

-रूपक शर्मा ,बढ़ता राजस्थान

क्या टीएमसी, सपा और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से किनारा करना चाहती है ?

अशोक भाटिया

सोमवार को संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक बैठक राज्य सभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में हुई, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी पहुंचे। हालांकि उस बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदारद रहे। इसकी आशंका पिछले शुक्रवार को ही हो गयी थी, जब चार दिन तक अडानी प्रकरण को लेकर संसद संसद का कामकाज बाधित रहा। टीएमसी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस को पहले ही पार्टी ने अपने रुख से अवगत करा दिया था।

इस प्रकरण से कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने के इरादे से बनाए गए इंडिया गठबंधन में बिखराव देखने मिल रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए कई मुद्दों को लेकर विपक्षी गठबंधन में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस चाहती है कि गौतम अडानी और ईवीएम के मुद्दे को सदन में उठाया जाए तो वहीं कई दल चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों को सदन में उछाला जाए, जिसका जनता से सीधा सरोकार हो।

सूत्रों ने कहा कि जब केवल कॉरपोरेट को लाभ होता है और चुनावी प्रक्रिया में खामियां हैं और विकल्पों को नकार दिया जाता है, तो यह लोगों का मुद्दा कैसे नहीं हो सकता है। इस बैठक में इंडिया ब्लॉक के संस्थापक सदस्य तृणमूल कांग्रेस ने हिस्सा न लेना ही एक बड़ा मुद्दा बन गया है । तीसरी बार बैठक में भाग न लेने वाली पार्टी का कहना है कि यह स्पष्ट हैं कि हम लोगों के मुद्दों पर मोदी सरकार से भिड़ना चाहते हैं।टीएमसी के मुताबिक, क्रोनी कैपिटलिज्म और ईवीएम जैसे मुद्दे लोगों को पसंद नहीं आते। पार्टी ने सवाल करते हुए कहा, उन इलाकों को देखिए जहां राहुल गांधी ने प्रचार किया है। अगर उन्होंने जो कहा वह लोगों के लिए मायने रखता तो कांग्रेस क्यों हारी? वहीं, टीएमसी, समाजवादी पार्टी (एसपी) और आम आदमी पार्टी (आप) जैसे सहयोगी दल कांग्रेस के ईवीएम और क्रोनी कैपिटलिज्म के प्रति जुनून को लेकर उत्साहित नहीं हैं। जबकि कांग्रेस ने 'भारत जोड़ो' की तर्ज पर 'ईवीएम जगाओ यात्रा' की योजना बनाई है और इंडिया ब्लॉक पार्टियों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, उनमें से अधिकांश ने बहुत कम रुचि दिखाई है। कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि क्या यह यात्रा उन राज्यों से होकर गुजरेगी जहां कांग्रेस ने चुनाव जीता है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने बीते रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन से इनकार किया है।

टीएमसी का साफ कहना है कि उनकी पार्टी के सांसद जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर मोदी सरकार से भिड़ना चाहते हैं जिनमें- महंगाई, बेरोजगारी, किसान, उर्वरक और मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके साथ ही सपा चाहती है कि इन मुद्दों के साथ-साथ संभल हिंसा को भी जोड़ दिया जाए। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा भी कि हमारे लिए अडानी से बड़ा मुद्दा किसान हैं और संभल हिंसा है।

इंडिया गठबंधन ब्लॉक में विभाजन के पीछे असली राजनीति भी छिपी है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में यह स्पष्ट है कि आप और कांग्रेस सहयोगी नहीं होंगे। बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस कभी एक दूसरे से सहमत नहीं हो सकते। यूपी में अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। दरअसल गठबंधन में शामिल दलों के अपने अलग-अलग मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस सिर्फ अडानी प्रकरण पर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश में लगी है। अन्य दलों को अब लग रहा है कि वे अपने मुद्दे को कांग्रेस के कारण सदन में नहीं उठा रहे हैं। सपा अपना फोकस यूपी पर करना चाहती है, लेकिन सदन नहीं चलने के कारण संभल सहित प्रश्न पत्र लीक प्रकरण को वह अब तक नहीं उठा पायी है। राजद भी बिहार से संबंधित कई मुद्दों को संसद में उठाना चाह रहा है। यही हाल डीएमके का भी बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा समस्या उन सांसदों के सामने है, जो अब तक अपना मेडन स्पीच भी संसद में नहीं दे पाये है। पहली बार चुनकर आये कई सांसदों ने अपने-अपने दल के नेताओं से अपनी पीड़ा व्यक्त की है।

कांग्रेस के कई सांसद भी यह मानने लगे हैं कि संसद न चलने का ज्यादा नुकसान उन्हें ही हो रहा है। सरकार को कटघरे में खड़ा करने का समय उनके हाथ से निकल रहा है।क्योंकि सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है और सरकार आंकड़ों में हेर-फेर कर सदन के बाहर देश को गुमराह कर रही है। जबकि संसद में सरकार की ओर से कोई आंकड़ा दिया जाता है, तो सरकार को उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। सोमवार को जब लोकसभा अध्यक्ष की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलायी गयी, तो संविधान पर चर्चा भाग न लेने का विकल्प विपक्ष के पास नहीं था। कांग्रेस लोगों के बीच यह संदेश नहीं देना चाहती कि संविधान की रट लगाने वाले पार्टी संविधान पर होने वाली चर्चा में भाग लेने से पीछे हट रही है। यही कारण रहा कि संविधान पर चर्चा को लेकर सभी दलों ने हामी भरी, लेकिन संसद के सुचारू संचालन में अभी कई बाधाएं है, जिसे दूर करने की जरूरत होगी।

कुछ कांग्रेस सांसद तो अब यहां तक कहने लगे है कि प्रियंका गांधी के लोकसभा में आने से रणनीति में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। उनके मुताबिक प्रियंका ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, वे वायनाड में भी जनता के ही मुद्दों पर फोकस कर रही थीं, ऐसे में यहां भी उनकी प्राथमिकता ऐसी ही देखने को मिल सकती है। अब समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस के कई सांसदों में रोष है, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं।

यह बात अब जगजाहिर हो चुकी है कि राहुल गांधी के लिए अडानी मुद्दा सबसे ज्यादा प्रिय है, वे इसी के सहारे चुनावों में उतरते हैं और सीधे पीएम मोदी को निशाने पर लेते हैं। संसद में भी वे सिर्फ इसी मुद्दे के दम पर केंद्र को पूरी तरह आइसोलेट करना चाहते हैं। लेकिन अब जब सदन कई दिनों से नहीं चल पा रहा है, कांग्रेस के ही सांसद मानने लगे हैं कि इस तरह से संसद को बाधित रखना ठीक नहीं। ऐसी स्थिति में सरकार की जवाबदेही तय करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार के बाद टीएमसी ने उसके नेतृत्व पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए है। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के सभी 6 विधानसभा उपचुनावों में जीत हासिल की है वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार को लेकर इन्डिया अलायंस के नेतृत्व परिवर्तन की मांग भी उठा दी है। पार्टी के सीनियर लीडर और सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस को अहंकार अपना किनारे रखना चाहिए और ममता बनर्जी को इन्डिया ब्लॉक का लीडर घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि गठबंधन को एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की जरूरत है।

टीएमसी सांसद ने दावा किया कि ममता बनर्जी के पास मजबूत नेतृत्व है। साथ ही, उनके जमीनी स्तर से जुड़ाव ने उन्हें विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे कारगर व्यक्ति बना दिया है। रक्तदान शिविर में बोलते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा, %कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को हाल के चुनावों में मिली विफलता को स्वीकार करना होगा। अब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर एकता को प्राथमिकता देने की जरूरत है। उन्हें अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए और ममता बनर्जी को इंडिया गुट के नेता के रूप में स्वीकार करना होगा।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

श्री आशुतोष ए.टी. पेडणेकर
(भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी)

नमस्कार साथियों हमारे आज के शख्सियत कॉलम के स्टार हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आशुतोष ए.टी. पेडणेकर। अजब सी ऊर्जा से लबरेज इस अधिकारी की क्या बात कहें। अलवर में जिला कलक्टर रहते हुए अनेकों नवाचार किए जोकि मील का पत्थर साबित हुए हैं। फिर वो चाहे पर्यटन स्थलों को जीर्ण होनें से बचाने का हो या फिर अलवर वाहिनी जैसे बड़े स्तर के कार्यक्रम को जमीन पर लाना हो इसके सारे प्रयास सफल रहे और एक सफल डीएम के रूप में अलवर की जनता उन्हें जानती रही है। आज भी उनका नाम बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। 28 जून सन 977 को गोआ में जन्में आशुतोष ए.टी. पेडणेकर ने विकास प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा कर सिविल सर्विसेज में जॉईन किया और आज शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं स्टेट मिशन निदेशक, आजिवि?का परियोजनाएँ एवं स्वयं सहायता समूह, जयपुर जैसे बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं। इससे पूर्व ये अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं अध्यक्ष, राजस्थान अक्षय उर्जा निगम, जयपुर। शासन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग एवं आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर। शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर। शासन सचिव उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) एवं राजकीय उपक्रम एवं दिल्ली.मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर एवं विशेषाधिकारी, भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण एवं शासन सचिव, विनियोजन एवं अप्रवासी भारतीय एवं निवेश संवर्धन ब्यूरो एव प्रबन्ध निदेशक, रीको एवं पदेन आयुक्त, डीएमआईसी राजस्थान, जयपुर। प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम रीको एवं पदेन आयुक्त, दिल्ली.मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर, जयपुर। प्रबन्ध निदेशक, रीको जयपुर। शासन सचिव, पंचायतीराज एवं आयुक्त, पंचायतीराज एवं शासन सचिव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर। शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर। आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग,राजस्थान जयपुर। आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर। निदेशक, पर्यटन विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम राजस्थान, जयपुर। निदेशकए पर्यटन विभाग, राजस्थान जयपुर। आयुक्त, नगर निगम जयपुर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त, नगर निगम जयपुर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम कोटा। उप शासन सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान जयपुर। उपखण्ड अधिकारी, घड़साना गंगानगर। उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी अलवर रहे। बेहद शानदार अधिकारी है आशुतोष ए.टी. पेडणेकर । दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

-रूपक शर्मा

आज का इतिहास

- फ्रांस के रसायन शास्त्री बर्टले का 1748 में जन्म हुआ।
- वायसराय लॉर्ड विलियम बैन्टिक ने 1829 में सती प्रथा समाप्त की।
- गोवा के मारगाव के अगस्टिनो लॉरेंसो ने 1860 में पैरिस विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि ली। वह विदेशी विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले पहले भारतीय बने।
- इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार का 1888 में जन्म।
- इंग्लैंड में स्मॉग की 1952 में घनी परत के छा जाने के कारण हजारों लोगों की जान चली गई थी।
- दक्षिणी अमरीका में ऐटलांटिक महासागर में स्थित बरमूडा द्वीप के बारे में 1952 में अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस की तीन पक्षीय कॉन्फ्रेन्स आरंभ हुई।
- भारत और नेपाल के बीच 1959 में गंडक सिंचाई एवं विद्युत परियोजना पर हस्ताक्षर।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच खराब होते हालात के मद्देनजर आपात सत्र बुलाया।
- भारतीय नौसेना ने 1971 में पाकिस्तान नौसेना और कराची पर हमला किया।
- मिस्र के विरुद्ध 1977 में अरब मोर्चा गठित।
- हिजबुल्ला आतंकवादियों ने 1984 में कुवैत एयरलाइन के विमान का अपहरण कर चार यात्रियों की हत्या की।
- सं.रा. अमेरिका डेविस कप 1995 में चैंपियन बना।
- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1996 में मंगल ग्रह के लिए एक और अंतरिक्ष यान 'मार्स पाथफाइंडर' प्रक्षेपित किया।
- अशोक गहलोत 2003 में विधानसभा क्षेत्र से 12वीं राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए।
- पेरू की मारिया जूलिया मांतिला गार्शिया को मिस वर्ल्ड 2004 चुना गया।
- फिलीपींस के एक गाँव में 2006 में आये तूफ़ान के बाद ज़मीन धंसने से लगभग एक हज़ार लोगों की मौत।
- प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर को 2008 में क्लूज सम्मान के लिये चुना गया।
- सीरिया में 2012 में हुए मोर्टार हमले में 29 लोगों की मौत।

4 दिसंबर को जन्मे व्यक्ति

- इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार का जन्म 1888 में हुआ।
- प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक विद्याभूषण विभु का जन्म 1892 में हुआ।
- प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक श्रीनिवास कृष्णन का जन्म 1898 में हुआ।
- भारत के आठवें राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकटरमण का जन्म 1910 में हुआ।

विशेष आलेख

'एक हैं, तो सुरक्षित हैं' के नारे के मर्म को समझा हिंदुसमाज ने

डॉ. आर.के. सिन्हा

महाराष्ट्र विधान सभा चुनावों को लेकर सारे देश की निगाहें लगी हुई थीं। सारे देश को ही बेसब्री से इंतजार था कि क्या बीते लोकसभा चुनाव में अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन के बाद भाजपा का प्रदर्शन महाराष्ट्र विधान सभा चुनावों में किस तरह का रहता है। दरअसल इसी साल में मात्र पाँच माह पूर्व संपन्न लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र के कई प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में आश्चर्यजनक असफलताओं के बाद, भाजपा के सामने बड़ी चुनौती यही थी कि वह राज्य में खोई हुई ज़मीन को किस तरह वापस हासिल कर लें। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के कारण भाजपा को लोकसभा चुनावों में कम से कम सात निर्वाचन क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था , जिसमें धुले और मुंबई उत्तर-पूर्व क्षेत्र भी शामिल हैं। इन दोनों जगहों में भाजपा का पहले से ही बहुत मजबूत आधार था। इन नतीजों के मद्देनज़र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने एक अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य न केवल इन खोई हुई ज़मीनों को वापस पाना था, बल्कि अपनी छवि को फिर से परिभाषित करना भी था। प्रधानमंत्री ने इस चुनाव में एक नया नारा पेश किया, एक हैं तो सुरक्षित हैं। यह नारा विशेष रूप से हिंदू मतदाताओं को आकर्षित कर एकजुट करने के लिए बनाया गया था, जिसमें जातीय विभाजन के ख़िलाफ़ पूरे हिंदू समाज की एकता पर ज़ोर दिया गया था।

बेशक, इस नारे ने महायुति गठबंधन को तगड़ा लाभ पहुंचाया। मोदी जी का नारा सिर्फ़ हिन्दू मतदाताओं को एक करना भर ही नहीं था। इसे पूरे समाज ने राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़कर भी देखा। महायुति गठबंधन में भाजपा, शिवसेना (शिंदे) और एनसीपी (अजित पवार) शामिल हैं। इस आह्वान के परिणामस्वरूप हिंदू वोटों का भाजपा और उसके सहयोगियों के पक्ष में मौन और अत्यंत ही प्रभावी एकीकरण हुआ। यह नारा विपक्ष द्वारा स्थापित कथानक का सीधा जवाब था। और, इसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक अन्य नारे 'बंटेंगे तो कटेंगे' से और भी शक्ति मिल गई। इन नारों का उद्देश्य उन क्षेत्रों में हिंदू मतदाताओं को आश्वस्त करना था, जहां उन्हें लगता था कि अल्पसंख्यक वोटों के एकीकरण के कारण उनका राजनीतिक प्रभाव कम हो रहा है।

मोदी और योगी के नारों से इसलिए भी हिन्दू मतदाता जुड़े , क्योंकि; कई मुस्लिम मौलवी लगातार यह अपील कर रहे थे कि मुस्लिम महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के उम्मीदवारों को ही वोट दें। इस्लामी प्रचारक मौलवी सज्जाद नोमानी विधानसभा चुनाव से पहले लगातार यह फतवे दे रहे थे , कि मुसलमानों को तो भाजपा के खिलाफ ही वोट देना है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सज्जाद नोमानी का एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें वह मुस्लिम समुदाय से कांग्रेस-सेना(उद्धव)-एनसीपी (शरद पवार) गठबंधन को ही वोट देने की अपील करते हुए दिखाई दिए थे।

सज्जाद नोमानी ने भाजपा का समर्थन करने वाले मुसलमानों के बहिष्कार का फतवा भी जारी किया था। नोमानी और उनके जैसे कुछ मजहबी और सियासी नेताओं की अपीलों और हरकतों के चलते ही उदारवादी हिन्दू मतदाता भी लामबंद हुआ। पत्रकारिता छोड़कर सियासत में आए औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील की पिछले महीने मुंबई में निकाली रैली ने भी हिन्दुओं को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। वे सैकड़ों कारों और दूसरे वाहनों के साथ मुंबई में आ गए थे। जलील को विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद पूर्व सीट पर भाजपा के अतुल सावे ने शिकस्त दी।

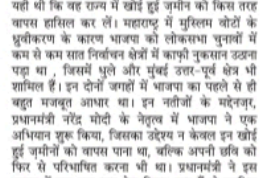

दरअसल राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल और महाराष्ट्र और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए कोटा की जोरदार तरीके से मांग कर रहे थे। इस कारण भी मोदी और योगी के नारों ने हिन्दू मतदाताओं को बहुत सोचने के लिए मजबूर किया। महाराष्ट्र में जैसे-जैसे चुनाव अभियान आगे बढ़ा, भाजपा की रणनीति विभाजन के कथित खतरों के खिलाफ सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता की रक्षा करने की कहानी में विकसित हुई। पीएम मोदी सहित महायुति के नेताओं ने रैलियों और बैठकों की एक श्रृंखला में भाग लिया, जिसमें एक साथ खड़े होने के महत्व पर जोर दिया गया। कहानी स्पष्ट थी- भाजपा के तहत एकता हिंदू समुदाय और विस्तार से राष्ट्र के लिए सुरक्षा और प्रगति का मार्ग है।मोदी और योगी के नारों को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने वार्षिक दशहरा संबोधन में समर्थन दिया। उन्होंने हिंदू एकता का आह्वान किया और बांग्लादेश में समुदाय पर हमलों से सबक लेने का आग्रह किया। वरिष्ठ संघ पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले ने भी हिंदू एकता के आह्वान को बढ़ाते हुए बटेंगे तो कटेंगे नारे का इस्तेमाल किया।

आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'बंटेंगे तो कटेंगे' के नारे ने हरियाणा चुनाव में भी अपना असर दिखाया था।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र हैं, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किन बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे ज्ञान से और जटिल मुद्दों को सुलझाने वाला सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करेंगे, बल्कि पारस्परिक संबंधों से भी, जहां तक सकारात्मकता वहां संवाद और बातचीत से लाभ प्रदान करेगा

मेष
स्वजनों एवं परिजनों के साथ विवाद हो सकता है। आय की अपेक्षा खर्च अधिक होगा और ज्यादा परिश्रम के बाद ही सफलता मिलेगी। दुर्घटना हो सकती है, सावधान रहें। आज आपका दिन बहुत लाभदायी है।

वृष
मित्र एवं प्रियजन आपके प्रवास को आनंद से भर देंगे। नए वस्त्रों की खरीदी के योग हैं। तन-मन की तंदुरस्ती अच्छी रहेगी। अच्छे भोजन एवं वैवाहिक सुख की अनुभूति होगी। आज आप के घर में सुख शांति और आनंद का माहौल रहेगा।

मिथुन
नौकरी में आपके अधिकारी खुश रहेंगे। आपकी पदोन्नति के योग हैं। अधिकारियों के साथ किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा होगा। परिजनों के साथ खुले मन से बातचीत होगी। घर के डेकोरेशन पर कुछ खर्च हो सकता है।

कर्क
पानी वाली जगहों से दूर रहें। आज नियम विरुद्ध कामों से दूर रहें। आज आपका दिन आनंद-प्रमोद में गुजरेगा। रोमांस के लिए आज का दिन अच्छा है और किसी खास व्यक्ति का साथ आपको आनंद देगा। आज कोई नया काम शुरू ना करें।

सिंह
अविवाहितों को योग्य जीवनसाथी मिलने के योग हैं। धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। मित्रों से अचानक हुई मुलाकात आनंददायी रहेगी। मित्रों से लाभ होगा। आज आपको अच्छा खाना नसीब होगा। मित्रों से लाभ होगा।

कन्या
हेल्थ का ध्यान रखने और खासकर बाहर के खाने-पीने से परहेज करने की सलाह आपको दी जाती है। आज आपमें क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी, इसलिए वाणी में गुस्सा ना रखें। परिजनों से उग्र चर्चा के कारण मनमुटाव न हो।

तुला
माता से लाभ होने के संकेत आपको मिल रहे हैं। मित्र और संबंधियों से घर का वातावरण अच्छा रहेगा। आज अचानक होने वाली घटनाओं से आप चिंतित रहेंगे। स्वास्थ्य खराब होने और आंखों में दर्द होने की आशंका बनी रहेगी। आपका

वृश्चिक
आज आपके धार्मिक एवं मांगलिक कामों में व्यस्त रहने की संभावना ज्यादा रहेगी। आप में आज क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी, इसलिए आप सावधान ही रहें। संतान एवं व्यापार की परेशानियों के कारण आपका मन अशांत रहेगा।

धनु
आपका शारीरिक एवं मानसिक आरोग्य अच्छा रहेगा। जरूरी कामों पर धन खर्च होगा। बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। दफ्तर में सहकर्मियों का अच्छा साथ मिलेगा। मित्रों से मुलाकात होगी।

मकर
संतान पक्ष से अच्छे समाचार मिलेंगे। नौकरीपेशा लोगों से आपको लाभ होगा। आय में वृद्धि होगी। वैवाहिक सुख की अनुभूति होगी। आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। आप आज हर काम सरलता से पूरे कर पाएंगे।

कुंभ
बाहर जाना हो सकता है। माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। सरकारी लाभ होगा एवं स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आप का दिन मध्यम फलदायी रहेगा। पहले से निर्धारित काम के लिए आपका प्रयास ज्यादा रहेगा। आज कोई नया काम शुरू

मीन
आप तन-मन से स्वस्थ होकर कई तरह के काम आसानी से पूरे कर पाएंगे। सफलता मिलने से आपके उत्साह में वृद्धि होगी। आज भाग्य आपका साथ देगा। इनकम बढ़ेगी। परिजनों के साथ आनंद एवं उल्लास से समय गुजरेगा। आज धन का व्यय अधिक होगा।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हमीरपुरा रोड खगड़वा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतीक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पाठन"। प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com "पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार